{ विश्वास वही रफ्तार नई }

बालाघाट
शुक्रवार 12 जून 2026
ज्येष्ठ कृष्ण 11 विक्रम सम्वत 2083
वर्ष 16, अंक 258
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

पद्मेश मीडिया समूह का प्रकाशन

बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

खास खबर

हायर सेकंडरी द्वितीय परीक्षा 2026 का परिणाम आज

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष-2026 का परीक्षा परिणाम 12 जून 2026 को घोषित किया जाएगा। यह परिणाम शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकेंगे।

पहली बार किसी भारतीय को सम्मान

नई दिल्ली। भारतीय सेना के मेजर प्रभात मिश्रा ने अमेरिकी सेना कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज (सीजीएससी) में दो शीर्ष शैक्षणिक अवॉर्ड जीते हैं। मेजर मिश्रा को उत्कृष्ट मास्टर ऑफ मिलिट्री आर्ट्स एंड साइंस थीसिस के लिए बिरर-ब्रूक्स अवॉर्ड दिया गया है। वहीं, जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। 10 महीने के इस नेतृत्व कार्यक्रम में 92 देशों के अधिकारी शामिल हुए। इस वर्ष 951 को उपाधि मिली। अमेरिका का यह कॉलेज दुनिया के सबसे प्रमुख सैन्य शिक्षा संस्थानों में से एक है। 1894 से 170 देशों के 8,700 अफसर प्रशिक्षण ले चुके हैं। मेजर प्रभात मिश्रा को अमेरिका के कंसास स्थित फोर्ट लीवनवर्थ में यूएस आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज के कमांड एंड जनरल स्टाफ ऑफिसर कोर्स के दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया। उन्हें दो पुरस्कार मिले।

केरलम में निपाह वायरस लौटा

तिरुवनंतपुरम। केरलम में इस साल निपाह वायरस का पहला केस मिला है। इसकी जानकारी गुरुवार को सामने आई। मरीज 43 साल का है और कोझिकोड का रहने वाला है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मरीज को हल्का बुखार आने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। बाद में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज भेजा गया। उसकी हालत गंभीर है और वह वेंटिलेटर पर है। स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने कहा, मरीज कई लोगों के संपर्क में आया था। अस्पताल के स्टाफ और उसके संपर्क में आए संभावित लोगों को क्वारंटीन रहने को कहा गया है। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है।

सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग

जालंधर। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में गुरुवार तड़के एक जिम के बाहर मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह जिम दिल्ली में राजौरी गार्डन के रहने वाले 2 कारोबारियों का है। इसके ब्रांड एंबेसडर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा हैं। वारदात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कुख्यात लॉरेंस गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

कुछ ना कहना

राज्यसभा चुनाव : 14 उम्मीदवार निर्विरोध जीते...भाजपा से 10, कांग्रेस से 4 चुने गए;

जीतने वालों में मल्लिकार्जुन खडगे और पवन खेड़ा शामिल, मप्र-गुजरात की सभी सीटों पर भाजपा जीती; राजस्थान में भाजपा को दो, कांग्रेस को मिली एक सीट

केवट की जीत पर रार!

नई दिल्ली/भोपाल/अहमदाबाद/जयपुर। राज्यसभा चुनाव में गुरुवार को भाजपा को बड़ी सफलता मिली। 14 उम्मीदवार गुरुवार को निर्विरोध राज्यसभा चुनाव जीत गए। इनके सामने कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं था। इनमें 10 भाजपा और 4 कांग्रेस से हैं। चुनाव जीतने वालों में कर्नाटक से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे और मीडिया व प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा का नाम शामिल है। वहीं, राजस्थान से भाजपा के सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और कांग्रेस के नीरज डांगी निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। इसके अलावा गुजरात से भाजपा के सभी चार राज्यसभा उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। वहीं,मप्र से भाजपा के रजनीश अग्रवाल, तरुण चुघ और महेश केवट की जीत हुई है। हालांकि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ पार्टी की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी थी। इस बीच महेश केवट को मप्र की तीसरी सीट से निर्विरोध जीत घोषित कर दी गई है। इसको लेकर मप्र से लेकर दिल्ली तक राजनीति गरमा गई है।

दरअसल, तीसरी सीट के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस के पास संख्या बल भी था, लेकिन 9 जून को नटराजन का नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया था। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के खारिज कर दिए जाने के बाद, राज्य की तीसरी राज्यसभा सीट पर मुकाबला भी समाप्त हो गया है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान, भाजपा ने कांग्रेस उम्मीदवार पर हलफनामे में आपराधिक मामले/कोर्ट नोटिस की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। आपत्तियों की जांच और सुनवाई के बाद उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही, भाजपा के तीनों उम्मीदवारों तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट का निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो गए हैं। भाजपा के तीनों उम्मीदवार जीत का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। भाजपा के तीनो उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की पीठ ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर के नामांकन रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। हालांकि मीनाक्षी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अदालत चुनाव होने दे और रिजल्ट घोषित करने पर अपने आदेश का कैप लगा दे। लेकिन अदालत ने दलील दरकिनार कर दी।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को घेरा

दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठक में इस घटनाक्रम को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग की जुगलबंदी ने सीट चोरी की है। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन मामूली आपत्ति पर खारिज कर दिया गया, जबकि भाजपा समर्थित उम्मीदवार को त्रुटियां सुधारने का मौका दिया गया। चुनाव आयोग ने दो उम्मीदवारों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया और कांग्रेस की आपत्तियों का जवाब भी नहीं दिया। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस चोरी में सभी शामिल हैं। सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। जब कोर्ट को मालुम था कि शाम 4 बजे के बाद हमारी याचिका निरर्थक हो जाएगी, तो आज सुनवाई क्यों नहीं की।

12 सीटों पर 18 जून को वोटिंग

अंध्रप्रदेश की 4, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु की एक सीट पर 18 जून को वोटिंग होगी। यहां कांग्रेस को एक, भाजपा को 8, जेएमएमए को दो और टीवीके को एक सीट पर जीत मिल सकती है। 244 सदस्यों वाली राज्यसभा में एनडीए के पास अभी 149 सांसद हैं, जबकि विपक्ष के पास 78 और गैर-गठबंधन वाले क्षेत्रीय दलों के पास 17 सांसद हैं।

राजस्थान राज्यसभा चुनाव

राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी हो गई है। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद भाजपा के डॉ. सतीश पूनिया और डॉ. अलका गुर्जर तथा कांग्रेस के नीरज डांगी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

गुजरात राज्यसभा चुनाव

गुजरात में राज्यसभा की चार सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा के सभी चार उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। राजू शुक्ल, मानसिंह परमार, मुकेश राठवा और जितेंद्र कंजारिया ने जीत दर्ज की है। इसके साथ अब राज्यसभा में गुजरात से 11 सांसद है, सभी सांसद भाजपा के हैं। साल 2029 मे अब अगले राज्यसभा चुनाव होंगे तब तक गुजरात से कांग्रेस का कोई भी सांसद नहीं होगा।

18 जून 2026 को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के बाद कई राज्यों में उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की स्थिति स्पष्ट हो गई है। जहां कुछ राज्यों में सभी सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध सीटों के बराबर रही, वहीं अन्य राज्यों में चुनावी प्रक्रिया अभी जारी है। राजस्थान में राज्यसभा की तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के सतीश पूनिया और अलका गुर्जर तथा कांग्रेस के नीरज डांगी बिना मतदान के राज्यसभा पहुंच गए हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि तक किसी अतिरिक्त उम्मीदवार के मैदान में नहीं रहने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया निर्विरोध पूरी हो गई। राजस्थान में तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इनमें- सतीश पूनिया (भाजपा) अलका गुर्जर (भाजपा) नीरज डांगी (कांग्रेस) हैं। मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्वाचित होने का प्रमाणपत्र सौंप दिया। वैसे मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्ध मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होने की संभावना जताई जा रही है। इस कारण सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार जिन राज्यों में आवश्यक संख्या से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं, वहां 18 जून को मतदान कराया जाएगा। इसके बाद आयोग द्वारा अंतिम परिणाम और राज्यवार विस्तृत सूची जारी की जाएगी। इससे पहले मार्च 2026 में हुए राज्यसभा चुनावों में भी कई राज्यों में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। महाराष्ट्र में शरद पवार, रामदास आठवले, विनोद तावड़े और पार्थ पवार समेत सात उम्मीदवार बिना मतदान के उच्च सदन पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, मेनका गुरुस्वामी, कोयल मल्लिक और राहुल सिन्हा निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए थे। वहीं छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी वर्मा और फूलो देवी नेताम को बिना मतदान के राज्यसभा सदस्य चुना गया था। इसके अतिरिक्त असम, तमिलनाडु, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की कई सीटों पर भी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। मार्च 2026 के चुनावों में कुल 26 उम्मीदवार बिना मतदान के राज्यसभा पहुंचे थे।

मिडिल ईस्ट में तीन दिन में तीसरे भारतीय जहाज पर अटैक

ओमान के पास जलवीर पर हमला

नई दिल्ली। ओमान तट के पास बुधवार को हुए हमले के 24 घंटे बीतने तक एक और हमला रिपोर्ट किया गया है। ये हमला ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक जहाज पर हुआ है। इस शिप का नाम एमटी जलवीर है और सामने आई तस्वीरों में समुद्र के बीच इस शिप को जलते हुए देखा जा सकता है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

अधिकारियों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्हें गुरुवार को शिनास बंदरगाह के पास एक पोत (वेसल) से संबंधित घटना की सूचना मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। बयान के अनुसार, घटना के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। फिलहाल घटना के कारणों और संभावित प्रभावों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस हमले की जानकारी ओमान में भारतीय एंबेसी की ओर से दी गई है। मामले में और जानकारी जुटाई जा रही है।

तीन भारतीय नाविकों की मौत

बता दें कि ओमान तट के पास बीते बुधवार को भी एक कमर्शियल जहाज पर हमला होने की बात सामने आई थी। इस जहाज पर कुल 28 लोग सवार थे। इनमें से 24 भारतीय थे। दुखद बात यह है कि इस हमले के बाद 3 भारतीय लापता हो गए थे, जिनकी मौत की पुष्टि हो गई है। जबकि 21 भारतीय को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। ये घटना 10 जून की है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। जिस जहाज पर हमला किया गया था उसका नाम सेटेबेलो था।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने की कड़ी निंदा

तेल टैंक पर हुए अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि होने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ओमान के तट पर वाणिज्यिक पोत सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं।

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को दी चेतावनी

'दीदी' तय करें अभिषेक को रखेंगी या मुझे छोड़ेंगी

नई दिल्ली। टीएमसी को फिर से एक बड़ा झटका लगा है। अब टीएमसी से सांसद और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के करीबी कल्याण बनर्जी ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से यह तक कह दिया है कि या तो अभिषेक बनर्जी को रखिए या फिर मुझे छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना है, मैंने 'दीदी' से कह दिया है। कल्याण बनर्जी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं।

जब पत्रकारों ने पूछा कि आप टीएमसी के साथ हैं, तो कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं ममता दीदी के साथ हूं। अभिषेक पर आरोप लगाते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि वो घमंडी हो गए हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आदर नहीं करते हैं। कल्याण बनर्जी के अनुसार अब वो अभिषेक का केस नहीं लड़ेंगे। कल्याण ने कहा कि अभिषेक के काम करने के तरीकों को लेकर पार्टी में असंतोष है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक के साथ मिलकर पार्टी चलाना चाहती हैं तो मैं नहीं रहूंगा।

मैं अभिषेक का कोई भी केस नहीं लड़ूंगा

कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं अभिषेक बनर्जी का कोई भी केस नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे उनका घमंडी रवैया पसंद नहीं है। मैंने इस पेशे में 45 साल बिताए हैं। ये सभी लोग मेरे साथ जूनियर के तौर पर काम कर चुके हैं। वह मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? राजनीति में भी मैं उनसे सीनियर हूं। वह ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें यह समझना होगा कि उन्हीं की वजह से हम हारे हैं।

आईएएस संजय प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद और सबसे ताकतवर नौकरशाहों में शुमार अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें संजय प्रसाद के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की गई थीं और उनके कार्यकाल पर असर डालने वाले निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और अतुल चंदुरकर की बेंच ने आईएएस संजय प्रसाद द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह स्थगन आदेश जारी कर दिया है लेकिन यह समझना है कि हाईकोर्ट का वो कौन सा मामला है, जिसकी वजह से आईएएस संजय प्रसाद के खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की थीं? दरअसल, यह पूरा विवाद एक महिला की याचिका से शुरू हुआ था, जिसकी नाबालिग बेटी का अपहरण हो गया था और पुलिस उसे ढूंढने में नाकाम रही थी। मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने पाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य में जांच व्यवस्था सुधारने के पुराने अदालती निर्देशों का पालन नहीं कर रही है।

दुर्घटना में महिला की मौत से जुड़े एक मुआवजा केस में सुप्रीम कोर्ट बोला

महिलाओं को होममेकर नहीं नेशन बिल्डर कहें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि गृहिणी को होममेकर के बजाय नेशन बिल्डर कहना चाहिए। कोर्ट की यह टिप्पणी दुर्घटना में महिला की मौत से जुड़े एक मुआवजा केस में आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी दुर्घटना के कारण गृहिणी की मौत हो जाती है, तब उसका मुआवजा तय करते उसके योगदान का आकलन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक गृहिणी का काम केवल खाना बनाना, बच्चों की देखभाल और घर संभालना नहीं है। वह परिवार की नींव को मजबूत बनाती है, अगली पीढ़ी तैयार करती है। इसके बाद जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने दुर्घटना की शिकार गृहिणियों के मामले में एक नई गाइडलाइन जारी की। कोर्ट ने कहा कि एक गृहिणी के काम के लिए 30 हजार रुपए हर महीने के हिसाब से मुआवजा तय किया जाना चाहिए। यह मामला पंजाब की रेशमा नाम की महिला से जुड़ा है। उनकी मौत नवंबर 2001 में एक सड़क हादसे में हुई थी। उनके पति और तीन बच्चों ने मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। ट्रिब्यूनल ने 2003 में फैसला दिया, लेकिन कानूनी लड़ाई वर्षों तक चलती रही। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर दिसंबर 2024 में फैसला सुनाया। हादसे के 23 साल बाद आए इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई।

बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर फिलहाल बने रहेंगे ऋतब्रत बनर्जी

-टीएमसी की याचिका पर अगली सुनवाई 16 जून को

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) की नियुक्ति को लेकर चल रहे राजनीतिक और कानूनी विवाद के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण अंतरिम फैसला सुनाया। अदालत ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की उस मांग पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में ऋतब्रत बनर्जी की नियुक्ति पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। इसके साथ ही ऋतब्रत बनर्जी फिलहाल विपक्ष के नेता के पद पर बने रहेंगे।

यह मामला उस समय शुरू हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष रथींद्रनाथ बोस ने टीएमसी के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया और तृणमूल कांग्रेस ने इसे चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया। टीएमसी का तर्क है कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति केवल विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर आधारित नहीं हो सकती। पार्टी का कहना है कि इस पद के निर्धारण में सदन में दलों की वास्तविक संख्या, राजनीतिक परिस्थितियों और संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पार्टी ने दावा किया कि विपक्ष में रहते हुए उसने इस जिम्मेदारी के लिए सोवंदेब चट्टोपाध्याय को चुना था और अध्यक्ष का निर्णय लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है।

दूसरी ओर, विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद ऋतब्रत बनर्जी को आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिल चुकी है। हाईकोर्ट द्वारा तत्काल रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद उनकी स्थिति फिलहाल यथावत बनी रहेगी। अदालत के इस अंतरिम रुख को राजनीतिक हलकों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्षी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे विधानसभा के भीतर चल रहे शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। वहीं टीएमसी इसे अपने राजनीतिक अधिकारों और संसदीय परंपराओं से जुड़ा मुद्दा बता रही है।

पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक बागी विधायक को विपक्ष का नेता बनाकर स्थापित परंपराओं से हटकर निर्णय लिया है। टीएमसी का कहना है कि इससे सदन की राजनीतिक संरचना और विपक्षी दलों की भूमिका प्रभावित हुई है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की गई है।

'370 रुपये बिरयानी' विवाद में बड़ा एक्शन, कॉमेडियन प्रणीत मोरे समेत कई लोगों पर एफआईआर

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर चर्चित '370 रुपये बिरयानी' विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कथित आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियों के मामले में कॉमेडियन प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा, डॉ. सेजल पवार और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए समन भी जारी किया है। जानकारी के अनुसार, मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ वीडियो क्लिप्स से जुड़ा है। इनमें से एक क्लिप कॉमेडी शो 'वुमन' की बताई जा रही है, जिसमें हिमांशु जांगड़ा डेटिंग के अनुभव साझा करते हुए महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी करते नजर आए। साइबर पुलिस का आरोप है कि इस तरह की टिप्पणियां महिलाओं की गरिमा, सहमति और सम्मान के खिलाफ हैं तथा समाज में गलत संदेश देती हैं। वहीं दूसरी वायरल क्लिप में डॉ. सेजल पवार पर भी अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि यह सामग्री सार्वजनिक शालीनता और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के मुताबिक, संबंधित वीडियो और कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर प्रसारित किया गया, जिससे लाखों लोगों तक इसकी पहुंच बनी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि व्यूज, लोकप्रियता और डिजिटल कमाई के उद्देश्य से इस सामग्री को रिकॉर्ड कर वायरल किया गया।

नगर में सफेद एलईडी और हाई पावर लाइटों का बढ़ता प्रचलन बना खतरा

बैहर रोड, वारासिवनी रोड और गोंदिया रोड पर वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों वाहनों में लगाई जा रही तेज सफेद एलईडी एवं हाई पावर हैलोजन लाइटें आम नागरिकों और वाहन चालकों के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही हैं। विशेष रूप से बैहर रोड, वारासिवनी रोड और गोंदिया रोड पर रात के समय ऐसे वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।जिनमें अत्यधिक चमकदार सफेद लाइटों का उपयोग किया जा रहा है। इन लाइटों की तेज रोशनी के कारण सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालक, मोटरसाइकिल सवार, साइकिल चालक एवं राहगीर भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।स्थानीय नागरिकों का कहना है कि रात के समय सामने से आने वाले वाहनों की तेज सफेद रोशनी सीधे आंखों पर पड़ती है।जिससे कुछ क्षणों के लिए सड़क दिखाई देना बंद हो जाता है। कई बार चालक अपनी दिशा और संतुलन खो बैठते हैं। जिसके कारण दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बनी रहती है। छोटे वाहन चालक विशेष रूप से इससे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

आंखों पर पड़ रहा बुरा प्रभाव

अत्यधिक तेज सफेद एलईडी लाइटें सामान्य पीली रोशनी की तुलना में आंखों पर ज्यादा दबाव डालती हैं। इन लाइटों की तीव्र चमक सामने से आने वाले व्यक्ति की दृष्टि को कुछ सेकंड के लिए प्रभावित कर देती है। रात के समय जब सड़क पर पहले से ही दृश्यता सीमित होती है। तब यह सफेद प्रकाश दुर्घटना का बड़ा कारण बन सकता है। लोगों का मानना है कि लगातार तेज सफेद रोशनी के संपर्क में आने से आंखों में जलन, सिरदर्द, धुंधलापन और दृष्टि संबंधी परेशानी भी बढ़ सकती है। बुजुर्ग वाहन चालक और कमजोर दृष्टि वाले लोग इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

नियमों के विपरीत लगाए जा रहे एलईडी और हैलोजन

जानकारी के अनुसार कई वाहन मालिक अपने दोपहिया और चारपहिया वाहनों में कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक क्षमता वाली एलईडी और हैलोजन लाइटें लगवा रहे हैं। कुछ वाहन चालकों द्वारा अतिरिक्त फॉग लाइट और हाई बीम का लगातार उपयोग भी किया जा रहा है। यह न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा माना जा रहा है।नगर के नागरिकों का कहना है कि कई बाइक और कारों में इतनी तेज रोशनी वाली लाइटें लगी हुई हैं कि सामने से आने वाले वाहन चालक की आंखें चौंधिया जाती हैं। इससे अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है और कई बार वाहन असंतुलित होकर दुर्घटना की स्थिति में पहुंच जाते हैं।

राहगीरों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक परेशानी

बैहर रोड, वारासिवनी रोड और गोंदिया रोड जैसे मार्गों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोग यात्रा करते हैं। इनमें मजदूर, छात्र, किसान और छोटे व्यापारी भी शामिल हैं। रात के समय सड़क किनारे पैदल चलने वाले राहगीरों एवं साइकिल चालकों को इन तेज लाइटों से सबसे अधिक परेशानी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर सड़क प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने के कारण वाहन चालकों की तेज सफेद लाइटें सीधे राहगीरों की आंखों पर पड़ती हैं। जिससे दुर्घटना का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार छोटे बच्चे और बुजुर्ग सड़क पार करते समय इन लाइटों के कारण घबरा जाते हैं।

यातायात एवं आरटीओ विभाग पर उठ रहे सवाल

नागरिकों ने यातायात विभाग और आरटीओ की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि नियमों के विपरीत चल रहे ऐसे वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यदि समय रहते सख्ती नहीं की गई तो आने वाले दिनों में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। नागरिकों का आरोप है कि वाहन जांच अभियान केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं। जबकि वास्तविकता में रात के समय सड़कों पर बड़ी संख्या में हाई पावर एलईडी लाइटों वाले वाहन दौड़ते दिखाई देते हैं। लोगों ने मांग की है कि नियमित जांच अभियान चलाकर ऐसे वाहनों पर जुर्माना लगाया जाए तथा अवैध लाइटों को तुरंत हटाने की कार्रवाई की जाए।

सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी

वाहन निर्माता कंपनियां सड़क सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर हेडलाइटों की क्षमता निर्धारित करती हैं। लेकिन कई वाहन चालक अधिक रोशनी और स्टाइल के नाम पर नियमों से अधिक क्षमता वाली लाइटें लगवा लेते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन रही है।नागरिकों का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर ही हाई बीम का उपयोग करें तथा शहर और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लो बीम का प्रयोग करें। साथ ही वाहन मालिकों को मानक क्षमता वाली लाइटों का ही उपयोग करना चाहिए।

नागरिकों ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग

आम नागरिकों ने जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग से मांग की है कि सफेद तेज रोशनी वाली अवैध एलईडी एवं हाई पावर हैलोजन लाइटों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। लोगों का कहना है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। नागरिकों ने प्रशासन से यह भी मांग की है कि वाहन चालकों को यातायात नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएं। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बताया जाए कि तेज रोशनी वाली लाइटें दूसरों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं।नगर में तेजी से बढ़ रही इस समस्या को लेकर आम लोगों में चिंता का माहौल है। नागरिकों का कहना है कि यदि अभी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। जनअपेक्षा है कि जिला प्रशासन, यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा आम नागरिकों को इस परेशानी से राहत दिलाएंगे।

In The Court Of I Civil Judge Senior Division
Waraseoni,District Court,Balaghat
Presiding Officer: दिव्या सिंह

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
सक्सेशन प्रकरण क्रमांक (MJC SUC/0000008/2026)

रोहित बोपचे............ आवेदक
Vs
जिला अक्षय उर्जा अधिकारी मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम लि.........अनावेदक

Process Id- 140/2026
पेशी तारीख- 10/07/2026

प्रेषिती-
(1) सर्वसाधारण आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक **रोहित बोपचे पिता स्व. तखतमल बोपचे** वार्ड नं. 03 ब्लाक आफिस के पीछे तुमसर रोड कटंगी तह. कटंगी जिला बालाघाट मध्यप्रदेश मृतक तुलसीराम बोपचे निवासी वार्ड नं. 03 ब्लाक आफिस के पीछे तुमसर रोड कटंगी तह0 कटंगी जिला बालाघाट मध्यप्रदेश की मृत्यु दिनांक 21/05/2021 को वार्ड नं. 03 ब्लाक आफिस के पीछे तुमसर रोड कटंगी तह. कटंगी जिला बालाघाट मध्यप्रदेश हो चुकी है यह है कि आवेदकगण के पिता तखतमल बोपचे की मृत्यु बाद उनकी शासकीय सेवा से संबंधित ग्रेच्युटी, जी.एस.एल.आइ. एवं प्राविडेंट फंड की राशि उनके द्वारा नांमाकिंत आवेदकगण की माँ श्रीमती निर्मला बोपचे को प्राप्त हो चुकी है तथा आवेदकगण की माँ की मृत्यु दिनांक 22/05/2025 को हो चुकी है यह है कि निर्मला बोपचे की मृत्यु के बाद आवेदकगण के पिता तखतमल बोपचे की सेवा के दौरान का सातवें वेतनमान के भुगतान की एरियर राशि 2,42,400 रूपये की राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक **10 July 2026** को नियत है।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक **10 July 2026** को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें । सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

यह आज तारीख **09 June 2026** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
वारासिवनी, जिला बालाघाट(म.प्र.)

कृपया ध्यान दें-
1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

कार्यालय तहसीलदार तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट (म.प्र.)

रा.प्र.क्र. 0008/ड-154/2026-27
मौजा लोहारा, रा.नि.मं. खमरिया

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक जयकिसन धुले पिता स्व0 इठोबा धुले जाति सुनार, निवासी ग्राम लोहार, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मौजा लोहारा, रा.नि.मं. खमरिया, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट में स्थित आवेदक द्वारा अपनी माता सरसता पति इठोबा का अनुज्ञा प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 (2), म.प्र. मृत्यु पंजीयन 1999 नियम 12 (2) प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त मृत्यु की घटना दिनांक 20.12.2004 मृत्यु स्थल ग्राम लोहारा के अंतर्गत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह दिनांक 15.06.2026 के पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक/अधिवक्ता सहित उपस्थित होकर इस न्यायालय में दावा आपत्ति पेश कर सकते है। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 08.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

स्थान - लालबर्रा
दिनांक - 12.06.2026

भूपेन्द्र अहिरवार
तहसीलदार
तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट म.प्र.

पुलिस लाइन रक्षित क्षेत्र परिसर में आयोजित ग्रीष्मकालीन वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अकादमी के तत्वाधान में नगर के पुलिस लाइन रक्षित क्षेत्र परिसर में 1 मई से आयोजित वॉलीबॉल ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन, पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। बताया गया कि इस 40 दिनों के प्रशिक्षण में 45 से 46 बालक बालिकाओं ने भाग लिया।जिन्होंने कोच सुधीर तोमर और अनिल चंदेश्वर के मार्गदर्शन में खेल की विभिन्न बारीकियां एवं कौशल प्राप्त किया।जहां प्रशिक्षित बच्चों के खेल को परखने एवं निखारने के लिए बच्चों के मध्य प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें विजेता एवं उपविजेता बालक बालीकाओं को टीआई कामेश धूमकेती द्वारा प्रथम पुरस्कार 3000 -3000 रु, द्वितीय पुरस्कार 2000- 2000 रु इनाम के तौर पर दिए गए।वही ट्रॉफी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से प्रदान की गई। विजेता एवं उपविजेता को सुरेश बागरेचा समाजसेवी एवं व्यापारी द्वारा पानी की बोतल प्रदान की गई। इसके उपरांत प्रशिक्षण शिविर एवं समारोह समापन की घोषणा की गई।इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में ललित शाक्यवार (आईजी बालाघाट), डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अकादमी के अध्यक्ष तपेश असाटी, उपाध्यक्ष श्रेयांश वैद्य, कोषाध्यक्ष आशीष मिश्रा, बास्केटबॉल संघ कोषाध्यक्ष संजय बरेवार,बास्केटबॉल कोच चीनू मिश्रा, डॉ. भूपेंद्र उईके आयुष विभाग एवं ट्रक ट्रांसपोर्ट संघ जिला अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया सहित अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

अब खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब- ललित शाक्यवार

इस अवसर पर आईजी ललित शाक्यवार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी बच्चों को खेल भावना के साथ खेलना चाहिए एवं खेल में अपने भविष्य को तलाश करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है।उन्होंने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब आज इस परिवेश में यह कहावत चरितार्थ हो रही है इस अवसर पर मंच का संचालन सुधीर कुमार तोमर वरिष्ठ वॉलीबॉल कोच के द्वारा किया गया और संदीप तिवारी जैनेंद्र उपरते, कमल किशोर तेलसे, शैलेंद्र यादव,श्री गौतम आदि का सरहानीय एवं अन्य खेल प्रेमी इस अवसर पर मौजूद रहे अंत में तोमर जी का 62 वा जन्मदिन का केक आई जी साहब के द्वारा काटकर मैदान पर ही जन्मदिन मनाया गया और सभी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके एवं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह कार्यक्रम संपन्न हुआ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का बालाघाट आगमन

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का 11 जून को अपरान्ह 04 बजे गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से बालाघाट के लिए प्रस्थान करेंगे और रात्रि 08 बजे बालाघाट पहुंचेंगे। मंत्री श्री पटेल रात्रि 09 बजे बालाघाट से मलाजखंड के लिए प्रस्थान करेंगे और रात्रि विश्राम मलाजखंड में करेंगे। मंत्री श्री पटेल 12 जून को प्रातः 07 बजे मलाजखंड से बंजर नदी के उद्गम स्थल छत्तीसगढ राज्य के खैरागढ जिला स्थित बंजारपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और प्रातः 08:30 बजे बंजारपुर पहुंचेंगे और नदी के उद्गम स्थल पर दर्शन पूजन करेंगे। मंत्री श्री पटेल प्रातः 09:15 बजे बंजारपुर से प्रस्थान करेंगे और दोपहर 12:45 बजे बालाघाट पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे।

हायर सेकंडरी द्वितीय परीक्षा 2026 का परिणाम 12 जून को

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष-2026 का परीक्षा परिणाम 12 जून 2026 को घोषित किया जाएगा। यह परिणाम शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकेंगे।

कार्यालय तहसीलदार तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट (म.प्र.)

रा.प्र.क्र. 0009/ड-154/2026-27
मौजा धपेरा, रा.नि.मं. कनकी

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक चमनलाल लिल्हारे पिता स्व0 झाडया लिल्हारे जाति लोधी, निवासी ग्राम धपेरा, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मौजा धपेरा, रा.नि.मं. कनकी, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट में स्थित आवेदक द्वारा अपने भाई अमरलाल पिता झाडया का अनुज्ञा प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 (2), म.प्र. मृत्यु पंजीयन 1999 नियम 12 (2) प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त मृत्यु की घटना दिनांक 23.06.2024 मृत्यु स्थल ग्राम धपेरा के अंतर्गत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह दिनांक 19.06.2026 के पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक/अधिवक्ता सहित उपस्थित होकर इस न्यायालय में दावा आपत्ति पेश कर सकते है। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

स्थान - लालबर्रा
दिनांक - 12.06.2026

भूपेन्द्र अहिरवार
तहसीलदार
तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट म.प्र.

कार्यालय तहसीलदार तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट (म.प्र.)

रा.प्र.क्र. 0009/ड-154/2026-27
मौजा मोहगांव बो0, रा.नि.मं. खमरिया

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक दीपा बागडे पति स्व0 देवेंद्र बागडे जाति महार, निवासी ग्राम मोहगांव बोरी, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मौजा मोहगांव बोरी, रा.नि.मं. खमरिया, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट में स्थित आवेदक द्वारा अपने ससुर नामदेव पिता सोविंदा का अनुज्ञा प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 (2), म.प्र. मृत्यु पंजीयन 1999 नियम 12 (2) प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त मृत्यु की घटना दिनांक 02.09.2024 मृत्यु स्थल ग्राम मोहगांव बोरी के अंतर्गत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह दिनांक 15.06.2026 के पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक/अधिवक्ता सहित उपस्थित होकर इस न्यायालय में दावा आपत्ति पेश कर सकते है। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 08.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

स्थान - लालबर्रा
दिनांक - 12.06.2026

भूपेन्द्र अहिरवार
तहसीलदार
तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट म.प्र.

एनसीटीई पाठ्यक्रमों के प्रथम चरण का आवंटन जारी

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु संचालित ई-प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत एनसीटीई पाठ्यक्रमों (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. आदि) के प्रथम चरण का महाविद्यालय आवंटन जारी कर दिया गया है। प्रथम चरण में पात्र अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किए गए हैं। आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये 15 जून 2026 तक निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कुल 64,641 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 59,113 आवेदनों का सत्यापन किया गया। प्रथम चरण में 32,918 अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे अपने लॉगिन के माध्यम से आवंटन की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित समय-सीमा में शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर आवंटन निरस्त माना जाएगा तथा सीट आगामी चरणों के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

किराये पर उपलब्ध
धनराज कॉम्पलेक्स बालाघाट में प्रथम तल पर दुकानें किराये पर देना है।
महेन्द्र सुराना 9425138670
ललित बाघरेचा 9424765679

आवश्यकता है
10वीं/12वीं या पदवीधर/आई.टी.आई. की यश एलईडी टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड कम्पनी नागपुर में इंटरव्यू के लिये।
-संपर्क करें-
शिव प्रसाद परिहार
9823234770
9823020378

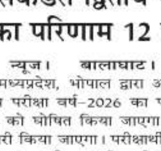

बंशपाल परिवार की ओर से संदीप व नीतू बंशपाल को 14 वी वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक :- माता जी कुंती बंशपाल, मम्मी आशा बंशपाल, पापा ब्रजलाल बंशपाल, सोनू प्रिया, लवलेश जी, विव की, अंजली, दीपशिखा, मनीष, वंशु बेटा, धानी बिटिया एवम समस्त बंशपाल परिवार ग्राम बकोड़ा लालबर्रा।

बारबेड वायर (कांटेदार तार) एवं चेन लिंक जाली उचित दाम पर उपलब्ध
लघु उद्योग निगम भोपाल से संबद्ध
निर्माता
तिरूपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टॉकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फोन:- 07632-243531
मो:- 8989976858, 9425139998

न्यूज गैलरी

समनापुर रोड पर तेज रफ्तार फोर व्हीलर मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार

नवविवाहित युवक गंभीर रूप से घायल

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत समनापुर रोड पर ग्राम आमगांव के पास गुरुवार को तेज रफ्तार फोर व्हीलर मोटरसाइकिल को ठोस पारकर फरार हो गई । इस जबरदस्त सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।वही उसकी मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायल युवक कमल किशोर पिता युगल किशोर नगपुरे

25 वर्ष ग्राम रोशना थाना ग्रामीण निवासी है । जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमल किशोर नगपुरे खेती-किसानी के साथ ड्राइविंग का कार्य भी करता है। वह प्रतिदिन मोटरसाइकिल से बालाघाट आना जाना करता था। बताया गया कि 11 जून को सुबह लगभग 8:30 बजे वह अपने काम से मोटरसाइकिल से द बालाघाट आया था। काम खत्म करने के बाद दोपहर करीब 2 बजे वह वापस अपने गांव रोशना लौट रहा था इसी दौरान समनापुर रोड स्थित ग्राम विश्रामपुर और आमगांव के बीच सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक फोर व्हीलर ने उसकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कमल किशोर सड़क पर जा गिरा और उसका दाहिना पैर फैक्चर हो गया। वहीं उसकी मोटरसाइकिल भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद फोर व्हीलर चालक मौके से फरार हो गया।घटना के बाद घायल कमल किशोर सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ा रहा। इसी बीच किसी राहगीर ने उसके मोबाइल से परिजनों को सूचना दी। खबर मिलते ही माता-पिता मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल कमल किशोर को तत्काल जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किये।जहां उसका इलाज जारी है। जिला अस्पताल पुलिस चौकी ने घायल युवक के पिता युगल किशोर के बयान दर्ज कर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस थाना ग्रामीण नवेगांव भेज दी है। मामले की जांच ग्रामीण पुलिस द्वारा की जा रही है।बताया गया कि कमल किशोर की पिछले माह ही शादी हुई थी। परिवार में उसके माता-पिता और एक छोटा भाई है। जो बाहर रहकर मिस्त्री का काम करता है।

जरा सी बारिश में लोगों के घरों में घुसा नालियों का गंदा पानी

बिना अनुमति के प्लाट धारक द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने से आई समस्या, अध्यक्ष सहित नपा अमले ने तोड़ा निर्माण,पानी निकासी की बनाई व्यवस्था, नगर के वार्ड नं 1,माता मंदिर रोड गली नंबर 02 का मामला

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

नगर में बिना अनुमति के प्लाट धारको द्वारा मकान व अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे है।जिसके चलते स्थानीय लोगो को बरसात के पूर्व ही पानी निकासी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।एक ऐसा ही मामला नगर के वार्ड नं.1 माता मंदिर रोड़ स्थित गली न.2 में सामने आया।जहा बगैर अनुमति के भूस्वामी द्वारा किए जा रहे अवैध निमार्ण कार्य के चलते बुधवार की शाम नगर में हुई जरा सी बारिश में उक्त मोहल्ले की सड़क गंदे पानी से तरबतर हो गई।जहा पानी निकासी की जगह ना होने और पानी निकासी की जगह पर अवैध निर्माण होने के चलते, बुधवार को हुई कुछ देर की बारिश में ही सड़क में पानी भर गया।वहीं नालियों का गंदा पानी सड़क से होते हुए लोगो के घरों में घुसने लगा।जिसकी शिकायत, रहवासियों ने नपाध्यक्ष भारती ठाकुर को की थी। जिसके बाद गुरूवार को नपाध्यक्ष, सीएमओ, सहित नपा अमले ने मौके पर पहुँचकर,हालातो का जायजा लिया और पानी निकासी की जगह में भूस्वामी द्वारा कराए गए अवैध निर्माण को हटा दिया।जिससे एक बार फिर पानी निकासी की व्यवस्था बहाल हो गई।उधर नपाध्यक्ष ने मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए नगर में हो रहे भवनों की निर्माण की अनुमति की जांच और अवैध मकानों पर कार्यवाही किए जाने की बात कही है। वहीं उन्होंने, इसके लिए प्रशासन से भी सहयोग मांगा है।

बुलडोजर चलाकर हटाया अतिक्रमण, साफ सफाई कराकर बनाई पानी निकासी व्यवस्था

बताया गया कि एक निजी प्लाट धारक की भूमि से गली नं. 2 की पानी निकासी होती है।जहां कुछ दिन पूर्व ही उक्त प्लाट धारक ने नपा की अनुमति के बगैर ही उक्त जगह में निर्माण शुरू करा दिया था।जिससे वहां से पानी की निकासी नही हो पा रही थी।उधर बुधवार की शाम नगर में कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई, जिससे नालियों का पानी सड़क से होता हुआ लोगो के घर मे घुसने लगा था।जिसकी जानकारी मिलने पर नपाध्यक्ष सीएमओ सहित नपा के अमले ने मौके पर पहुचकर उक्त प्लाट धारक द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्यवाही कराकर अतिक्रमण हटाया, तो वही उक्त प्लाट से पानी निकासी के लिए पुन: अस्थाई नाली बनाकर,वार्ड वासियों की समस्या का वैकल्पिक समाधान किया है ।

तत्काल कार्यवाही पर परिसर वासियों ने जताया हर्ष

बताया गया कि शहर में आवासों का निर्माण, नगर पालिका की बिना परमिशन से हो रहा है,जो बूढ़ी वार्ड नं 1 माता मंदिर रोड गली नंबर 2 में भी किया गया था, जिससे पानी निकासी की समस्या निर्मित हो गई और जरा सी बारिश में लोगो के घर नालियों का गंदा पानी घुसने लगा था।शिकायत पर तत्काल मौके पर पहुचे नपा अध्यक्ष ने जहा निर्माण पर बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण हटवाया ,तो सीएमओ सूर्यप्रकाश उईके ने भी रहवासियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ही अधिनस्थल अमले को सफाई अभियान में झोंक दिया।नालियों का पानी, निजी जमीन पर रोके गई नाली को जेसीबी से खुदवाकर वैकल्पिक नाली बनाई और बहते पानी को रास्ता दिया। जिसके बाद वार्डवासियों के घरो की नालियों से पानी का बहाव सुचारू होना शुरू हो गया।और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।

जिला प्रशासन ने अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही करनी चाहिए- भारती ठाकुर

नपाध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि 4-5 दिन से कटंगी निवासी प्लांट मालिक के द्वारा यहां चलती रोड और नाली को बंद कर प्लाट में निर्माण कार्य कराया जा रहा था, दोनों साइड की नाली से पानी की निकासी नहीं हो रही थी, जिसे 30 - 40 मकान प्रभावित हो रहे थे. कल जरा सी बारिश में यहां लोगों के घरों में पानी घुस गया था, जिसकी सूचना हमें रात में मिली थी इसीलिए सुबह यहां आकर देखा गया है यहां पर रोड नाली पानी निकासी सब बंद करके रखी गई थी।मकान मालिक ने भवन निर्माण की कोई अनुमति नहीं ली है। फिर भी मकान निर्माण कराया जा रहा था।जबकि प्लाट मालिक को हमने पहले ही समझाईश दी थी की नाली के लिए जग छोड़ना पड़ेगा लेकिन वह नहीं माने जिसके बाद सख्ती दिखाते हुए जेसीबी से अवरूद्ध किए गए रास्ते और वैकल्पिक नाली का निर्माण कर पानी को सड़क किनारे निकाला है।उन्होंने आगे बताया कि नगर के अन्य जगहों पर भी ऐसी ही समस्या है जगह-जगह अवैध प्लाटिंग करके पानी निकासी को रोका गया है, ऐसे लोगो पर जिला प्रशासन ने भी कार्यवाही करनी चाहिए।

फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव, भरवेली के वार्ड नंबर 18 पंवारी मोहल्ला का मामला

आत्महत्या की कही जा रही बात, फाँसी लगाने का कारण अज्ञात, जांच में जुटी पुलिस

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भरवेली ,वार्ड नंबर 18 में बुधवार की शाम उस वक्त सनसनी मच गई,जब वार्ड के पंवारी मोहल्ला में एक 24 वर्षीय युवक का शव उसी के घर मे फांसी पर लटका हुआ मिला।जिसके फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की आंशका जताई गई है।मृतक युवक का नाम शुभम पिता जगदीश ढेकवार बताया गया है।जिसके शव का गुरुवार की सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर,अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। तो वही भरवेली पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।हालांकि युवक ने फांसी क्यों लगाई फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।

घटना के वक्त घर पर अकेला था शुभम

प्राप्त जानकारी के अनुसार भरवेली वार्ड नंबर 18 निवासी जगदीश ढेकवार मजदूरी का कार्य करते हैं। जिनके दो बेटे थे, शुभम उनका बड़ा बेटा था ,जो माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। जबकि छोटा पुत्र शिवम ढेकवार भी किसी कॉलेज में पढ़ाई करता

है।बताया गया कि बुधवार को जगदीश का छोटा पुत्र शिवम और उनकी पत्नी गांव गए थे ,जबकि जगदीश बनी मजदूरी के काम पर गया हुआ था, वही बड़ा पुत्र शुभम घर पर अकेला था।जिसका शव उसी शाम घर मे फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। जिसके आत्महत्या किए जाने की बात जा रही है।

शाम को परिजन घर लौटे तो फंदे पर लटका मिला शुभम

बताया गया कि बुधवार की शाम जब शुभम के परिजन घर वापस आए तो घर के दरवाजे अंदर से बंद थे, बाहर से बार बार आवाज लगाने पर भी घर के भीतर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था,इसी दरमियान खिड़की से झांकने पर शुभम घर के सामने वाले कमरे में स्लैप के हुक में,साड़ी का फंदा बनाकर लटका हुआ था, जो हल्का हिलडुल रहा था।यह देखने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया और शुभम को नीचे उतारा,आस पड़ोस के लोगों को आवाज देकर मामले की जानकारी दी, इसी दरमियान शुभम की मृत्यु हो गई।

मौत का कारण अज्ञात, जांच में जुटी पुलिस

उधर घटना के बाद परिजनों द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी भरवेली पुलिस को दी गई, जहां सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव व कमरे की तलाशी लेकर, पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पुरी की,जहां शाम अधिक होने के चलते शव को घर पर ही रखा गया, जिसके अगले दिन, गुरुवार की सुबह शव को जिला अस्पताल लाकर, आवश्यक कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम कराया गया।जिसके उपरांत अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है।हालांकि शुभम ने यह कदम क्यों उठाया फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसकी जांच भरवेली पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है।

उसने यह कदम क्यों उठाया, जानकारी नहीं है- गोल्डी

इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान मृतक के बड़े पिता के पुत्र भाई गोल्डी ढेकवार ने बताया कि शुभम, मायनिंग की पढ़ाई कर रहा था।बुधवार को वह घर पर अकेला था।बीती शाम जब परिजन घर वापस आए तब घटना की जानकारी लगी,उसने यह कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी नहीं है।

मामले की जांच जारी है- मडामे

वही चर्चा के दौरान भरवेली थाना एएसआई अनिल मड़ामे ने बताया कि घटना का कारण अज्ञात है, मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट और जांच के बाद ही युवक की मौत की असली वजह का पता चल पाएगा।

घर से दुकान जाने निकल युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

पोस्टमार्टम के बाद होगा खुलासा, गोंगलई निवासी है मुकेश कुर्वे

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। घर से दुकान जाने निकले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 11 जून को दोपहर में युवक बेहोशी की हालत में वैनगंगा नदी किनारे बने मंदिर के पास मिला था।जिसे डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मुकेश पिता रमेश कुर्वे 36 वर्ष ग्राम गोंगलई थाना ग्रामीणनवेगांव निवासी बताया गया है। जिसकी मौत किस वजह से हुई स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। जिला अस्पताल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्षित रखवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश के परिवार में माता-पिता और एक छोटा भाई है। मुकेश लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम मोहगांव (धपेरा) में जेवरात की दुकान में काम करता था। बताया गया कि वह प्रतिदिन अपने गांव गोंगलई से पैदल या लिफ्ट लेकर बालाघाट आता था और यहां से बस से मोहगांव पहुंचता था। शाम को वह इसी मार्ग से वापस घर लौटता था। परिजनों और आसपास के लोगों के अनुसार मुकेश को शराब पीने की आदत थी। बताया गया कि 11 जून की सुबह वह घर से पैदल ही बालाघाट के लिए निकला था। दोपहर के समय ग्राम गायखुरी के समीप वैनगंगा नदी किनारे बने मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे वह बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर डायल 112 मौके पर पहुंची और उसे जिला अस्पताल बालाघाट लेकर आये। जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद मुकेश को मृत घोषित कर दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि अस्पताल लाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की

जानकारी मिलते ही परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए थे।अस्पताल से सूचना मिलने के बाद जिला अस्पताल पुलिस ने मृतक मुकेश का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्षित रखवा दिया है। 12 जून को शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जिला सेन समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह 14 को, बैठक में हुई चर्चा

पद्मेश न्यूज।बालाघाट। जिला सेन समाज बालाघाट के तत्वावधान में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। उक्त कार्यक्रम 14 जून रविवार को दोपहर 12 बजे से भटेरा रोड़ स्थित एक होटल में

होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बालाघाट-सिवनी सांसद श्रीमती भारती पारधी, प्रमुख अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, विधायक वैशाली नगर भिलाई रीकेश सेन, भारतीय सेन समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप सेन, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा उपाध्यक्ष जमना सेन, नपाध्यक्ष रायसेन श्रीमती सविता सेन, युवा सेन समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष भोला सेन व कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में जिला सेन (नाई) समाज अध्यक्ष सत्यनारायण श्रीवास उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर भरवेली में बैठक आहूत कर चर्चा की गई। इसके अलावा विभिन्न मुद्दों को लेकर भी विचार विमर्श कर प्रतिभा सम्मान समारोह में सामाजिक बंधुओं से अधिकाधिक उपस्थिति की अपील की गई है।

सड़क हादसे ने छीनी 2 जिंदगी, युवती के बाद युवक की भी उपचार के दौरान मौत

लालबर्रा-सिवनी हाईवे में कटंगटोला नाला के पास हुआ था सड़क हादसा

पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

लालबर्रा-सिवनी हाईवे मार्ग स्थित कटंगटोला नाला के पास मंगलवार को हुए एक सड़क हादसे में गम्भीर रूप से घायल युवती के बाद गुरुवार की सुबह घायल युवक की भी उपचार के दौरान मौत हो गई।इस तरह इस सड़क हादसे ने जहां 2 जिंदगी छीन ली, तो वही एक ही गांव के युवक- युवती होने के चलते उनके गांव में शोक का माहौल व्याप्त है।मृतक युवक नाम थाना किरनापुर ग्राम धड़ी निवासी 28 वर्षीय उत्तम राहंगडाले बताता गया है।जिसका पिछले 2 दिनों गोंदिया के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था, जिसकी गुरुवार की सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई।उधर हादसे में युवक की भी मौत होने पर परिजनों ने मृतक के शव का गोंदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर, अंतिम संस्कार के लिए शव उनके गृह ग्राम थाना किरनापुर, धड़ी लाया गया।जहा परिजनों, परिचितो और ग्रामीणो की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार किया गया है।आपको बताए कि इस युवक की मृत्यु के एक दिन पूर्व बुधवार को, इसी सड़क हादसे में घायल, इसी गांव की 19 वर्षीय युवती प्रेमलता पिता टेकचंद पांचे की भी गोंदिया के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी।तो वही आज गुरुवार को युवक ने भी दम तोड़ दिया।

एक ही बाइक पर सवार होकर कही जा रहे थे, युवक युवती

प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवती और युवक, एक ही गांव के रहने वाले है, युवती प्रेमलता, मंगलवार को बीएससी सेकंड इयर का पेपर देने सुबह घर से आई थी। जिसके बाद, वह गांव के ही परिचित युवक उत्तम राहंगडाले के साथ कब गई और कहां जा रही थी।इसकी कोई जानकारी परिजनों को नहीं है।बताया गया कि ये युवक युवती लालबर्रा-सिवनी हाईवे मार्ग पर मोटर साइकिल में सवार होकर कही जा रहे थे।इसी

दरमियान मार्ग स्थित कटंगटोला नाला के पास किसी अज्ञात वाहन चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी मोटर साइकिल को ठोस मार दी और मौके से तत्काल फरार हो गया।उधर अज्ञात वाहन की ठोस से युवक युवती मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिरकर गम्भीर रूप से घायल हो गए थे।

गोंदिया के अलग अलग अस्पताल में चल रहा था उपचार

बताया गया कि इस सड़क हादसे में युवक युवती दोनो के पैर टूट गए थे और सिर तथा शरीर के अन्य हिस्सो में गंभीर चोटें आई थी। उधर हादसे के बाद उसके पास मिले मोबाईल नंबर से परिजनों को उनके सड़क हादसे में गम्भीर रूप से घायल होने की खबर मिली। जिसके बाद परिजन, लालबर्रा पहुंचे। जहां से गंभीर रूप से घायल युवक और युवती को प्राथमिक उपचार के बाद, जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया था।लेकिन उनकी नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सको ने मंगलवार शाम को ही उन्हें गोंदिया रिफर कर दिया था।जहा दोनो के परिजनों द्वारा उन्हें अलग अलग निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था।जहा बुधवार को युवती प्रेमलता की उपचार के दौरान मौत के बाद आज गुरुवार सुबह युवक की भी उपचार के दौरान मौत हो गई।

बरसात सिर पर, सर्राटी नदी पुल का एप्रोच कार्य कछुआ गति से जारी, बाढ़ आई तो बह जायेगी लाखों की लागत

प्री-मानसून की दस्तक के बाद भी निर्माण कार्य कछुआ गति से, बारिश के पूर्व कार्य पूर्ण नहीं होने पर दर्जनों गांवों का आवागमन होगा ठप

राहगीर एवं ग्रामीणों ने गुणवत्तापूर्ण एवं तीव्र गति से निर्माण करवाने की शासन-प्रशासन से की मांग

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। लालबर्रा।

नगर मुख्यालय के तहसील कार्यालय के समीप लालबर्रा से बोरी पहुंच मार्ग पर स्थित सर्राटी नदी के पुल का एप्रोच कार्य इन दिनों प्रशासनिक उदासीनता और कछुआ गति का शिकार है। करीब तीन से चार वर्ष पूर्व यह पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद से इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद था। लंबे समय तक ग्रामीणों और राहगीरों द्वारा शासन-प्रशासन से की गई मांग के बाद आखिरकार विगत माह पूर्व क्षतिग्रस्त पुल के एप्रोज निर्माण कार्य को स्वीकृति मिली थी। लेकिन निर्माण कार्य में प्रशासन के द्वारा विलंब किया गया और क्षतिग्रस्त पुल के एप्रोच निर्माण कार्य का कार्य करीब एक माह पूर्व बरसात के समीप में शुरू किया गया है। लेकिन निर्माण कार्य धीमी गति से किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में तेज बारिश होने पर निर्माण कार्य प्रभावित होने के साथ ही नदी में बाढ़ आती है तो करोड़ों रूपयों की लागत से बन रहे एप्रोज कार्य की लागत भी बह सकती है, जिससे काफी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही समय पर निर्माण कार्य नही होने पर जिस तरह से तीन से चार वर्ष से पुल क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में क्षेत्रीयजनों को परेशानी हुई है वह परेशानी इस वर्ष भी बनी रह सकती है। राहगीर एवं ग्रामीणजनों ने लालबर्रा से बोरी पहुंच मार्ग सर्राटी नदी पर बन रहे क्षतिग्रस्त पुल के एप्रोज कार्य को गुणवत्तापूर्ण एवं तीव्र गति से करवाने की शासन-प्रशासन से मांग की है।

बाढ़ आने पर काम प्रभावित होने और भारी नुकसान की आशंका

आपको बता दे कि क्षेत्र में प्री-मानसून की दस्तक हो चुकी है और आसमान में कभी भी तेज आंधी-तूफान के साथ मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो सकता है। यदि तेज बारिश होती है और सर्राटी नदी में उफान आता है, तो पानी के तेज बहाव में निर्माणाधीन एप्रोच कार्य को भारी नुकसान पहुंचने की पूरी आशंका है। साथ ही कछुआ गति से चल रहे इस कार्य के कारण करोड़ों रूपये की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट के प्रभावित होने और सरकारी राशि का दुरूपयोग होने की संभावना बनी हुई है। वहीं वर्तमान में पुल का निर्माण कार्य जारी होने के कारण वैकल्पिक मार्ग न होने से दर्जनों गांवों के ग्रामीण, राहगीर और स्कूली विद्यार्थी जान जोखिम में डालकर पुल के बाजू से, नदी के अंदर से ही आवागमन कर रहे हैं। यदि आगामी दिनों में तेज बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ता है, तो यह अस्थाई रास्ता पूरी तरह बंद हो जायेगा। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों और छात्र-छात्राओं को अधिक दूरी तय कर लालबर्रा मुख्यालय आना पड़ेगा, जिससे उनका समय और रूपये होने बर्बाद होगें।

गुणवत्ता और तीव्र गति से निर्माण करवाने की उठी मांग

लालबर्रा से बोरी पहुंच मार्ग सर्राटी नदी पर बने पुल करीब 3 से 4 वर्ष पूर्व नदी में बाढ़ आने एवं पानी के तेज बहाव में दो स्थानों से पुल क्षतिग्रस्त होकर बह गया था। जिससे इस पुल एवं मार्ग से आवागमन पुरी तरह से बंद हो चुका था। जिसके बाद पिछले वर्ष की बरसात के बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कच्चा मरम्मत कार्य करवाया गया था। उक्त कार्य होने के बाद आवागमन शुरू हुआ था लेकिन कच्चा मरम्मत कार्य होने से कुछ महीनों बाद समस्या जस की तस हो चुकी थी और लोगों को लग रहा था कि इस समस्या से हमेशा जुझना पड़ेगा। किन्तु लंबे समय बाद करोड़ों रूपयों की लागत से क्षतिग्रस्त पुल का एप्रोज कार्य प्रारंभ हो चुका है किन्तु कछुआ गति से कार्य किया जा रहा है जिससे बरसात शुरू होने के पूर्व निर्माण कार्य पूर्ण नही हुआ तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्षेत्रीयजनों एवं राहगीरों का कहना है कि निर्माण कंपनी और संबंधित विभाग को इस संवेदनशील कार्य की गंभीरता को समझना चाहिए था। मानसून सिर पर होने के बावजूद कार्य में तेजी नहीं दिखाई दे रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बरसात के पूर्व यह कार्य पूर्ण नहीं हो पायेगा। राहगीर एवं ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों से पुरजोर मांग की है कि लालबर्रा-बोरी मार्ग पर सर्राटी नदी के इस क्षतिग्रस्त पुल के एप्रोच कार्य को युध्दस्तर पर तीव्र गति से और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करवाये ताकि आवागमन में हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।

कछुआ गति से किया जा रहा निर्माण कार्य - अमीनुद्दीन

नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमीनुद्दीन हन्फी ने बताया कि मानसून ने दस्तक दे दी है और लालबर्रा से बोरी पहुंच मार्ग सर्राटी नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल का एप्रोज का निर्माण कार्य कछुआ गति से किया जा रहा है। जबकि किसी भी समय तेज बारिश हो सकती है, ऐसी स्थिति में नदी में बाढ़ आने पर निर्माण कार्य प्रभावित हो सकता है और लोगों को आवागमन में परेशानी होगी। श्री हन्फी ने बताया कि बरसात शुरू होने के पहले पुल का एप्रोज कार्य पूर्ण होना चाहिए ताकि जिस उद्देश्य से कार्य स्वीकृत करवाया गया है उसका लाभ क्षेत्रीयजनों को मिल सके। वर्तमान समय में बोरी, बल्हारपुर सहित अन्य ग्रामों के ग्रामीणजन एवं विद्यार्थी पुल के किनारे नदी के अंदर से आना-जाना कर रहे है, बारिश होने पर नदी में पानी बहने पर आवागमन में परेशानी होगी। ऐसी स्थिति में अधिक दुरी तय कर उन्हे लालबर्रा मुख्यालय आना पड़ेगा इसलिए तीव्र गति से निर्माण कार्य करवाये प्रशासन।

तीव्र गति एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण करवाये प्रशासन - भाऊराम

कांग्रेस कमेटी जिला सचिव भाऊराम गाडेश्वर ने बताया कि लालबर्रा से बोरी पहुंच मार्ग सर्राटी नदी पर बना पुल 3 से 4 वर्ष पूर्व क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके बाद लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। क्षेत्रीय विधायक महोदया के द्वारा क्षतिग्रस्त पुल के एप्रोज कार्य के लिए राशि स्वीकृत पूर्व में करवाई गई है। लेकिन प्रशासन के द्वारा निर्माण कार्य में विलंब किया गया है और बरसात शुरू होने वाली है उसे पहले कार्य प्रारंभ किया गया है। जबकि बरसात शुरू होने के 2 महीने पहले ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर देना था और अब तक बनकर तैयार होना चाहिए था किन्तु निर्माण कार्य लेट से शुरू किया गया है। श्री गाड़ेश्वर ने बताया कि कार्य भी कछुआ गति से किया जा रहा है, बरसात के पहले कार्य पूर्ण होना चाहिए, अगर नही हुआ और नदी में बाढ़ आने पर करोड़ों रूपयों की लागत से बन रहे एप्रोज कार्य को काफी नुकसान हो सकता है एवं निर्माण कार्य भी प्रभावित होगा। इसलिए प्रशासन एवं निर्माण कंपनी से मांग है कि क्षतिग्रस्त पुल का एप्रोज कार्य तीव्र गति एवं गुणवत्तापूर्ण करवाये ताकि आवागमन में हो रही परेशानियों से क्षेत्रीयजनों को निजात मिल सके।

कक्षा 5 वीं और 8 वीं की पुन: परीक्षा 16 से

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के द्वारा कक्षा 5 वीं और 8 वीं में जो छात्र-छात्राएं अनुत्तीर्ण हो चुके है एवं किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नही हो पाये ऐसे बच्चों को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया गया है। जिनकी परीक्षा आगामी 16 जून से प्रारंभ होगी जिसका टाईमटेब्लल रा'य शिक्षा केन्द्र भोपाल के द्वारा जारी कर दिया गया है। साथ ही शिक्षा विभाग भी कक्षा 5 वीं एवं 8 वीं बोर्ड की पुन: परीक्षा संपन्न करवाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। इसी कड़ी में लालबर्रा विकासखण्ड में कक्षा 5 वीं, 8 वीं बोर्ड कक्षाओं की पुन: परीक्षा के लिए 7 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है जहां 16 जून को प्रात: 10 बजे से कक्षा 5 वीं की हिन्दी/अंग्रेजी एवं कक्षा 8 वीं की हिन्दी/अंग्रेजी प्रश्नपत्र के साथ परीक्षा प्रारंभ हो जायेगी और इस पुन: परीक्षा में लालबर्रा विकासखण्ड के कक्षा 5 वीं के 34 एवं कक्षा 8 वीं के 47 बच्चें शामिल होकर अपने-अपने विषय का पर्चा हल करेगें। जिसकी तैयारी सभी 7 परीक्षा केन्द्रों में पूरी कर ली गई है और जो बच्चें अनुत्तीर्ण या फिर एक या दो विषय में फेल हो चुके थे ऐसे बच्चें शिक्षकों के मार्गदर्शन में पढ़ाई कर परीक्षा की तैयारी कर रहे है ताकि वे पुन: परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर आगे की पढ़ाई कर सके। चर्चा में बीआरसी श्रीराम तुरकर ने बताया कि राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार कक्षा 5 वीं एवं 8 वीं की पुन: परीक्षा 1 जून से प्रारंभ होने वाली थी जिसे स्थगित कर दिया गया और नया टाइमटेबल जारी किया गया है। अब 16 जून से कक्षा 5 वीं एवं 8 वीं की पुन: परीक्षा शुरू होगी। श्री तुरकर ने बताया कि गत माह कक्षा 5 वीं, 8 वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है जिसमें जो बच्चें अनुत्तीर्ण हो चुके है या फिर अनुपस्थित रहे है ऐसे बच्चों को उत्तीर्ण करने के लिए दोबारा अवसर प्रदान किया गया है। जिनकी पुन: परीक्षा आगामी 16 जून से आयोजित की गई है और लालबर्रा विकासखण्ड में कक्षा 5 वीं, 8 वीं की पुन: परीक्षा संपन्न करवाने के लिए 7 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है। साथ ही यह भी बताया कि 16 जून को प्रात: 10 बजे से कक्षा 5 वीं, 8 वीं की हिन्दी मीडियम के बच्चों की हिन्दी एवं अंग्रेजी मीडियम के बच्चों की अंग्रेजी विषय के प्रथम प्रश्नपत्र के साथ पुन: परीक्षा शुरू हो जायेगी जिसकी तैयारी पुरी कर ली गई है। श्री तुरकर ने बताया कि इस पुन: परीक्षा में कक्षा 5 वीं के 34 एवं कक्षा 8 वीं के 47 बच्चें शामिल होगें और यह परीक्षा प्रात: 10 बजे से प्रारंभ होकर 12.30 बजे संपन्न होगी एवं परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर जल्द परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

सड़क पर 'यमदूत' बने आवारा मवेशी, हादसों को दे रहे आमंत्रण

यातायात हो रहा प्रभावित, खरीफ सीजन की फसल पर मंडराया संकट, ग्रामीणों व किसानों ने मवेशी मालिकों पर कार्यवाही कर गौशाला भेजने की मांग की

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों आवारा मवेशियों का आतंक चरम पर है। बालाघाट-सिवनी हाईवे मार्ग से लेकर हाई स्कूल मार्ग, गुजरी पहुंच मार्ग, अमोली-समनापुर राज्य मार्ग और सर्राटी नदी पुल सहित हाईवे किनारे बसी ग्राम पंचायतों में जगह-जगह आवारा मवेशी 'यमदूत' बनकर घूम रहे हैं। सड़कों पर मवेशियों की इस धमाचौकड़ी से न सिर्फ आम यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, बल्कि आये दिन हादसे भी घटित हो रहे हैं। लगातार बनी दुर्घटना की आशंका के चलते राहगीरों और वाहन चालकों में भय का माहौल है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार नगर मुख्यालय में आवारा मवेशियों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। ये मवेशी शांति नगर स्थित मजार के पास, हाईस्कूल रोड, सर्राटी नदी पुल और जैन स्थानक भवन के सामने बीच सड़क पर झुंड बनाकर बैठ जाते हैं या खड़े रहते हैं। स्थिति इतनी बदतर हो जाती है कि दुपहिया व चौपहिया वाहन चालकों, साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों का निकलना दूभर हो जाता है। हॉर्न बजाने के बाद भी ये मवेशी टस से मस नहीं होते, जिससे आये दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हो रही है और दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा इन आवारा मवेशियों के मालिकों पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है। इसलिए वे बेझिझक होकर अपने मवेशियों को खुला छोड़ दे रहे है जो राहगीरों व ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनते जा रहे है।

फसलों पर भी मंडराया संकट, किसानों की बढ़ी चिंता

क्षेत्र में खरीफ सीजन की शुरूआत हो चुकी है और किसानों ने खेतों में धान के बीज (खार) की बुआई का कार्य प्रारंभ कर दिया है। कुछ ही दिनों में खेतों में खार तैयार हो जायेगी। किसानों को डर है कि ये आवारा मवेशी रात के समय खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचायेगें, जिससे उन्हे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। क्षेत्र के जागरूक नागरिकों और किसानों ने बताया कि वे लंबे समय से इन आवारा मवेशियों को पकड़कर वारासिवनी गौशाला भेजने और अपने मवेशियों को खुला छोड़ने वाले मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। किन्तु पशु मालिकों की बेफिक्री का आलम यह है कि वे दूध निकालने के बाद मवेशियों को सड़कों पर लावारिस छोड़ देते हैं। इस गंभीर समस्या के बावजूद स्थानीय ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और प्रशासनिक जिम्मेदार मौन साधे बैठे हैं। प्रशासन की इस घोर अनदेखी और उदासीनता को लेकर अब स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों में भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीयजनों एवं किसानों ने हाईवे मार्ग में यमदूत बनकर धमाचौकड़ी मचा रहे आवारा मवेशियों को पकड़कर गौशाला वारासिवनी भेजने एवं मवेशी मालिकों पर कार्यवाही करने की प्रशासन से मांग की है।

बकोड़ा में हवन-पूजन के साथ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का हुआ समापन

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय से लगभग 4 किमी दूर सांई ग्राम बकोड़ा स्थित सांई मंदिर में गत दिवस से जारी 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का गुरूवार को हवन-पूजन एवं महाप्रसादी वितरण के साथ समापन किया गया। इस 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक पू'य महंत हंसराज जी मिश्रा के द्वारा भगवान श्रीकृष्ण के जीवनलीलाओं पर संगीतमय प्रवचन दिया गया। जिससे पूरे ग्राम में ज्ञान की गंगा बही है और क्षेत्रीय श्रध्दालुओं ने कथा श्रवण कर पुण्यलाभ अर्जित किये। 7 दिनों तक चले इस संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ में व्यास पूजन, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्रराम अवतार तथा भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्मोत्सव, भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक बाल लीलाओं, माखन चोरी के नटखट प्रसंगों और गोवर्धन पूजा का अत्यंत मनोहारी व जीवंत वर्णन, उध्दव संवाद, रासलीला, कृष्ण विवाह, सुदामा चरित्र, द्वारिका लीला, यदोवंशीय उध्दार, गवलोक गमन, परिक्षित मोक्ष पर कथावाचक के द्वारा प्रवचन दिया गया और क्षेत्रीयजनों ने कथा श्रवण कर धर्मलाभ अर्जित किये। वहीं अंतिम दिन यज्ञ पूर्णाहुति एवं विशाल महाप्रसादी वितरण के साथ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का समापन किया गया। इस अवसर पर कथावाचक के द्वारा सभी श्रध्दालुओं से कहा कि कथा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे अपने जीवन में आत्मसात कर आध्यामिकता से जुड़कर एवं सत्य के बारे में चलकर बेहतर जीवन जीने एवं भगवान श्रीकृष्ण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की बात कही। इस अवसर पर आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं श्रध्दालुजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

पानी नहीं मिलने की शिकायत पर जिम्मेदार मौन, योजना के सफल संचालन की उठ रही मांग

मेंढ़की के प्रेम नगर में नल-जल योजना से ग्रामीण परेशान

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मेंढ़की के प्रेम नगर में नल जल योजना ग्रामीणों के लिये परेशानी का सबब बनी हुई हैं। योजना के माध्यम से कुछ मकानों में पानी पहुंच रहा हैं तो वहीं कुछ मकान पानी को तरस रहे हैं। यह स्थिति नल जल योजना के निर्माण के वक्त से बनी हुई हैं। जिन्हे नल से पानी मिल रहा हैं उन्हें भी पर्याप्त पानी नहीं मिलने पर ग्राम के पारम्परिक जल स्त्रोत से जरुरत का पानी प्राप्त करना पड़ रहा हैं। इस समस्या से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हैं जिनके द्वारा योजना का सफल संचालन करने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं।

पानी नही मिलने से निराशा ग्रामीण आक्रोशित

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मेंढ़की के प्रेम नगर में मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण नल जल योजना शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत की गई थी। यह योजना २३५.२८ लाख रुपए की लागत से निर्माण की गई जिसका निर्माण कार्य २९ दिसंबर २०२० को प्रारंभ कर २९ सितंबर २०२१ को पूर्ण कर दिया गया। जिसमें दो नलकूप और ५०००० लीटर की क्षमता की पानी टंकी २०० लीटर की क्षमता वाला संपवेल निर्माण किया गया। परंतु लगातार समस्याओं के चलते आज भी नल जल योजना शत प्रतिशत

पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। ग्राम में आज भी कई ऐसे परिवार है जिनके घर नल जल योजना का पानी प्राप्त नहीं होता है हालांकि उनके आसपास पानी आता है। जिसको लेकर कई बार योजना के अधिकारी एवं ग्राम पंचायत में शिकायत की गई है परंतु आज तक उनका निराकरण नहीं हो पाया है।तो वहीं कई मकान ऐसे हैं जिन्हें नल जल योजना का पानी मिलता है परंतु वह पर्याप्त नहीं होता है। वह ग्राम के लोग करीब ५०० मीटर की दूरी तय कर ग्राम में स्थित एक कुएं से निस्तार के लिए पानी लेकर जाते हैं। वहीं पीने के लिए हैंडपंप का पानी ले जाते हैं ग्राम में नल जल योजना का करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण होने के बाद भी ग्रामीणों को आज भी पारंपरिक जल स्त्रोत पर निर्भर होना पड़ रहा है। जो योजना के निर्माण और क्रियान्वयन सहित विभागीय जिम्मेदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जबकि शासन के द्वारा हर घर नल हर घर जल की बात कही जा रही है परंतु वास्तविकता में यह बात केवल कागजों में साबित हो रही है। क्योंकि हर घर नल कनेक्शन तो लगा दिया गया है, परंतु हर घर जल पहुंचने में योजना विफल साबित हो रही है। हालांकि कई ग्रामीणों के द्वारा पंचायत में शिकायत की गई है कि उनके आसपास नल जल योजना पानी मिल रहा है। उनके घर पानी नहीं आ रहा है परंतु इस पर जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिसके चलते ग्राम में लोग बहुत ज्यादा परेशान है और उनके द्वारा विभाग से इस समस्या का समाधान करने की मांग की जा रही है।

पानी नही मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है-नंदलाल सहारे

ग्रामीण नंदलाल सहारे ने बताया कि नल जल योजना का संचालन ग्राम में हो रहा है परंतु कुछ मकानों में पानी आता है कुछ मकानों में नहीं आता है। हमारे यहां दो नल लगे हैं परंतु दोनों में पानी नहीं आता है जबकि हमारे सामने वाले मकान में पानी आता है। स्थिति यह है कि हमारे नल कनेक्शन से बूंद.बूंद पानी टपकता है ऐसे में मजबूरी में हमें बाजू में स्थित कुएं से निस्तार का पानी लेना पड़ता है और पीने के लिए हैंडपंप से पानी लाते हैं। जो करीब ५०० मीटर दूर जाना होता है काफी दिक्कत है पंचायत में शिकायत भी की गई है पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं अकेला ही नहीं ग्राम में ऐसे कई परिवार है जिनके घर यह दिक्कत है इसमें सुधार होना चाहिए।

नल जल योजना का पानी नही मिल रहा है-आसनी आमाडारे

ग्रामीण श्रीमती आसनी आमाडारे ने बताया कि नल जल योजना का कनेक्शन हमारे घर में भी है परंतु उसमें पानी नहीं आता है। जब से यह नल जल योजना बनी है तब से हमारे यहां पानी नहीं आता है हम कुएं और हैंडपंप से पानी लाकर अपनी जरूरत को पूरी कर रहे हैं। इस बारे में शिकायत भी की गई है पर आज तक कुछ हुआ नहीं है हमारे जैसे और भी परिवार हैं जिन्हें अपनी नहीं मिलता है। जबकि योजना का पानी मिलना चाहिए परंतु नहीं मिलने से काफी दिक्कतें भी होती है जरूरत के लिए दूर से पानी लाकर व्यवस्था बना रहे हैं।

सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य अभ्यास वर्ग सम्पन्न

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। सरस्वती शिशु मंदिर के द्वारा विद्या भारती महाकौशल प्रांत की योजना के अनुसार आयोजित आचार्य अभ्यास वर्ग सत्र २०२६-२७ का द्वितीय दिवस अत्यंत उत्साह अनुशासन एवं शिक्षण नवाचारों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ नितिन चौधरी,मनोज पूरी गोस्वामी, चुन्नीलाल बोपचे , विजय तेलास्कर,प्रदीप तिवारी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। जिसमें जितेंद्र टेंभरे , रविशंकर पटले ,मयंक मिश्रा सहित शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। प्रथम कालखंड वंदना सत्र का रहा जिसमें चुन्नीलाल बोपचे के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने सभी आचार्यों को वंदना का शुद्ध भावपूर्ण एवं अनुशासित अभ्यास कराया तथा विद्यालयीन वातावरण में वंदना के महत्व को स्पष्ट किया। द्वितीय कालखंड में नितिन चौधरी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उन्होंने विद्यालय में आचार्यों के गुण दायित्व एवं कर्तव्यों को समझाया । तृतीय कालखंड में मनोज पूरी गोस्वामी के द्वारा मॉड्यूल एवं दक्षता आधारित शिक्षण का प्रशिक्षण दिया गया । उन्होंने शिक्षण मॉड्यूल के विभिन्न चरणों दक्षता आधारित अधिगम तथा शिक्षण कार्य में आईसीटी के प्रभावी प्रयोग के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक का समुचित उपयोग शिक्षण को अधिक रोचक प्रभावी एवं बाल केंद्रित बनाता है। चतुर्थ कालखंड में चुन्नीलाल के द्वारा योग का अभ्यास करवाया गया । उन्होंने योग के माध्यम से अनुशासन एकाग्रता के महत्व को व्यावहारिक रूप से समझाया। आचार्यों ने पूर्ण उत्साह एवं सहभागिता के साथ अभ्यास में भाग लिया। पंचम कालखंड में चेतना देवरस के द्वारा कक्षा कक्ष में आचार्यों का व्यवहार विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

आरोग्य भारती की जिला कार्यकारिणी घोषित

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के आयाम आरोग्य भारती की जिला कार्यकारिणी घोषित की गई है। यह कार्यकारिणी क्षेत्रीय संगठन मंत्री भोलानाथ के मार्गदर्शन में एवं विभाग संयोजक डॉ.नीरज अरोरा की सहमति से घोषित की गई है। जिसमें अध्यक्ष डॉ. दीपांक रामटेककर,उपाध्यक्ष डॉ.गिरेन्द्र पवार,डॉ.सुशांत शुक्ला,अविरल चावड़ा सचिव डॉ. वागीश रहांगडाले,सहसचिव डॉ,निलेश शिवहरे,डॉ.प्रभात घुले,नोकेश बिसेन,कोषाध्यक्ष डॉ.विशाल असाटी, महिला प्रमुख डॉ.जयश्री अरोरा,कार्यकारिणी सदस्य डॉ.गगन अग्रवाल,देवेन्द्र रहांगडाले,रमेश बलभद्र, किशोरी विकास प्रमुख डॉ साधना मिश्रा, वनौषधि प्रचार.प्रसार प्रमुख डॉ. मोहित पटेल,घरेलु उपचार प्रमुख डॉ. गौरव पुरी, महाविद्यालय प्रबोधन प्रमुख डॉ.रूपाल शरणागत,व्यसन मुक्ति प्रमुख डॉ.विशेष बाकट,पर्यावरण प्रमुख डी डी मेश्राम, स्वस्थ ग्राम योजना प्रमुख डॉ नरेन्द्र मेहरबान, आरोग्य संपदा प्रमुख डॉ हेमंत बिसेन,योग प्रमुख दशरथ बिसेन,संरक्षक डॉ. आर के पंड्या,डॉ.जे पी सुनेरी इसके पश्चात जिले के विभिन्न खण्ड स्तर पर दायित्व धारियों की घोषणा शीघ्र अतिशीघ्र की जावेगी।

बिठली में किसान गर्जना संगठन की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर हुआ गंभीर मंथन

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बिठली के पावन ब्रह्ममंदिर प्रांगण में किसान गर्जना संगठन की महत्वपूर्ण और व्यापक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश बंसोड के मुख्य आतिथ्य एवं जिला अध्यक्ष रामकुमार नगपुरे की गरिमामयी अध्यक्षता एवं जिला उपाध्यक्ष संदीप बिसेन, ग्रामीण अध्यक्ष नारायण पटले सहित अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से आए भारी संख्या में किसानों और ग्रामीण जनों ने सहभागिता कर अपनी अटूट एकजुटता का परिचय दिया। जहाँ संगठन विस्तार पर विस्तृत चर्चा की गई जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में संगठन की पहुंच प्रत्येक ग्राम स्तर तक सुनिश्चित की जाएगी। ताकि शोषित और जरूरतमंद किसानों की आवाज को शासन प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही संगठन को और अधिक सक्रिय व सशक्त बनाने के उद्देश्य से नए पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपने पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में क्षेत्र के किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर गहन चिंतन मनन हुआ। उपस्थित किसानों ने कृषि लागत, सिंचाई व्यवस्था, फसलों के उचित मूल्य नही मिलने जैसी प्रमुख कठिनाइयों को प्रमुखता से सामने रखा। प्रांतीय नेतृत्व ने आश्वासन दिया कि किसान गर्जना संगठन किसानों के हक की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

किसानों की समस्याओं की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी-रामकुमार नगपुरे

इस अवसर पर रामकुमार नगपुरे ने कहा की किसान हमारे देश की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता हर परिस्थिति में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जल्द ही आगामी व्यापक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर धरातल पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर हुकुमचंद बिसेन ,युगल किशोर बिसेन, राजेन्द्र बिसेन, गिरिश पटले ,गुरुदयाल भगत, रुपेन्द्र राउत ,धनश्याम राउत, काशीराम वनकर, अंकित बिसेन ,प्रतिक पटले ,अभिषेक बिसेन ,राधेश्याम राउत, हेमराज राउत ,लोमचन्द बिसेन ,ओमकार पटले ,होसलाल पटले ,बलिराम पटले ,गुनाराम पटले ,मुरली नेरकर, रामेश्वर नेरकर ,सामुलाल नेरकर ,देवदास नेरकर ,शिवराम बनकर, प्रलाद उइके ,अर्जुन उइके ,बिलराम दानवे सहित बड़ी संख्या में सक्रिय सदस्य व गणमान्य नागरिक उपस्थिति रहे।

प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन किरनापुर ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

पद्मेश न्यूज। किरनापुर। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन म.प्र.तहसील शाखा किरनापुर ने एसडीएम की अनुपस्थिति में प्रभारी तहसीलदार सुश्री बबीता सूर्या को अपनी 6सुत्री मांगो को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा पेंशनर्स की लंबीत न्यायोचित मागों का शीघ्र निराकरण करने प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स की ज्वलत लंबित समस्याओं का निराकरण नहीं होने से पेंशनर्स एवं उनके परिवार में घोर निराशा एवं असतोष व्याप्त है। यहां तक की केन्द्र की देय तिथि से ना तो मंहगाई राहत दी जाती है और न ही स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिये जा रहे है। इससे पेंशनरों का मनोबल गिरा है, निराशा हताशा ही उनके हाथ लगी है। तथा वे अभाव ग्रस्त जीवन जीने के लिये मजबूर है। पेशनर्स की मुख्य मांगे-म.प्र.राज्य पुर्नगठन अधिनियम की धारा 49(6) को अविलंब समाप्त किया जावे।2. अभी राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार केशलेस बीमा की योजना लागू की जा रही है परन्तु प्रीमीयम के रूप में कर्मचारी से 1 प्रतिशत और पेंशनर्स से 4 प्रतिशत लेने का प्रावधान किया गया है। निवेदन है कि या तो पेंशनर्स से कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जावें अथवा कर्मचारीयों से अधिक लेना तो अन्याय पूर्ण है।3. पेशनर्स को देय आर्थिक लाभ 4,6,8, माह बाद अथवा 1 वर्ष बाद भी मुश्किल से दिये जाते है। पेंशनर्स के दिये जाने वाले लाभ विलब से दिया जाना पेंशनर्स के हक पर डाका डालने जेसा है पेशनर्स को एरियर नही दिया जाता यह घोर अन्याय है। पेंशनर्स को समय पर लाभ दिया जाना अनिवार्य है। 4. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एवं अन्य न्यायालयों द्वारा निर्देश दिये गये है कि म.प्र. के पेंशनर्स को केन्द्र की तिथि से ही लाभ दिया जावे जिसके लिये उच्च न्यायालय द्वारा म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को निर्देश दिये है कि कोरोनाकाल का एरियर, छटवे वेतन मान का 32 माह का एरियर एवं 7 वें वेतन मान का 27 माह एरियर का भुगतान किया जावे इस पर अविलंब कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। यह लाभ 6 प्रतिशत ब्याज की दर से दिया जाये।5. पूर्व में दिये गये माननीय न्यायालयीन निर्णयों को मान्य किया जावे तथा 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत लाभ दिया जाता है। इसे 79 वर्ष पूर्ण होने पर दिया जाये।6. कर्मचारीयों की तरह पेंशनर्स को उपादान राशि का भुगतान किया जाने की मांग रखी ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान तहसील अध्यक्ष डी डी मेश्राम, शंकर सिंह कछ्वाह, आर पी मिश्रा, उदय राम भारद्वाज, व्ही एन मेश्राम संरक्षक मंडल,उपाध्यक्ष भूपेंद्र अजीत,सचिव अ. मुकीम कुरेशी, कोषाध्यक्ष पवन कुमार बिसेन, प्रवक्ता खुमेश अजीत, संगठन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, चैन लाल बल्के, प्रचार प्रसार मंत्री राजेंद्र हाथीमारे, जे एल बनोटे, सेक्टर प्रभारी जे एल जिजोते, अशोक रामटेके ,चंदन लाल लिल्हारे,महिला प्रकोष्ठ श्रीमती उमा ताई मेश्राम, श्रीमती राजकुमारी उके, कार्यालय सहायक उमराव पालेवार, राधे लाल सोनवाने, मुरलीधर ढाकरे, हरिदास मेश्राम, एन एल निकूसे, एम आर बागडे, बी आर डोंगरे, बिरनलाल भीमटे, घनश्याम मानेश्वर,हरिश्चंद्र पटले, काशीराम रावते, चंदन लाल लिल्हारे, देवेंद्र पाण्डेय ,विजय कुमार अमरकर, अशोक रामटेके व्हाय आर भोयर , आरपी मिश्रा और भी अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन रही है जंगल की आग

जंगल की आग (दावानल) एक अत्यंत विनाशकारी प्राकृतिक व मानवजनित आपदा है। यह अनियंत्रित आग चंद घंटों में हजारों हेक्टेयर वन भूमि, मूल्यवान पेड़ों और वन्यजीवों को राख में बदल देती है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है और भारी बर्बादी होती है।जंगल की आग के प्रभाव और नुकसान कई स्तरों पर महसूस किए जाते हैं। वन्यजीवों की मौत हो जाती है आग की चपेट में आने से कई जानवर, पक्षी और उनके बच्चे जिंदा जल जाते हैं। जो बच जाते हैं, उनके प्राकृतिक आवास और भोजन स्रोत नष्ट हो जाते हैं।आग के धुएं से भारी मात्रा में जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, सांस लेने में दिक्कत और वायु प्रदूषण होता है। बेशकीमती लकड़ियां, औषधीय पौधे और वनस्पतियां जलकर नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा, आग वाली जगह पर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है।कई बार यह आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाती है, जिससे लोगों के घर, खेत और मवेशी नष्ट हो जाते हैं। जानमाल का भारी खतरा पैदा हो जाता है।जंगल की आग में अकेले उत्तराखंड में वर्ष 2015 से अब तक 36 लोगों की जान ले चुकी है, जबकि 76 लोग घायल हुए। विश्वभर में पर्यावरण के तेजी से असंतुलित और विषाक्त होते जाने के परिणाम अब गंभीर रूपों में सामने आते जा रहे हैं। ये प्रभाव रोकने के बावजूद भले ही सामान्य लोग इनका अनुभव नहीं कर पा रहे हों लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले शोधों और अनुसंधानों में इन्हें लेकर कोई भ्रम या अनिश्चितता नहीं है। विडंबना यह है कि सारी बातें साफ तौर पर सामने रख दिए जाने के बावजूद आम लोग ही नहीं बल्कि सरकारें तक सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं। शोध बताता है कि आग से पैदा होने वाला प्रदूषण वायु गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। जंगलों की आग से निकलने वाले धुएं में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि कई ऐसे कार्बनिक यौगिक भी होते हैं जो ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी माना है कि गंगा के मैदानों की धुंध और अमेजन के जंगलों से उठने वाला धुआं वायु प्रदूषण को लगातार बढ़ा रहा है। इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य, कृषि और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। संगठन ने एक उदाहरण के माध्यम से बताया है कि दो साल पहले अमेजन में लगी आग से निकला धुआं हजारों किलोमीटर दूर बसे शहरों तक पहुंचा और वहां की हवा को गंभीर रूप से प्रदूषित कर दिया। ऐसा ही एक अध्ययन बताता है कि 2001 के बाद से जंगलों की आग से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में करीब साठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह भी बताया गया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर मौजूद जंगलों में भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में गंभीर इजाफा हुआ है। इन क्षेत्रों में हर साल करीब पचास करोड़ टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जा रहा है। आमतौर पर जंगलों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है जिसके कारण उनके संरक्षण की दिशा में कदम भी नहीं उठाए जाते। विकसित देशों तक का यही हाल है। नतीजा यह है कि वनाग्नि जैसी घटनाएं होती हैं। बुझाने के उपाय न होने के कारण यह आग फैलती जाती है और पर्यावरण खतरनाक रूप से प्रदूषित होता जाता है। भारत में वर्तमान में भीषण गर्मी और सूखे के कारण जम्मू-कश्मीर (राजौरी के नौशेरा क्षेत्र) और हिमाचल प्रदेश (चंबा और कांगड़ा के नैना देवी क्षेत्र) के जंगलों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा उत्तराखंड (चमोली और गढ़वाल क्षेत्र) के पहाड़ी इलाकों में भी अक्सर जंगलों में आग की समस्या बनी हुई है।

आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 ज़ारी- विदेशी निवेशकों को जी-सेक पर टैक्स छूट

वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा संकट,ऊंची ब्याज दरों और पूंजी प्रवाह की अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। अमेरिका- इजराइल-ईरान संघर्ष,कच्चे तेल की कीमतों में उतार- चढ़ाव और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी पूंजी के निकास ने अनेक देशों की मुद्राओं और वित्तीय बाजारों पर दबाव बढ़ाया है। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, तेल कीमतों में अस्थिरता तथा वैश्विक निवेशकों की जोखिम से बचने की प्रवृत्ति ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। पिछले कुछ महीनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों से पूंजी निकासी, डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ाया।ऐसे समय में भारत सरकार द्वारा 5 जून 2026 को जारी आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 केवल एक कर सुधार नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीतिक आर्थिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस अध्यादेश के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों तथा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) को सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज आय और पूंजीगत लाभ पर पूर्ण आयकर छूट प्रदान की गई है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। पहले विदेशी निवेशकों को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर लगभग 12.5प्रतिशत तथा ब्याज आय पर 20 प्रतिशत तकविदहोल्डिंग टैक्स का सामना करना पड़ता था, जबकि अब यह कर भार समाप्त हो गया है। यह निर्णय भारत को वैश्विक निवेश प्रतिस्पर्धा में अधिक आकर्षक बनाने, विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ाने, रुपये पर दबाव कम करने, ऋण बाजार को गहरा करने तथा शेयर बाजार को नई मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल हैं।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यदि इस कर राहत का प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव देखा जाए तो यह विदेशी निवेशकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विदेशी पेंशन फंड भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में 1000 करोड़ रुपये का निवेश करता है और उसे 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, तो पहले 70 करोड़ रुपये की ब्याज आय पर 20 प्रतिशत तक कर देयता उत्पन्न होती थी, अर्थात लगभग 14 करोड़ रुपये कर के रूप में चले जाते थे। अब यह पूरी राशि निवेशक के पास रहेगी। इसी प्रकार यदि किसी विदेशी निवेशक को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री से 100 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ प्राप्त होता था तो लगभग 12.5 करोड़ रुपये कर के रूप में देने पड़ते थे। नए प्रावधानों के बाद यह राशि भी पूर्णत: बच जाएगी। अर्थात एक बड़े संस्थागत निवेशक के लिए कुल कर बचत कई करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि वैश्विक पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, संप्रभु धन कोष और दीर्घकालिक निवेशक भारत को अब पहले से कहीं अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में सटीकता से देख सकते हैं। साथियों बात अगर हम इस सुधार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को समझने की करें तो, भारतीय ऋण बाजार को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। विश्व के अनेक विकसित और उभरते देशों ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी बॉन्ड्स पर कर संबंधी रियायतें दी हुई हैं। भारत में अपेक्षाकृत अधिक कराधान विदेशी निवेशकों के लिए एक बाधा माना जाता था। अब जब यह बाधा समाप्त हो गई है तो भारतीय सरकारी प्रतिभूतियां वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक लाभकारी और प्रतिस्पर्धी बन जाएंगी। इससे भारतीय बॉन्ड बाजार की गहराई बढ़ेगी, लेन-देन की मात्रा में वृद्धि होगी और भारत की वित्तीय प्रणाली में दीर्घकालिक स्थिर पूंजी का प्रवाह सुनिश्चित होगा।यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ महीनों से वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण भारतीय रुपये पर दबाव देखा जा रहा था। तेल आयात पर अत्यधिक निर्भरता के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा प्रभाव भारतीय मुद्रा पर पड़ता है। यदि विदेशी निवेशक बड़ी मात्रा में डॉलर लेकर भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी और डॉलर की आपूर्ति बढ़ने से रुपये को समर्थन मिलेगा। यद्यपि किसी एक नीति के कारण रुपये में तत्काल और नाटकीय मजबूती की अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन मध्यम और दीर्घकालिक अवधि में यह कदम रुपये की स्थिरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मजबूत रुपया न केवल आयात लागत को नियंत्रित करता है बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए मुद्रा जोखिम भी कम करता है, जिससे भारत में और अधिक निवेश आकर्षित होने की संभावना सटीकता से बनती है। साथियों, भारतीय शेयर बाजार पर भी इस निर्णय का बहु आयामी प्रभाव पड़ सकता है। पहली दृष्टि में यह कदम बॉन्ड बाजार से जुड़ा दिखाई देता है,लेकिन वास्तव में ऋण और इक्विटी बाजार एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब विदेशी निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए भारत आते हैं तो उनके द्वारा लाया गया पूंजी प्रवाह वित्तीय प्रणाली की समग्र तरलता को बढ़ाता है। बेहतर तरलता का लाभ अंतत: शेयर बाजार को भी मिलता है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली से जो दबाव बाजार पर बनता है, उसमें कमी आने की संभावना है। यदि विदेशी पूंजी का प्रवाह स्थिर होता है तो बाजार की धारणा में सुधार होगा और घरेलू निवेशकों का विश्वास भी सटीकता से मजबूत होगा। साथियों, सरकार द्वारा किए गए अन्य सुधार इस प्रभाव को और व्यापक बनाते हैं। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में निवेश की व्यक्तिगत सीमा को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा कुल सीमा को 24 प्रतिशत तक बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका अर्थ है कि विदेशी निवेशकों के पास अब भारतीय कंपनियों में अधिक हिस्सेदारी लेने का अवसर होगा। विशेष रूप से लार्ज- कैप और मिड-कैप कंपनियों में विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है। इससे बाजार में नई पूंजी आएगी, शेयरों की मांग बढ़ेगी और मूल्यांकन को समर्थन मिलेगा।इस नीति का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव सरकारी बॉन्ड यील्ड पर पड़ सकता है।जब किसी परिसंपत्ति की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ती है और यील्ड घटती है। यदि विदेशी निवेशकों की मांग बढ़ने से सरकारी प्रतिभूतियों की कीमतें ऊपर जाती हैं तो यील्ड में कमी आ सकती है। सरकारी बॉन्ड यील्ड को अक्सर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बेंचमार्क माना जाता है। यील्ड कम होने का अर्थ है कि सरकार, बैंक और निजी कंपनियां अपेक्षाकृत कम लागत पर धन जुटा सकेंगी। इससे कॉर्पोरेट क्षेत्र की पूंजी लागत घटेगी, निवेश बढ़ेगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

साथियों, विशेष रूप से बैंकिंग, एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट क्षेत्र इस परिवर्तन से लाभान्वित हो सकते हैं। बैंक और वित्तीय संस्थान सरकारी प्रतिभूतियों के बड़े धारक होते हैं। यदि बॉन्ड कीमतें बढ़ती हैं तो उन्हें ट्रेजरी लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं कम ब्याज दरों का वातावरण कर्ज आधारित क्षेत्रों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट परियोजनाओं की वित्तीय लागत घटने से उनकी लाभप्रदता बढ़ सकती है। इससे इन क्षेत्रों की सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय परिणाम बेहतर होने की संभावना बनती है।भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फुली एक्सेसिबल रूट के अंतर्गत 15, 30 और 40 वर्ष की नई सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे दीर्घकालिक निवेशकों को अधिक विकल्प मिलेंगे। पेंशन फंड और संप्रभु धन कोष जैसे निवेशक लंबी अवधि की परिसंपत्तियों को प्राथमिकता देते हैं। जब उन्हें भारत में लंबी अवधि की, सुरक्षित और कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियां उपलब्ध होंगी तो उनका निवेश बढ़ने की संभावना स्वाभाविक है। इसी प्रकार शॉर्ट-टर्म निवेश सीमा, कंसंट्रेशन लिमिट और व्यक्तिगत सिक्योरिटी लिमिट जैसी कई बाधाओं को हटाने से निवेश प्रक्रिया अधिक सरल और आकर्षक बनेगी।हालांकि इस नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करते समय संतुलित दृष्टिकोण अपनाना भी आवश्यक है। केवल कर छूट देना पर्याप्त नहीं होता। विदेशी निवेशक राजनीतिक स्थिरता, नियामकीय पारदर्शिता, मुद्रास्फीति, विनिमय दर जोखिम और आर्थिक विकास की संभावनाओं को भी ध्यान में रखते हैं। यदि वैश्विक वित्तीय परिस्थितियां प्रतिकूल रहती हैं या भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो अपेक्षित पूंजी प्रवाह सीमित भी रह सकता है। इसलिए इस नीति को व्यापक आर्थिक सुधारों और स्थिर नीतिगत वातावरण के साथ जोड़कर देखना चाहिए। फिर भी यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।मजबूत जनसांख्यिकीय आधार, बढ़ता उपभोक्ता बाजार, डिजिटल परिवर्तन, बुनियादी ढांचे में निवेश और अपेक्षाकृत उच्च आर्थिक विकास दर भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। ऐसे में कर छूट और निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे कदम भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को और मजबूत करते हैं।

अत: अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 भारत की वित्तीय और निवेश नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज आय और पूंजीगत लाभ को कर-मुक्त बनाकर भारत ने वैश्विक निवेशकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि वह दीर्घकालिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए गंभीर और प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से विदेशी निवेशकों की कर बचत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, भारतीय ऋण बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा, रुपये को संरचनात्मक समर्थन मिलेगा, कॉर्पोरेट क्षेत्र की पूंजी लागत घट सकती है और शेयर बाजार को नई मजबूती प्राप्त हो सकती है। यदि यह नीति अपेक्षित स्तर पर विदेशी पूंजी आकर्षित करने में सफल होती है, तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल एशिया बल्कि विश्व के प्रमुख निवेश गंतव्यों में अपनी स्थिति और अधिक मजबूत कर सकता है।

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

बचपन को श्रम नहीं, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार मिलें

हर वर्ष 12 जून को मनाया जाने वाला बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि मानवता के अंत:करण को झकझोरने वाला अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया का कोई भी बच्चा मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं होता। उसके हाथों में औजार, ईंट, बर्तन, हथौड़े, कूड़े की बोरी या कारखानों की मशीनें नहीं, बल्कि किताबें, खिलौने, रंग, सुनहले सपने और संभावनाएं होनी चाहिए। बचपन जीवन का वह स्वर्णिम काल है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, संस्कार, शिक्षा और भविष्य की नींव रखी जाती है। यदि यही काल श्रम, शोषण और अभाव की भट्टी में झोंक दिया जाए तो केवल एक बच्चे का नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन- आईअलओ द्वारा 2002 में शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य बाल श्रम की भयावहता के प्रति वैश्विक चेतना जगाना और इसके उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों को गति देना है। वर्ष 2026 में भी यह दिवस ऐसे समय पर आ रहा है जब दुनिया तकनीकी विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आर्थिक प्रगति के नए आयाम छू रही है, लेकिन दूसरी ओर करोड़ों बच्चे आज भी शिक्षा और बचपन के अधिकार से वंचित हैं। यह विडम्बना मानव सभ्यता के सामने एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। जब हम किसी ढाबे, होटल, चाय की दुकान, कारखाने, गैरेज, ईंट-भट्टे, खेत या ट्रैफिक सिग्नल पर किसी मासूम बच्चे को कठिन श्रम करते देखते हैं, तब अक्सर हमारी संवेदना कुछ क्षणों के लिए जागती है और फिर हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कब तक हम इस पीड़ा को सामान्य मानते रहेंगे? क्या हम उस बचपन की चीख नहीं सुन पा रहे जो अपने अधिकारों से वंचित होकर मजदूरी के अंधेरे में खो रहा है?

आज भी विश्व में करोड़ों बच्चे किसी न किसी रूप में बाल श्रम में संलग्न हैं। इनमें से बड़ी संख्या खतरनाक परिस्थितियों में काम करती है, जहां उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास बाधित होता है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, विस्थापन, तस्करी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और कमजोर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं बाल श्रम की प्रमुख वजहें हैं। परिवार की आर्थिक विवशताएं बच्चों को स्कूल की बजाय काम की दुनिया में धकेल देती हैं। लेकिन गरीबी का समाधान बच्चों से काम कराना नहीं, बल्कि परिवारों को सम्मानजनक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। बाल श्रम केवल आर्थिक समस्या नहीं है; यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। यह बच्चों से उनका बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, आत्मविश्वास और भविष्य छीन लेता है। जो बच्चा विद्यालय में होना चाहिए, वह यदि कारखाने में है, तो यह केवल उस बच्चे की नहीं, पूरे समाज की विफलता है। बाल श्रम गरीबी का चक्र भी बनाए रखता है, क्योंकि अशिक्षित बच्चा बड़ा होकर कम आय वाले कार्यों तक सीमित रह जाता है और अगली पीढ़ी भी उसी अभाव में जीने को मजबूर होती है। भारत सहित अनेक देशों में बाल श्रम रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईअलओ के कन्वेंशन 138 और कन्वेंशन 182 न्यूनतम कार्य आयु और बाल श्रम के सबसे खतरनाक रूपों पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। भारत में भी बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम तथा शिक्षा का अधिकार कानून मौजूद हैं। लेकिन कानूनों की प्रभावशीलता उनके कठोर और ईमानदार क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। कई बार कानूनी प्रावधान होने के बावजूद बाल श्रम छिपे हुए रूपों में जारी रहता है। आज आवश्यकता केवल कानून बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देने की है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जन-जागरण अभियान चलाए जाने चाहिए। विद्यालयों,

धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, मीडिया, उद्योग जगत और नागरिक समाज को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण और महिला अधिकारों को लेकर वैश्विक चेतना विकसित हुई है, उसी प्रकार बाल अधिकारों के लिए भी विश्वव्यापी जनमत तैयार करना होगा। कैसा विरोधाभास है कि हमारा समाज, सरकार और राजनीतिज्ञ बच्चों को देश का भविष्य मानते नहीं थकते लेकिन क्या इस उम्र के लगभग 25 से 30 करोड़ बच्चों से बाल मजदूरी के जरिए उनका बचपन और उनसे पढने का अधिकार छीनने का यह सुनियोजित षड्यंत्र नहीं लगता? मिसाल के तौर पर एक कानून बनाकर हमने बच्चों से उनका बचपन छिनने की कुचेष्टा की है। इस कानून में हमने यदि पारिवारिक कामधंधा या रोजगार है तो 4 से 14 की उम्र के बच्चों से कानूनन काम कराया जा सकता है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कैसी विडम्बना है कि जब इस उम्र के बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, खानदानी व्यवसाय के नाम पर एक पूरी पीढ़ी को शिक्षा, खेलकूद और सामान्य बाल्य सुलभ व्यवहार से वंचित किया जा रहा है और हम अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं। बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर हकीकत में हम उन्हें पैसा कमाकर लाने की मशीन बनाकर अंधकार में धकेल रहे हैं।

विशेष रूप से डिजिटल युग में तकनीक का उपयोग बाल श्रम उन्मूलन के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक उद्योग और आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शी निगरानी, बाल श्रम शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल, त्वरित कार्रवाई तंत्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणालियां विकसित की जा सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला में कहीं भी बाल श्रम का उपयोग न हो। जो कंपनियां ऐसा करती पाई जाएं, उनके विरुद्ध कठोर आर्थिक और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाल श्रम समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा है। केवल विद्यालय खोल देना पर्याप्त नहीं है; शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को आकर्षित करे, जीवनोपयोगी कौशल दे और उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास करे। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार आवश्यक है। यदि परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी तो बच्चों को मजदूरी के लिए भेजने की मजबूरी भी कम होगी।

हमें यह भी समझना होगा कि बचपन केवल जीवित रहने का नाम नहीं है; बचपन का अर्थ है सपने देखने की स्वतंत्रता, खेलने का अधिकार, सीखने का अवसर, स्नेहपूर्ण वातावरण और सुरक्षित भविष्य। जिस समाज में बच्चे मुस्कुरा नहीं सकते, वह समाज कभी वास्तविक विकास नहीं कर सकता। आर्थिक विकास की ऊंची इमारतें तब तक अधूरी हैं जब तक उनके नीचे किसी बच्चे का कुचला हुआ बचपन पड़ा हो। महान शिक्षाविद् नेल्सन मंडेला ने कहा था, किसी समाज की आत्मा को जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि हम सचमुच विकसित और संवेदनशील समाज बनना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों के प्रति दृष्टिकोण बदलना होगा। उन्हें दया का नहीं, अधिकार का विषय मानना होगा।

आज आवश्यकता है कि सरकारें बाल श्रम के विरुद्ध शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाएं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करें, तस्करी और बंधुआ श्रम के नेटवर्क को ध्वस्त करें, और हर बच्चे तक शिक्षा एवं सुरक्षा की पहुंच सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक नागरिक यह संकल्प ले कि वह किसी भी रूप में बाल श्रम को ब?ावा नहीं देगा और जहां भी ऐसी घटना देखेगा, उसके विरुद्ध आवाज उठाएगा। बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस हमें यह संदेश देता है कि बचपन को बचाना केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य की रक्षा का संकल्प है। यदि हम प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और अवसर प्रदान कर सकें, तो वही बच्चा कल एक सशक्त नागरिक, संवेदनशील मानव और राष्ट्रनिर्माता बनेगा। सच तो यह है कि बचपन को बचाना ही भविष्य को बचाना है। जब दुनिया का हर बच्चा भय और श्रम से मुक्त होकर मुस्कुराएगा, तभी मानव विकास की यात्रा वास्तव में सार्थक कहलाएगी।

-ललित गर्ग

लोभ मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु

-कांतिलाल मांडोत

मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति, सद्गुणों का विकास और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह भी है। मनुष्य के भीतर अनेक प्रकार की इच्छाएँ और आकांक्षाएँ होती हैं। इच्छाएँ जीवन को गति देती हैं और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु जब यही इच्छाएँ सीमा का अतिक्रमण कर लेती हैं और केवल अधिक से अधिक प्राप्त करने की अंधी दौड़ में परिवर्तित हो जाती हैं, तब वे लोभ का रूप धारण कर लेती हैं। लोभ या लालच ऐसा दुर्गुण है जो मनुष्य के समस्त सद्गुणों को नष्ट कर देता है और उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं तथा दुखों का कारण बनता है। इसी कारण सभी धर्मों और महान विचारकों ने लोभ को पापों की जड़ तथा मानव पतन का प्रमुख कारण बताया है।

लोभ का अर्थ है आवश्यकता से अधिक पाने की तीव्र और अनियंत्रित इच्छा। सामान्य इच्छाएँ मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक होती हैं, परंतु जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से आगे बढ़कर केवल संग्रह, स्वार्थ और भौतिक संपत्ति को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तब लोभ उत्पन्न होता है। लोभी व्यक्ति को कभी संतोष नहीं मिलता। उसके पास चाहे कितना भी धन, वैभव और प्रतिष्ठा क्यों न हो, वह और अधिक पाने की लालसा में निरंतर व्याकुल रहता है। यही असंतोष उसके मन की शांति छीन लेता है और उसे अनेक अनैतिक कार्यों की ओर प्रेरित करता है।

लोभ को पापों का जनक कहा गया है क्योंकि इसके प्रभाव में आकर व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है। वह अपने लाभ के लिए दूसरों का अहित करने में भी संकोच नहीं करता। इतिहास और वर्तमान समाज दोनों इस बात के साक्षी हैं कि अधिकांश अपराधों के पीछे किसी न किसी रूप में लोभ ही कार्य करता है। चोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, शोषण, विश्वासघात और हिंसा जैसी अनेक बुराइयों की जड़ में लालच ही पाया जाता है। जब व्यक्ति धन और संपत्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मान लेता है, तब उसके भीतर करुणा, दया, प्रेम, सत्य और ईमानदारी जैसे गुण धीरे-धीरे समाप्त होने लगते हैं। उनकी जगह क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और छल-कपट जैसे दुर्गुण जन्म लेने लगते हैं।

आज के भौतिकवादी युग में लोभ की समस्या और भी अधिक बढ़ गई है। आधुनिक समाज में सफलता का मापदंड प्राय: धन और वैभव को माना जाने लगा है। लोग अधिक धन कमाने और दूसरों से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। इस प्रतिस्पर्धा ने मानव संबंधों को भी प्रभावित किया है। अनेक बार व्यक्ति अपने परिवार, मित्रों और समाज के हितों की उपेक्षा करके केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है। धन कमाना गलत नहीं है, परंतु जब धन ही जीवन का केंद्र बन जाता है, तब जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। व्यक्ति बाहरी रूप से समृद्ध दिखाई देता है, किंतु भीतर से अशांत और असंतुष्ट बना रहता है।

लोभ का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि यह मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। लोभी व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामों का विचार नहीं रहता। वह तत्काल लाभ के आकर्षण में पड़कर ऐसे निर्णय लेता है जो अंतत: उसके लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। कई बार व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन लोगों का भी विश्वास तोड़ देता है जिन्होंने जीवनभर उसका साथ दिया होता है। इस प्रकार लोभ केवल व्यक्ति का ही नहीं बल्कि उसके संबंधों और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विनाश कर देता है।

एक प्रसिद्ध कथा इस सत्य को स्पष्ट करती है। एक धनी व्यापारी को ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई जिससे वह जिस वस्तु को स्पर्श करता, वह सोने में बदल जाती। प्रारंभ में उसे अपनी इस शक्ति पर बहुत गर्व हुआ और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपने घर की अनेक वस्तुओं को सोने में बदल दिया। किंतु जब उसके स्पर्श से उसकी प्रिय पत्नी भी स्वर्ण प्रतिमा बन गई, तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि धन और सोना जीवन की वास्तविक खुशियों का स्थान नहीं ले सकते। प्रेम, संबंध, अपनापन और मानवीय संवेदनाएँ किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। इस घटना ने उसके जीवन की दिशा बदल दी और उसे वैराग्य तथा आत्मचिंतन की ओर प्रेरित किया।

वास्तव में मनुष्य की आवश्यकताएँ सीमित होती हैं, परंतु उसकी लालसाएँ असीमित हो सकती हैं। यदि इच्छाओं पर नियंत्रण न रखा जाए तो वे कभी समाप्त नहीं होतीं। जितना अधिक व्यक्ति प्राप्त करता है, उतना ही अधिक पाने की इच्छा उसके भीतर जन्म लेती है। यह स्थिति उस समुद्र के समान है जो अनगिनत नदियों का जल प्राप्त करने के बाद भी कभी नहीं भरता। इसलिए संतोष को मानव जीवन का सबसे बड़ा धन माना गया है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति प्रयास करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है अपनी उपलब्धियों के प्रति कृतज्ञ रहना और अनैतिक साधनों से अधिक प्राप्त करने की लालसा से बचना।

आध्यात्मिक दृष्टि से भी लोभ अत्यंत हानिकारक है। यह मनुष्य को आत्मिक उन्नति से दूर कर देता है। जब व्यक्ति का मन केवल भौतिक वस्तुओं में उलझा रहता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप और जीवन के उच्च उद्देश्यों को भूल जाता है। आत्मा का सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आंतरिक शांति, सदाचार और आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। इसलिए सभी धर्मों ने संयम, त्याग और संतोष को महत्वपूर्ण गुण माना है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही वास्तविक सुख और शांति का अनुभव कर सकता है।

लोभ से बचने के लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को महत्व दें। हमें यह समझना चाहिए कि धन और संपत्ति जीवन के साधन हैं, साध्य नहीं। यदि भौतिक उपलब्धियों के साथ मानवीय संवेदनाएँ, नैतिकता और आत्मिक विकास न हो तो वह सफलता अधूरी है। हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर समझना चाहिए तथा जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सेवा, परोपकार, दान और सहयोग जैसे गुण लोभ को कम करने में सहायक होते हैं और व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं।

लोभ मानव जीवन का एक घातक दुर्गुण है जो व्यक्ति के सद्गुणों का नाश कर देता है और उसे पतन की ओर ले जाता है। यह असंतोष, अशांति और अनेक प्रकार के पापों का कारण बनता है। इसके विपरीत संतोष, संयम और सदाचार व्यक्ति को सच्चा सुख, सम्मान और आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक लालसाओं पर नियंत्रण रखे और अपने जीवन को नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर संचालित करे। यही मानव जीवन की सार्थकता है और यही वास्तविक सुख एवं सफलता का मार्ग भी है।

आरबीआई ने 135 एनबीएफसी के लाइसेंस किए रद्द, 13 ने स्वेच्छा से सौंपे प्रमाणपत्र

नई दिल्ली। एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर कड़ा रुख अपनाते हुए 135 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। इस फैसले से वित्तीय क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त, 13 एनबीएफसी ने विभिन्न व्यावसायिक कारणों से स्वेच्छा से अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र आरबीआई को वापस सौंप दिए हैं। आरबीआई ने बताया कि जिन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं, उनमें से बड़ी संख्या पश्चिम बंगाल में पंजीकृत कंपनियों की है। रद्द की गई प्रमुख कंपनियों में एक्सप्रेस फिनकैप हाउस, अक्षय फिस्कल सर्विसेज, टाइम्स फाइनेंस, जुपिटर फिनवेस्ट और एस्सेल फाइनेंस बिजनेस लोन्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। आरबीआई समय-समय पर एनबीएफसी की गतिविधियों की समीक्षा करता है और नियमों का पालन न करने या अन्य आवश्यक कारणों से ऐसे सख्त कदम उठाता है। वहीं 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने स्वेच्छा से अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र आरबीआई को सौंप दिए हैं। इन कंपनियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार से बाहर निकलने, विलय, अधिग्रहण, विघटन या स्वैच्छिक बंदी जैसे कारणों से यह कदम उठाया है। इनमें जे. थॉमस फाइनेंस, कार्नेक्स विनिमय और इम्पैक्ट लीजिंग प्रमुख हैं। कुछ कंपनियों ने अपनी कारोबारी संरचना में बदलाव के कारण लाइसेंस वापस किए, जैसे फोररनर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। कैस्पियन इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स सहित कई अन्य कंपनियों ने विलय या कानूनी रूप से समाप्त होने के कारण अपने लाइसेंस लौटाए।

उद्योगों और कॉर्पोरेट्स का हरित ऊर्जा की ओर रुझान

नई दिल्ली। एजेंसी। देश के बड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ता (सीएंडआई) अब महंगी ग्रिड बिजली की बजाय सीधे सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली खरीद रहे हैं। 30-45 फीसदी तक की लागत बचत को मुख्य कारण बताते हुए, एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2025 तक देश में सीएंडआई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर लगभग 45 गीगावॉट हो गई है। यह क्षमता वित्त वर्ष 2030 तक 121-134 गीगावॉट तक पहुंच सकती है, जो सात साल पहले के मुकाबले तीन गुना से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल बिजली मांग में सीएंडआई उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत है। उद्योगों को ग्रिड बिजली के लिए प्रति यूनिट 6.6-8.7 रुपये चुकाने पड़ते हैं, जबकि कैप्टिव सौर परियोजनाओं से यह 4-5.9 रुपये प्रति यूनिट में उपलब्ध है, जिससे 20-60 फीसदी तक बचत होती है। इस आर्थिक लाभ के कारण कंपनियां ओपन एक्सेस मॉडल अपना रही हैं, सीधे उत्पादकों से बिजली खरीद रही हैं। 2019 में नई सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में ओपन एक्सेस की हिस्सेदारी 5 फीसदी थी, जो 2024 तक 34 फीसदी हो गई। डेटा सेंटर इस बदलाव का एक बड़ा नया अवसर हैं; इनकी आईटी क्षमता 2030 तक 1.5 जीडब्ल्यू से बढ़कर 7 जीडब्ल्यू तक पहुंचने का अनुमान है, जहाँ बिजली कुल परिचालन लागत का 30-40 फीसदी होती है। 24 घंटे निर्बाध बिजली की जरूरत के कारण डेटा सेंटर भी तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज की ओर बढ़ रहे हैं।

भारत को कृषि से उद्योग की ओर बढ़ना होगा-नीति आयोग

नई दिल्ली। एजेंसी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक व्यापक सुधार एजेंडा पेश किया है, जिसमें मध्यम से दीर्घावधि में अधिशेष श्रम को उद्योग व सेवाओं में स्थानांतरित करने, कुशल बाजार बनाने और जिंस सब्सिडी को प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण में बदलने पर जोर दिया गया है। उन्होंने आगाह किया कि आधी आबादी की आजीविका के लिए कृषि पर निर्भरता, जो जीडीपी का मात्र छठा हिस्सा है, संकट का कारण है। एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में लाहिड़ी ने जोर दिया कि कृषि से अधिशेष श्रम को उद्योग और सेवाओं जैसे उत्पादक क्षेत्रों में स्थानांतरित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिंस-आधारित सब्सिडी को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण में बदलने की वकालत की, हालांकि इसे राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण बताया। लाहिड़ी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली की भी कड़ी आलोचना की, बताया कि इससे 10 फीसदी से भी कम किसानों को सीधा लाभ मिलता है, फिर भी यह फसल विविधीकरण को रोकता है और पानी-गहन अनाजों की खेती को बढ़ावा देता है। उन्होंने बिना एमएसपी समर्थन के सफल हुए मुर्गी पालन और डेयरी जैसे क्षेत्रों का उदाहरण दिया। लाहिड़ी ने निष्कर्ष निकाला कि खाद्य कमी के युग में बना एमएसपी अब अधिशेष के दौर में वित्तीय और पर्यावरणीय लागतों को बढ़ा रहा है, जिससे इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठते हैं।

अमेरिका-ईरान विवाद से सोना-चांदी में गिरावट

नई दिल्ली। एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया है। इसका सीधा असर सोने और चांदी की वायदा कीमतों पर देखने को मिल रहा है, जहां लगातार सुस्ती बनी हुई है। गुरुवार को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में इन बहुमूल्य धातुओं के भाव गिरावट के साथ खुले और खबर लिखे जाने तक इनमें तेज नरमी दर्ज की गई। भू-राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षित निवेश के प्रति बदलती धारणा ने इन कीमती धातुओं पर दबाव डाला है। वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों में आए बदलाव, विशेषकर अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे उभरे तनाव, ने सोने और चांदी के वायदा भाव को बुरी तरह प्रभावित किया है। गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने और चांदी के वायदा भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 1,499 की गिरावट के साथ 1,46,518 रुपए के भाव पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,48,017 रुपए था। खबर लिखे जाने तक यह कॉन्ट्रैक्ट 1,026 की गिरावट के साथ 1,46,991 पर कारोबार कर रहा था, जो 1,47,051 रुपए के दिन के उच्च स्तर से नीचे है। वहीं चांदी का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 3,834 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ 2,31,671 पर खुला। इसका पिछला बंद भाव 2,35,505 रुपए था। खबर लिखे जाने तक यह कॉन्ट्रैक्ट 3,249 की नरमी के साथ 2,32,256 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस साल सोने ने 1,80,779 और चांदी ने 4,20,048 रुपए के उच्चतम स्तर को छुआ था, जो मौजूदा गिरावट की गंभीरता को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की चमक फीकी पड़ी है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 150, निफ्टी 53 अंक गिरा

मुंबई। एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के तीसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से भी निवेशकों ने बाजार से दूरी बना ली है। अमेरिका द्वारा ईरान पर की गई ताजा सैन्य कार्रवाई के बाद वैश्विक बाजारों में चिंता बनी हुई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई का बेंचमार्क सेंसेक्स 150.63 अंक टूटकर 73,832.55 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 53.35 अंक टूटकर 23,161.60 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा गिरावट तकनीकी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्षेत्र में रही। निफ्टी आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और केमिकल इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे।

आईटी कंपनी इन्फोसिस के शेयर सबसे अधिक गिरे। व्यापक बाजार में मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी गिरावट रही। निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर नीचे आये। हालांकि निफ्टी मीडिया, प्राइवेट बैंक और फार्मा क्षेत्र के शेयरों में बढ़त रही। इससे बाजार की गिरावट पर अंकुश लगा। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार गिरावट के साथ खुले। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से निवेशकों की धारणा को कमजोर कर दिया। सुबह के कारोबार में, प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। शुरुआत में सेंसेक्स 311.08 अंक की गिरावट के साथ 73,672.10 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी भी 86.20 अंक फिसलकर 23,128.75 के स्तर पर आ गया। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका द्वारा ईरान पर नए हमलों और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कड़े बयानों ने वैश्विक निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसका सीधा असर एशियाई बाजारों सहित भारतीय बाजार पर भी पड़ा है।

एथेनॉल वाले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क खत्म

नई दिल्ली। एजेंसी। पेट्रोल में उच्च एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब 22 से 30 फीसदी तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इस फैसले से ग्राहकों, तेल कंपनियों और आम किसानों को सीधा फायदा पहुंचने की उम्मीद है, साथ ही देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के जरिए ई22, ई25, ई27 और ई30 श्रेणी के पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क शून्य किया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश भारत, लंबे समय से पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की नीति पर काम कर रहा है। यह कदम कच्चे तेल आयात पर निर्भरता कम करेगा और भविष्य में ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने में सहायक होगा। एथेनॉल गन्ने और मक्का जैसे कृषि उत्पादों से बनने वाला एक जैव-ईंधन (बायोफ्यूल) है। इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और एथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि क्षेत्र में मांग बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के लिए वाहन निर्माताओं को अनुकूल इंजन विकसित करने होंगे। सरकार का यह महत्वपूर्ण निर्णय देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और हरित ईंधन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

एल्युमिनियम फॉइल पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी 15 दिसंबर तक जारी रहेगी

नई दिल्ली। एजेंसी। भारत सरकार ने घरेलू एल्युमिनियम फॉइल निर्माताओं को बड़ी राहत देते हुए चीन, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से आने वाले सस्ते एल्युमिनियम फॉइल पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी 15 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योगों को विदेशी डंपिंग से बचाना और उन्हें प्रतिस्पर्धी माहौल देना है। यह ड्यूटी विशेष रूप से 80 माइक्रोन या उससे पतले एल्युमिनियम फॉइल पर लागू होगी। एंटी-डंपिंग शुल्क विदेशी उत्पादों पर तब लगता है, जब उन्हें उनके उत्पादन लागत से भी कम दाम पर भारतीय बाजार में बेचा जाता है। यह अक्सर विदेशी कंपनियों द्वारा बाजार पर कब्जा करने की रणनीति होती है। इस कदम से विदेशी आयात महंगा होगा और भारतीय कंपनियों को उचित प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से भारतीय एल्युमिनियम फॉइल उत्पादक, जैसे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को सीधा फायदा होगा। ये कंपनियां लंबे समय से इस ड्यूटी को जारी रखने की मांग कर रही थीं, क्योंकि सस्ते आयात से उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। अब घरेलू उत्पादों की बिक्री बढ़ने से उत्पादन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल खाद्य पैकेजिंग, दवा और कई अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में बड़े पैमाने पर होता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज इस मामले की सनसेट रिव्यू के तहत जांच कर रहा है, और जब तक यह पूरी नहीं होती, यह ड्यूटी लागू रहेगी। सरकार का यह कदम देश के उद्योगों को मजबूत बनाने और विदेशी सस्ता आयात कम करने की दिशा में एक अहम पहल है।

मेष- आज का दिन मिला-जुला रहेगा, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच हर स्थिति को आसान बना देगी। मन में ईर्ष्या या नकारात्मकता रखने से बचें। सेहत से जुड़ी किसी पुरानी समस्या को अब नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। रिश्तों में गर्माहट लौटेगी और सगे-संबंधियों से मुलाकात का मौका मिलेगा। जीवनसाथी के साथ पुरानी अनबन दूर होगी और साथ में कहीं घूमने का प्लान बन सकता है।

वृषभ- आज भाग्य आपके साथ खड़ा नजर आएगा। मेहनत का फल मिलेगा और आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। कोर्ट-कचहरी का मामला आपके पक्ष में जा सकता है। रिश्तों में चल रही खटास बातचीत से खत्म होगी। भाई-बहनों का सहयोग आपके लिए मददगार साबित होगा। दोस्तों का दायरा बढ़ने से सामाजिक जीवन में रौनक बनी रहेगी।

मिथुन- आज का दिन संतुलन और शांति लेकर आएगा। किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होकर मन को सुकून मिलेगा। राजनीति या सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े लोग जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। पुराने मनमुटाव को खत्म करने के लिए पहल करेंगे, जिससे रिश्तों में मिठास लौटेगी।

कर्क- आज का दिन सामान्य लेकिन स्थिर रहेगा। नए काम की शुरुआत का विचार मन में आ सकता है, लेकिन अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा न करें। आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत करेगा। किसी काम में समय पर मदद मिल जाएगी। पिताजी की किसी बात से मन थोड़ा दुखी हो सकता है।

सिंह- आज परिवार और रिश्तों में तालमेल बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपकी समझदारी उनके हर प्रयास को कमजोर कर देगी। संतान की संगति पर नजर रखें। घूमने-फिरने की योजना बन सकती है। नौकरी से जुड़ी परेशानी होने पर नए विकल्पों पर विचार करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।

कन्या- आज दिल की कोई इच्छा पूरी होने से मन खुश रहेगा। जीवनसाथी के लिए कोई खास गिफ्ट खरीद सकते हैं। माता-पिता की सेवा में समय बिताकर आत्मिक शांति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में समस्याओं को लेकर वरिष्ठों से खुलकर बातचीत करना फायदेमंद रहेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने के प्रयास तेज होंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

तुला- आज खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलना जरूरी होगा। काम का दबाव ज्यादा रहेगा और परिवार को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है। संतान की सेहत को लेकर मन परेशान रहेगा। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। बिजनेस में बदलाव करने का विचार मन में आएगा।

वृश्चिक- आज मन किसी फैसले को लेकर उलझा रह सकता है, लेकिन खुद पर भरोसा रखना जरूरी होगा। सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। गुस्से पर कंट्रोल रखना आज सबसे बड़ी सीख साबित होगा। बिजनेस से जुड़ी समस्या को सुलझाने के लिए पार्टनर से खुलकर बात करनी होगी। अनजान लोगों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा।

धनु- आज का दिन भागदौड़ से भरा रहेगा। जरूरी कामों को टालना नुकसान दे सकता है। परिवार के मामलों को मिल-बैठकर सुलझाने से रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ मिलकर किसी नए काम की शुरुआत का विचार बन सकता है। पिताजी से सलाह लेने पर मन की चिंता दूर होगी। रुका हुआ काम पूरा होने से राहत मिलेगी।

मकर- आज जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। निवेश से लाभ मिलने के योग हैं। खानपान में सुधार से सेहत बेहतर रहेगी। मन की कोई इच्छा पूरी होने से खुशी का माहौल रहेगा। वैवाहिक जीवन में तालमेल अच्छा बना रहेगा, हालांकि भागदौड़ बनी रह सकती है।

कुंभ- आज चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन परिवार और दोस्तों का साथ आपको मजबूत बनाए रखेगा। दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें। आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी दूर रहने वाले अपने की याद भावुक कर सकती है। विद्यार्थी करियर से जुड़े कामों में व्यस्त रहेंगे।

मीन- आज सामाजिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में सफलता के संकेत हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास सफल रहेंगे। नौकरी के नए अवसर सामने आ सकते हैं। माता-पिता के साथ संपत्ति को लेकर चर्चा हो सकती है। अचानक यात्रा का योग बन रहा है, जो लाभदायक साबित होगी।

शब्दजाल - 8287

कं	क	दो	यु	ला	प	नं	दा	दे	वी	क
ज	च	ल	प	ह	रिं	गा	ना	द्रि	शा	त्रि
अं	इ	व	म	सं	दा	प	श	र	ला	शू
क	कु	दा	जं	धा	ब	र्व	नू	रि	श	ल
क	ति	श	न	घा	क	त	न	न	वी	ता
सा	से	र	कां	ग	ड़ी	र्त	कू	ती	कू	रु
पौ	हु	न	री	अं	गा	म	य	कौ	ला	न
क	बा	अ	ब	टी	क	शे	त	न	श	चौ
क	स	थो	गि	व	न	ज	र	शा	जू	खं
द	र	ना	प	ति	रं	र्त	ऐ	ब्र	प	बा
थो	दू	सा	रु	मा	नी	हो	जा	एं	म	क

शब्द जाल में भारत के 10 प्रमुख पर्वतों के नाम ढूंढिए. नाम उपर से नीचे एवं तिरछे भी हैं.

कंचनजंघा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, चौखंबा, दूनागिरी, सासेर कांगड़ी, नूनकून, गाशेर ब्रम, पौहुनरी, त्रिशूल

शब्दजाल - 8286 का हल

फिल्म वर्ग पहेली - 7231

बायें से दायें:-

१. अमोल पालेकर, ज़रीना की 'दो दीवाने शहर में' गीत वाली फिल्म-३
३. 'बंबई से रेल चली' गीत वाली अक्षयकुमार, ममू की फिल्म-३
६. सुनीलदत्त, नूतन की 'सावन का महीना' गीत वाली फिल्म-३
७. 'ये हवाएं सर्द हैं' गीत वाली राजेश, मिथुन, शबाना की फिल्म-४
१०. फिल्म 'नरसिम्हा' में नायक कौन था-२
११. 'तुम को कितना है प्यार' गीत वाली फिल्म-२
१२. 'आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है' की नायिका कौन थी-४
१४. 'अनपढ़' में धर्मेन्द्र की नायिका-२
१५. फिल्म 'देवदास' में 'चंद्रमुखी' कौन बनी है?-३
१६. 'दिन प्यार के आये रे' गीत वाली शेखर, कामिनी कौशल की फिल्म-२
१७. अमिताभ, शशिकपूर, शत्रुघ्न, राखी, परवीन, विदिया गोस्वामी की फिल्म-२
१८. शशिकपूर, जीनत की 'तैरा ने भी प्यार किया' गीत वाली फिल्म-३
२०. 'सुना था देखा न था' गीत वाली आफताब, उर्मीला की फिल्म-३
२१. आमिर, माधुरी की 'साथ जैसी खड़ी हैं' गीत वाली फिल्म-२
२२. फिल्म 'ब्लैकमेल' में नायिका कौन थी?-२
२३. अक्षय, माधुरी की 'अब तेरे दिल में' गीत वाली फिल्म-३
२६. 'ऊपरवाला दुखियों की' गीत वाली दिलीप, सायरा बानो की फिल्म-३
२८. प्रसिद्ध बालगीत 'आओ बच्चों तुम्हें दिखायें' किस फिल्म का है?-३
२९. 'मैं प्यार का पुजारी' गीत वाली गोविंदा, नीलम की फिल्म-२
३०. प्रदीपकुमार, वैजयंती की 'जादूगर सैंया' गीत वाली फिल्म-३

ऊपर से नीचे:-

१. 'आजकल पाँव जमीं पर' गीत वाली फिल्म-२
२. 'गवाह हैं चाँद तारे' गीत वाली फिल्म-३
३. अक्षय कुमार, करिश्मा की 'सच कहते हैं हम' गीत वाली फिल्म-४
४. 'काली नागिन के जैसी' गीत वाली फिल्म-२
५. राज कपूर, नर्गिस की 'ये शाम की तनहाइयाँ' गीत वाली फिल्म-२
८. 'बात बात में रूठो ना' गीत वाली बलराज साहनी, नूतन की फिल्म-२
९. 'शोला और शबनम' में नायिका कौन थी-३
१०. फिल्म 'सनम बेवफा' में चांदनी के साथ नायक कौन था?-४
१२. 'चोरी चोरी कोई आए' गीत वाली फारुख शेख, पूनम की फिल्म-२
१३. संजय कपूर, शिल्पा की 'टक टका टक' गीत वाली फिल्म-३
१४. 'काले लिबास में बदन' गीत वाली इंद्रकुमार, आयशा की फिल्म-३
१७. जॉय मुखर्जी, साधना की 'उड़ के पवन के संग' गीत वाली फिल्म-३
१९. 'ऐ दीवाने दिल' गीत वाली अक्षय कुमार, सोनाली बेंद्रे की फिल्म-३
२१. 'हाँ हाँ ये प्यार है' गीत वाली फिल्म-३
२४. फिल्म 'आँखियों से गोली मारे' की नायिका कौन है?-३
२५. 'काश तुम मुझ' गीत वाली संजय, रवीना, करिश्मा की फिल्म-३
२६. 'सपने में मिलती है' गीत वाली फिल्म-२
२७. फिल्म 'भूत' में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका किसने की है?-२
२८. 'नैनों में मतवाले' गीत वाली फिल्म-२

फिल्म वर्ग पहेली - 7230

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

12 जून 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति	लग्नारंभ समय
सूर्य	वृष में	मिथुन 05.31 बजे से
चंद्र	मेष में	कर्क 07.44 बजे से
मंगल	मेष में	सिंह 10.01 बजे से
बुध	मिथुन में	कन्या 12.12 बजे से
गुरु	कर्क में	तुला 14.23 बजे से
शुक्र	कर्क में	वृश्चिक 16.38 बजे से
शनि	मीन में	धनु 18.54 बजे से
राहु	कुंभ में	मकर 20.59 बजे से
केतु	सिंह में	कुंभ 22.45 बजे से
		मीन 00.18 बजे से
		मेष 01.49 बजे से
		वृष 03.29 बजे से

राहुकाल 10.30 से 12.00 बजे तक

शुक्रवार 2026 वर्ष का 163 वां दिन
दिशाशूल पश्चिम **ऋतु** ग्रीष्म।
विक्रम संवत् 2083 **शक संवत्** 1948
मास ज्येष्ठ **पक्ष** कृष्ण
तिथि द्वादशी 19.37 बजे को समाप्त।
नक्षत्र अश्विनी 06.29 बजे तदनन्तर भरणी 04.06 बजे रात को समाप्त।
योग अतिगण्ड 21.26 बजे को समाप्त।
करण कौलव 09.11 बजे तदनन्तर तैतिल 19.37 बजे को समाप्त।
चन्द्रायु 24.2 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 23° 08'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1872738
जूलियन दिन 2461203.5
कलियुग संवत् 5128
कल्पारंभ संवत् 1972949128
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885128
वीरनिर्वाण संवत् 2552
हिजरी सन् 1447
महीना जिल्हेज **तारीख** 26
विशेष प्रदोष व्रत।

दिन का चौघड़िया		रात का चौघड़िया	
चर	05.55 से 07.23 बजे तक	रोग	05.38 से 07.11 बजे तक
लाभ	07.23 से 08.51 बजे तक	काल	07.11 से 08.43 बजे तक
अमृत	08.51 से 10.19 बजे तक	लाभ	08.43 से 10.15 बजे तक
काल	10.19 से 11.47 बजे तक	उद्वेग	10.15 से 11.47 बजे तक
शुभ	11.47 से 01.15 बजे तक	शुभ	11.47 से 01.19 बजे तक
रोग	01.15 से 02.43 बजे तक	अमृत	01.19 से 02.51 बजे तक
उद्वेग	02.43 से 04.10 बजे तक	चर	02.51 से 04.23 बजे तक
चर	04.10 से 05.38 बजे तक	रोग	04.23 से 05.55 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, मध्यम चर, अशुभ उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

प्रसंगतः प्रेमचंद की गाय

उन दिनों प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक मुंशी प्रेमचंद गोरखपुर में अध्यापक थे। उन्होंने अपने यहाँ गाय पाल रखी थी। एक दिन चरते-चरते उनकी गाय वहाँ के अंग्रेज जिलाधीश के आवास के बाहरवाले उद्यान में घुस गई। अभी वह गाय वहाँ जाकर खड़ी ही हुई थी कि वह अंग्रेज बंदूक लेकर बाहर आ गया और उसने गुस्से से आग बबूला होकर बंदूक में गोली भर ली। उसी समय अपनी गाय को खोजते हुए प्रेमचंद वहाँ पहुँच गए। अंग्रेज ने कहा कि 'यह गाय अब तुम यहाँ से ले नहीं जा सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने जानवर को मेरे उद्यान में घुसा दिया। मैं इसे अभी गोली मार देता हूँ, तभी तुम काले लोगों को यह बात समझ में आएगी कि हम यहाँ हुकूमत कर रहे हैं।' और उसने भरी बंदूक गाय की ओर तान दी। प्रेमचंद ने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की, 'महोदय! इस बार गाय पर मेहरबानी करें। दूसरे दिन से इधर नहीं आएगी। मुझे ले जाने दें साहब। यह गलती से यहाँ आई।' फिर भी अंग्रेज झल्लाकर यही कहता रहा, 'तुम काला आदमी ईडियट हो - हम गाय को गोली मारेगा।' और उसने बंदूक से गाय को निशान बनाना चाहा। प्रेमचंद झट से गाय और अंग्रेज जिलाधीश के बीच में आ खड़े हुए और गुस्से से बोले, 'तो फिर चला गोली। देखूँ तुझमें कितनी हिम्मत है। ले। पहले मुझे गोली मार।' फिर तो अंग्रेज की हेकड़ी हिरन हो गई। वह बंदूक की नली नीची कर कहता हुआ अपने बंगले में घुस गया।

सूडोकु नवताल- 7540

★☆☆☆☆ सरल

		2				1		
				2	5	7	3	
	9	4		6	7			2
	5		4		3			9
	8			9			7	
1			6		8		2	
6			7	4		9	5	
	4	5	8	3				
		8				6		

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7539 का हल

9	1	6	2	3	7	4	5	8
8	2	3	4	5	9	1	7	6
4	5	7	1	6	8	3	9	2
5	6	8	7	1	2	9	3	4
1	7	4	9	8	3	2	6	5
2	3	9	5	4	6	8	1	7
7	4	1	8	9	5	6	2	3
3	8	5	6	2	1	7	4	9
6	9	2	3	7	4	5	8	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्द पहेली - 8755

बाएँ से दाएँ

1. जंगल की आग-4
4. अयोग्य, नालायक-4
6. बंदर का खेल दिखाने वाला-3
8. तैयार होना-3
9. जीभ, जिव्हा-3
11. पाश, फंदा, -2
13. नामकरण करना-2,3
15. मेरा(सं.-2)
16. खाद्य सामग्री-3
18. तहत-3
19. कक्ष, रूम-3
20. भरोसा, विश्वास-4
22. सचेत, होशियार-4

ऊपर से नीचे

1. दागी, धब्बेवाला-4
2. गीलापन, तर होना-2
3. दुनिया, जगत-3
4. अदा, हाव-भाव-5
5. भरा हुआ-4
7. टपकना, गिरना-3
10. नाम रखना-5
12. एकमत-4
14. भक्षक, विनाशकारी-3
17. खारा, क्षारीय-4
18. वन, जंगल-3
21. लाश, मुर्दा, मृतक-4

शब्द पहेली - 8754 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

बोलेगांव दुर्गा मंदिर के समीप बना पुलिया हुआ क्षतिग्रस्त

बारिश से पहले बढ़ी ग्रामीणों की चिंता, शिकायतों के बाद भी नहीं जागे जिम्मेदार; निर्माण की गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल

पद्मेश न्यूज। लांजी। लाखों रुपये की सरकारी राशि खर्च कर बनाए जाने वाले पुल और पुलियों का उद्देश्य वर्षों तक जनता को सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना होता है, लेकिन बोलेगांव में दुर्गा मंदिर के पास स्थित स्लैब कलवर्ट पुलिया का हाल इस दावे पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहा है। लगभग 36.62 लाख रुपये की लागत से निर्मित यह पुलिया निर्माण के महज तीन वर्ष के भीतर ही बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। पुलिया से जुड़ी एप्रोच रोड नीचे बैठ जाने के कारण पुल और सड़क के जोड़ वाले हिस्से पर बड़ा गड्ढा उभर आया है, जो राहगीरों और वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि आगामी 15 से 20 दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। ऐसे में यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो आवागमन जोखिम भरा हो जाएगा। स्थानीय लोगों के अनुसार विशेष रूप से रात के समय या बारिश के दौरान यह गड्ढा दिखाई नहीं देता, जिससे दोपहिया वाहन चालक असंतुलित होकर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कोई वाहन तेज रफ्तार में इस हिस्से से गुजरे तो बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिया निर्माण के दौरान एप्रोच रोड को तकनीकी मानकों के अनुरूप पुल से नहीं जोड़ा गया। उचित कॉम्पेक्शन और गुणवत्ता नियंत्रण नहीं होने के कारण समय के साथ सड़क धंसती चली गई

और अब पुलिया के दोनों ओर खतरनाक स्थिति निर्मित हो गई है। लोगों का कहना है कि यह केवल सामान्य टूट-फूट का मामला नहीं, बल्कि निर्माण गुणवत्ता से जुड़ा गंभीर विषय है, जिसकी जांच होनी चाहिए।

ठेकेदार नहीं उठाता फोन, कौन करेगा मरम्मत..?

ग्रामीणों के अनुसार इस समस्या को लेकर ठेकेदार को 50 से अधिक बार फोन कर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक न तो कोई निरीक्षण किया गया और न ही मरम्मत की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया। इससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब निर्माण के कुछ वर्षों बाद ही पुलिया की यह स्थिति है, तो इसकी गुणवत्ता का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में किसी आरसीसी पुल या स्लैब कलवर्ट की आयु कई दशकों तक मानी जाती है। गुणवत्तापूर्ण निर्माण और नियमित रखरखाव होने पर ऐसे निर्माण 30 से 50 वर्ष या उससे अधिक समय तक सुरक्षित रूप से उपयोग में बने रहते हैं। ऐसे में महज तीन वर्ष के भीतर एप्रोच रोड का धंस जाना और पुलिया के समीप खतरनाक गड्ढा उभर आना निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। बारिश सिर पर है और स्थिति दिन-प्रतिदिन चिंताजनक होती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद जनता को टिकाऊ और सुरक्षित निर्माण कब मिलेगा, और यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना से हुआ था निर्माण

जानकारी के अनुसार उक्त निर्माण कार्य प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत कराया गया था। बोलेगांव दुर्गा मंदिर से बस्ती मार्ग पर स्थित इस स्लैब कलवर्ट का निर्माण 7 अप्रैल 2023 से 3 अगस्त 2023 के बीच पूर्ण किया गया था। इसकी स्वीकृत लागत 36.62 लाख रुपये थी। निर्माण कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक-02, बालाघाट रही, जबकि कार्य का ठेका रामेश्वर कटरे को दिया गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई और इसी का परिणाम आज सामने दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि यदि निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुरूप किया गया होता तो तीन वर्ष के भीतर ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। ग्रामीणों ने पुलिया की तकनीकी जांच, निर्माण गुणवत्ता की स्वतंत्र पड़ताल तथा दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।

इनका कहना है

पुलिया से जुड़ी समस्या की जानकारी विभाग के संज्ञान में आ चुकी है। संबंधित ठेकेदार को पत्र जारी कर आवश्यक मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मौके पर सुधार कार्य कराकर ग्रामीणों को इस समस्या से राहत दिलाई जाएगी।

टी.पी. परते, सहायक यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस)

पीएम स्वनिधि योजना ने बदली राखी गजबे की जिंदगी, आज सफलतापूर्वक संचालित कर रही हैं क्लॉथ स्टोर

पद्मेश न्यूज। लांजी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। नगर परिषद लांजी की वार्ड क्रमांक 02 निवासी श्रीमती राखी गजबे ने इस योजना का लाभ लेकर न केवल अपना व्यवसाय स्थापित किया, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाया है। श्रीमती राखी गजबे बताती हैं कि कोरोना महामारी के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। परिवार के भरण-पोषण के लिए कोई स्थायी आय का साधन नहीं था। वह स्वयं का क्लॉथ स्टोर खोलना चाहती थीं, लेकिन पूंजी के अभाव में उनका सपना अधूरा था। इसी दौरान उन्हें नगर परिषद लांजी के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जानकारी मिली। योजना के तहत उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया और उन्हें प्रथम चरण में ऋण राशि प्राप्त हुई। इस राशि से उन्होंने अपने क्लॉथ स्टोर व्यवसाय की शुरुआत की। व्यवसाय शुरू होने के बाद उनकी मासिक आय में वृद्धि हुई और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। समय पर ऋण चुकाने और व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित करने के कारण उन्हें योजना के अगले चरणों में भी ऋण की सुविधा मिलती रही। वर्तमान में उन्हें तृतीय चरण में 50 हजार रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है, जिससे उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। आज उनका क्लॉथ स्टोर लांजी के सुभाष चौक में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है और उन्हें नियमित आय प्राप्त हो रही है।

श्रीमती राखी गजबे को पीएम स्वनिधि योजना के साथ-साथ 'मैं भी डिजिटल' तथा 'स्वनिधि से समृद्धि' योजनाओं का भी लाभ मिला है, जिससे उनके व्यवसाय को और मजबूती मिली है। राखी गजबे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि इस योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है। आज वह अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं।

मुख्यमंत्री के नाम पेंशनर्स ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

महंगाई राहत एरियर भुगतान और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित कई मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही सरकार, पेंशनर्स ने जताई नाराजगी

पद्मेश न्यूज। लांजी। प्रोगेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन तहसील शाखा लांजी ने पेंशनर्स की लंबित मांगों के निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लांजी के माध्यम से सौंपा। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि वर्षों से लंबित मांगों पर उचित ध्यान नहीं दिए जाने के कारण प्रदेश के करीब पांच लाख पेंशनर्स और उनके परिवारों में गहरा असंतोष व्याप्त है। ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुरूप पेंशनर्स को महंगाई राहत और अन्य आर्थिक लाभ समय पर नहीं मिल रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव में वरिष्ठ नागरिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। एसोसिएशन ने प्रमुख मांगों में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को समाप्त करने की मांग उठाई, जिसे पेंशनर्स के अधिकारों में बाधक बताया गया। वहीं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का स्वागत करते हुए उसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों में समानता लाने की मांग की गई। एसोसिएशन का कहना है कि कर्मचारियों से एक प्रतिशत और पेंशनर्स से चार प्रतिशत प्रीमियम लिया जाना न्यायसंगत नहीं है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि पेंशनर्स को मिलने वाले आर्थिक लाभ और एरियर का भुगतान कई महीनों अथवा वर्षों की देरी से किया जाता है। संगठन ने इसे पेंशनर्स के अधिकारों का हनन बताते हुए सभी देयकों का

समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। पेंशनर्स ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित विभिन्न न्यायालयों के आदेशों का हवाला देते हुए मांग की कि मध्यप्रदेश के पेंशनर्स को भी केंद्र सरकार की देय तिथि से लाभ प्रदान किए जाएं। साथ ही कोरोना काल का बकाया एरियर, छठवें वेतनमान का 32 माह तथा सातवें वेतनमान का 27 माह का एरियर छह प्रतिशत ब्याज सहित शीघ्र भुगतान करने की मांग रखी गई। इसके अतिरिक्त संगठन ने 80 वर्ष की आयु पर मिलने वाले 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन लाभ को पूर्व न्यायालयीन निर्णयों के अनुरूप 79 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लागू करने तथा नियमित कर्मचारियों की भांति पेंशनर्स को भी उपादान राशि (ग्रेच्युटी) का लाभ प्रदान करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान पेंशनर्स ने इंकलाब जिंदाबाद और पेंशनर्स एकता जिंदाबाद के नारे लगाए तथा चेतावनी दी कि यदि उनकी न्यायोचित मांगों पर शीघ्र और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान तहसील अध्यक्ष सेवकराम ठाकरे, सचिव आई.एस. चौहान, एन.एल. बसेना, बी.के. पारधी, गजलाल दमोह, बलवंत बाहे, तिलकचंद धामने, कन्हैयालाल बनोटे, बी.आर. बनोटे, लुकचंद चौधरी, डी.आर. लिल्हारे, के.आर. नाईक, लालाराम नंदनवार, उमंगप्रसाद कबीरे, लखनलाल मुछावड़, धनीराम सोनवाने, तेजराम लिल्हारे, श्यामदेव येरपुड़े, हृदयराम राहंगडाले, भक्त प्रहलाद ठाकरे, सदाराम धारने, सोनीप्रसाद टेंभरे, परमेश्वर कुथे, जागेश्वर एड़े, जगनलाल चौधरी, बेनीराम ढोक, ठाकुर दास पटले, पी.एल. मस्करे सहित बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना से लक्ष्मी पशीने के पक्के घर का सपना हुआ साकार

पद्मेश न्यूज। लांजी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आशा की नई किरण बनकर उभरी है। नगर परिषद लांजी के अंतर्गत रहने वाली श्रीमती लक्ष्मी पशीने पति श्री मनोज पशीने ने इस योजना का लाभ प्राप्त कर अपने पक्के घर का सपना साकार किया है। श्रीमती लक्ष्मी पशीने अपने परिवार के साथ लंबे समय से एक जर्जर कच्चे मकान में निवास कर रही थीं। परिवार में पति-पत्नी एवं उनकी पुत्री शामिल हैं। मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले इस परिवार के लिए पक्का मकान बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। बारिश के दिनों में कच्चे मकान की छत से पानी टपकता था और सांप-बिच्छू एवं अन्य जहरीले जीव-जंतुओं का भय हमेशा बना रहता था। छोटी बच्ची को भी प्रतिकूल परिस्थितियों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी दौरान उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने नगर परिषद लांजी में आवेदन प्रस्तुत किया। पात्रता जांच के बाद उनका चयन योजना के लिए किया गया और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 2.50 लाख रुपये की सहायता राशि किश्तों में प्राप्त हुई। प्राप्त राशि का उपयोग कर श्रीमती लक्ष्मी पशीने ने अपना पक्का आवास निर्मित कराया। आज उनका परिवार सुरक्षित और सुविधाजनक पक्के घर में निवास कर रहा है। आवास निर्माण के बाद उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है। वर्तमान में वे मजदूरी कार्य के साथ-साथ सिलाई का कार्य भी कर रही हैं, जिससे परिवार की आय में वृद्धि हो रही है। श्रीमती लक्ष्मी पशीने का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके परिवार को नई पहचान और सुरक्षा प्रदान की है। वे इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हैं। उनका मानना है कि यह योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में होगा सामूहिक योग कार्यक्रम

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2026 को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी कुलसचिवों, प्राचार्यों एवं संबंधित संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए निर्धारित गतिविधियों का पालन किया जाएगा। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से कहा गया है कि वे योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। कार्यक्रम की तैयारी के तहत 19 जून 2026 को विद्यार्थियों को प्रशिक्षित योग शिक्षकों द्वारा योगाभ्यास कराया जाएगा। सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को योग के अनुरूप आरामदायक वेशभूषा धारण करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को योग दिवस कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, 21 जून को आयोजित गतिविधियों की एकत्रित प्रतिवेदन रिपोर्ट 24 जून 2026 तक उच्च शिक्षा विभाग को भेजने के लिए कहा गया है। उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना तथा विद्यार्थियों में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है।

लांजी में "पद्मेश"
इंटरनेट (ब्राडबेंड)
कनेक्शन के लिये संपर्क करें
Mo. 8319969927

दिग्विजय सिंह के 'अपमान' पर कांग्रेस में घमासान

समर्थकों ने प्रभारी हरीश चौधरी के खिलाफ खोला मोर्चा

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मचे अंदरूनी घमासान ने अब एक बड़ा रूप ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई तनातनी का वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की आग भड़क उठी है। दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने अब सीधे प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे संगठन के भीतर एक बड़े नए विवाद के संकेत मिल रहे हैं।

वीडियो सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह के समर्थक बेहद आक्रोशित हैं। समर्थकों ने आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व को दो टूक संदेश देते हुए कहा है। राजा साहब (दिग्विजय सिंह) हमारे मार्गदर्शक और अभिभावक हैं। उनका अपमान हमारा व्यक्तिगत अपमान है। इसके बाद सामने फिर चाहे वह कोई भी बड़ा नेता क्यों न हो, हमारे लिए उसका अब कोई महत्व नहीं है।। समर्थकों के इस कड़े रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और अंदरूनी कलह और ज्यादा गहराने वाली है।

दरअसल, मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर बुलाई गई कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब दिग्विजय सिंह ने जेपी धनोपिया को बोलने के लिए कहा, तो प्रभारी हरीश चौधरी ने उन्हें बीच में टोकते हुए कह दिया था कि हम कर लेंगे। इस पर दिग्विजय सिंह ने हाथ जोड़ लिए थे और बाद में जीतू पटवारी के आग्रह पर भी मीडिया से बात करने से मना कर दिया था। इसी 'मंच युद्ध' ने अब कांग्रेस के भीतर एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है।

बीजेपी ने कसा तंज

मंच पर वरिष्ठ नेता के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर विपक्षी दल बीजेपी को भी कांग्रेस पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। बीजेपी के फायरब्रांड विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखा तंज कसा है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में स्थानीय और वरिष्ठ नेताओं का लगातार अपमान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली से आने वाले नेता यहाँ के कद्दावर नेताओं को अपमानित करते हैं, जो इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी को दिग्विजय सिंह ने अपने जीवन के इतने साल दिए, वहीं आज उनका यह हश्र हो रहा है। ऐसे में अब दिग्विजय सिंह को सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए।

मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा निर्विरोध विजयी

भोपाल। मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्वाचित होने का प्रमाणपत्र सौंप दिया। इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने सभी तीनों सीटों पर कब्जा कर लिया। राज्यसभा चुनाव के दौरान तीसरी सीट को लेकर राजनीतिक मुकाबले की संभावना थी, क्योंकि कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस के पास उम्मीदवार को मैदान में बनाए रखने के लिए आवश्यक संख्याबल भी मौजूद था, लेकिन 9 जून को उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। इसके बाद चुनाव का पूरा समीकरण बदल गया और भाजपा उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो गया।

नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर मोर्चा खोला। पार्टी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। दूसरी ओर, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से भी मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आयोग की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बुधवार को कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा और नामांकन निरस्त किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि उसके उम्मीदवार को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने के कारण उसे राज्यसभा की संभावित सीट से वंचित होना पड़ा।

उधर, निर्वाचन प्रमाणपत्र जारी होने के बाद भाजपा ने इसे अपनी संगठनात्मक मजबूती और विधानसभा में बहुमत का परिणाम बताया है। पार्टी नेताओं ने तीनों सीटों पर जीत को राज्य में भाजपा के प्रभाव और समर्थन का संकेत बताया। इस बीच, कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठकें जारी हैं, जिनमें आगे की कानूनी और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह मामला राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया और नामांकन निरस्तीकरण की वैधता से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है।

डीएपी खाद की किल्लत से भड़के किसान, सिवनी में किया चक्काजाम

भोपाल। खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खाद की भारी कमी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खाद की अनुपलब्धता और कालाबाजारी के आरोपों से नाराज किसानों ने चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि समय पर उर्वरक नहीं मिलने से फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है।

जानकारी के अनुसार सिवनी जिले के बंडोल क्षेत्र में डीएपी खाद को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि बिना ई-टोकन के किसानों को निर्धारित मूल्य से कहीं अधिक दरों पर खाद बेची जा रही थी। जहां डीएपी की सरकारी कीमत निर्धारित है, वहीं कुछ स्थानों पर इसे 2400 से 2500 रुपये प्रति बोरी तक बेचे जाने की शिकायतें मिलीं। शिकायतों के बाद कृषि विभाग ने मामले की जांच शुरू की। बताया गया कि कृषि अधिकारी स्वयं किसान बनकर खाद केंद्रों पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जांच में अनियमितताएं पाए जाने के बाद संबंधित गोदामों को सील कर दिया गया तथा संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है।

वहीं दूसरी तरफ खाद संकट को लेकर किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। कई स्थानों पर किसानों ने मुख्य मार्गों और हाईवे पर चक्काजाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं होने और वितरण व्यवस्था में खामियों के कारण उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। इससे बोवनी प्रभावित हो रही है आने वाले समय में फसल को भी खासा नुक्सान हो सकता है। किसानों की सबसे बड़ी शिकायत ई-टोकन प्रणाली को लेकर है। उनका कहना है कि टोकन मिलने में देरी और तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें कई बार सरकारी केंद्रों से खाली हाथ लौटना पड़ता है। वहीं मांग के मुकाबले सीमित आपूर्ति होने से वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें लग रही हैं।

इससे पहले नर्मदापुरम जिले के सिवनी-मालवा क्षेत्र में भी खाद की कमी को लेकर किसानों ने विरोध दर्ज कराया था। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से डीएपी और अन्य उर्वरकों की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे खरीफ सीजन की तैयारियों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। कृषि विभाग का कहना है कि कालाबाजारी और अवैध वसूली के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है तथा किसानों को निर्धारित दरों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं।

ई-टोकन पाने रातभर जाग रहे, बोवनी के समय झेल रहे खाद-बीज की किल्लत

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों को खाद और बीज उपलब्ध न होने पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का गरीब, कर्जदार किसान तो आज भी खाद, बीज, सिंचाई, उचित मूल्य, बढ़ते कर्ज के संकट से जूझ रहा है। उन्होंने एक्स पर किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए लिखा- राज्य के अशोकनगर, सिवनी, विदिशा, गुना, राजगढ़ जैसे कई जिलों में किसान आधी रात से खाद के लिए लाइन लग रहे हैं, ई-टोकन के लिए रातभर जाग रहे हैं, बोवनी के समय में खाद-बीज की किल्लत झेल रहे हैं।

पीएम मोदी द्वारा किसानों की स्थिति में आ रहे बदलाव की बात पर जीतू पटवारी ने कहा कि मेरी समझ से यह परे है कि आप कौन-से देश के किसानों की समृद्धि की तस्वीर बता रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का गरीब, कर्जदार किसान तो आज भी खाद, बीज, सिंचाई, उचित मूल्य, बढ़ते कर्ज के संकट से जूझ रहा है। पटवारी ने किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा, पीएम-किसान सम्मान निधि पर सवाल उठाया और कहा कि जब डीजल, खाद, बीज और कृषि लागत रोजाना और लगातार बढ़ रही है तो किसानों की वास्तविक आय क्यों नहीं बढ़ रही है? उन्होंने किसान आत्महत्या को लेकर कहा कि देश में किसान, कृषि मजदूर आत्महत्याओं का संकट भी चिंता का विषय है। राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि 2023 में खेती-किसानी से जुड़े आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है। किसान सम्मान निधि की छह हजार रुपए की सालाना सहायता ऊंट के मुंह में राई है, क्योंकि यह राशि बढ़ती कृषि लागत, महंगी खाद, बिजली, सिंचाई और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर पटवारी ने कहा कि किसान को अब भाषण नहीं, समय पर खाद चाहिए। सरकारी प्रचार नहीं, उपज का लाभकारी मूल्य चाहिए। किसान को हैशटैग नहीं, खेती की गारंटी चाहिए। सीएम मोहन यादव भी राज्य के इस जमीनी सच से इनकार नहीं कर सकते कि जब तक खेत की मेड़ पर खड़ा किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक सोशल मीडिया पर लिखी गई किसान समृद्धि झूठी ही मानी जाएगी।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में ऑनलाइन होगी उत्तरपुस्तिकाओं की जांच

भोपाल। भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) ने उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन को डिजिटल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय की योजना के अनुसार करीब तीन लाख उत्तरपुस्तिकाओं को स्कैन कर ऑनलाइन जांचा जाएगा। इसके लिए डिजिटल एजेंसी और तकनीकी व्यवस्था विकसित की जा रही है। नई प्रणाली में कॉपियों की हार्ड कॉपी परीक्षकों तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि स्कैन की गई प्रतियां कंप्यूटर पर उपलब्ध होंगी। प्रत्येक परीक्षक को यूनिक आईडी दी जाएगी और पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। हालांकि पिछले वर्ष सीबीएसई की 12वीं परीक्षा के परिणामों में स्कैन की गई उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर विवाद सामने आया था।

उर्वरकों की कालाबाजारी एवं किसानों के आर्थिक शोषण की शिकायतों की उच्चस्तरीय जांच हो - दिग्विजय सिंह

भोपाल । पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश में डीएपी, एसएसपी तथा विभिन्न कॉम्प्लेक्स उर्वरकों के वितरण और बिक्री में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसानों एवं किसान संगठनों द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि सहकारी समितियों, विपणन संस्थाओं तथा निजी विक्रेताओं के माध्यम से उर्वरकों का विक्रय मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दरों पर किया जा रहा है। किसानों की यह भी शिकायत है कि पुराने स्टॉक में उपलब्ध उर्वरकों, जिनकी खरीद एवं मुद्रित कीमत कम थी, उन्हें पीओएस एवं ई-टोकन प्रणाली में प्रदर्शित नई एवं बढ़ी हुई दरों पर बेचा जा रहा है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 20-20-0-13 उर्वरक की 50 किलोग्राम की एक बोरी, जिसकी पूर्व निर्धारित कीमत लगभग 1450 रुपये थी, उसे कई स्थानों पर 2100 रुपये तक में बेचे जाने की शिकायतें मिली हैं। इससे किसानों पर प्रति बैग लगभग 650 रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसी प्रकार एसएसपी एवं अन्य उर्वरकों के संबंध में भी अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह मामला केवल मूल्य वृद्धि का नहीं, बल्कि किसानों के उपभोक्ता अधिकारों, पारदर्शिता तथा कानून के संभावित उल्लंघन से भी जुड़ा हुआ है। फर्टिलाईजर (कंट्रोल) आर्डर, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी उर्वरक की बिक्री उसके मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दर पर नहीं की जा सकती।

उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रदेशभर में उर्वरक वितरण एवं विक्रय व्यवस्था की विशेष और स्वतंत्र जांच कराई जाए, पुराने स्टॉक पर नई दरों की वसूली की शिकायतों की जिला स्तर पर जांच हो, किसानों से अधिक वसूली गई राशि वापस कराई जाए तथा दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाई की जाए।

हर साल भर्ती परीक्षाओं पर लग रहा ग्रहण

नाम बदला, सिस्टम बदला, लेकिन नहीं बदली परेशानी

भोपाल (ईएमएस)। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए भर्ती परीक्षाएं अब केवल प्रतिस्पर्धा की नहीं, बल्कि अनिश्चितता की भी परीक्षा बन गई हैं। व्यापमं घोटाले के बाद परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए बड़े बदलाव किए गए। व्यापमं का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) रखा गया, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू की गई और तकनीकी निगरानी बढ़ाई गई। इसके बावजूद भर्ती परीक्षाओं के निरस्त होने, परिणामों में संशोधन और तकनीकी खामियों का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला 7 जून 2026 को आयोजित वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा का है। परीक्षा की दूसरी पाली सर्वर डाउन होने के कारण निरस्त करनी पड़ी। हजारों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के बाद बिना परीक्षा दिए लौटने को मजबूर हुए। अब उन्हें दोबारा परीक्षा का इंतजार करना होगा। यह घटना एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है।

प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए भर्ती परीक्षाएं लगातार चिंता का कारण बनती जा रही हैं। मप्र कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) में तकनीकी गड़बड़ियां और परीक्षा स्थगित होने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वर्ष 2026 में एमपीईएसबी को 14 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करनी हैं। लेकिन 7 जून को आयोजित वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरी पाली सर्वर डाउन होने के कारण निरस्त करनी पड़ी। इसके बाद से एमपीईएसबी की विश्वसनियता पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी खामियों के कारण कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे महीनों तक तैयारी करते हैं, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में समय और पैसा खर्च करते हैं, लेकिन तकनीकी खामियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। परीक्षा होने के बाद भी परिणाम आने में लंबा समय लगने से नियुक्ति प्रक्रिया और अधिक विलंबित हो जाती है।

हर साल दोहराई जा रही पुरानी कहानी

रिकॉर्ड बताते हैं कि यह कोई अपवाद नहीं, बल्कि लगातार सामने आ रही समस्या है। वर्ष 2025 में समूह-1 और समूह-2 की संयुक्त भर्ती परीक्षा तकनीकी कारणों से पुनर्निर्धारित करनी पड़ी। इसी वर्ष समूह-1 उपसमूह-3 की परीक्षा की पहली पाली सर्वर फेल होने के कारण निरस्त कर दी गई थी। साल 2024 में आबकारी आरक्षक, समूह-4 और महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षाएं विभिन्न कारणों से प्रभावित हुईं। 2023 में कृषि और उद्यान विभाग की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद दोबारा संशोधित परिणाम जारी करना पड़ा। 2022 में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर और अन्य समूह परीक्षाओं के परिणामों में बदलाव करना पड़ा। वहीं 2021 में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के कारण कई परीक्षाएं दोबारा आयोजित करनी पड़ी थीं।

तकनीकी खामी का बोझ अभ्यर्थियों पर

भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों का सबसे बड़ा असर अभ्यर्थियों पर पड़ता है। कई उम्मीदवार दूरदराज जिलों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते हैं। यात्रा, आवास और तैयारी पर हजारों रुपये खर्च होते हैं। परीक्षा निरस्त होने या परिणामों में बदलाव होने पर न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि मानसिक तनाव और भविष्य की अनिश्चितता भी बढ़ जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि वे महीनों तक तैयारी करते हैं, लेकिन तकनीकी खामियों और प्रशासनिक कमजोरियों की कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। कई मामलों में परीक्षा के बाद परिणाम आने में भी लंबा समय लग जाता है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया वर्षों तक खिंच जाती है।

सवाल सिर्फ सर्वर का नहीं, भरोसे का भी

विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या केवल तकनीकी नहीं है। यदि लगातार कई वर्षों तक परीक्षाएं निरस्त होती हैं, परिणाम संशोधित किए जाते हैं या प्रक्रिया दोबारा करानी पड़ती है, तो इससे पूरी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। व्यापमं कांड के बाद जिस भरोसे को बहाल करने की कोशिश की गई थी, वह बार-बार ऐसी घटनाओं से कमजोर पड़ता दिखाई देता है।

2026 में 14 परीक्षाओं की चुनौती

एमपीईएसबी को वर्ष 2026 में 14 प्रमुख भर्ती परीक्षाएं आयोजित करनी हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती केवल परीक्षा आयोजित करना नहीं, बल्कि उसे बिना तकनीकी बाधा, बिना विवाद और समयबद्ध परिणामों के साथ पूरा करना है। क्योंकि अब अभ्यर्थियों का सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया पर भरोसे का भी है। एमपीईएसबी के जनसंपर्क अधिकारी विशाल जोशी का कहना है कि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उनके अनुसार तकनीकी कारणों से कभी-कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, लेकिन इन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। फिर भी बड़ा सवाल कायम है कि जब हर वर्ष किसी न किसी भर्ती परीक्षा पर तकनीकी या प्रशासनिक संकट खड़ा हो रहा है, तो आखिर परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह भरोसेमंद कब बनेगी?

17 पुराने श्रम कानून खत्म, अब एक ही एक्ट में होंगे सभी नियम

रातभर खुल सकेंगे थिएटर-रेस्टोरेंट, कर्मचारी खुद तय करेंगे साप्ताहिक अवकाश

भोपाल । मध्यप्रदेश में श्रम कानूनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार 17 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर उनकी जगह एक व्यापक और एकीकृत श्रम कानून लागू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत थिएटर, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति मिल सकेगी, जबकि कर्मचारियों को अपनी साप्ताहिक छुट्टी चुनने का अधिकार भी मिलेगा। सरकार का दावा है कि नए कानून से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और उद्योगों तथा कर्मचारियों दोनों के हितों में संतुलन स्थापित होगा। इसके लिए अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति प्रारूप तैयार कर रही है। समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं और मसौदा अंतिम चरण में बताया जा रहा है।

दुकानों और प्रतिष्ठानों पर खत्म होंगी कई पुरानी पाबंदियां

वर्तमान व्यवस्था में दुकानों, रेस्टोरेंट और मनोरंजन प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित है। नए कानून के लागू होने के बाद समय संबंधी अधिकांश प्रतिबंध हट सकते हैं। इससे बड़े शहरों में 24म7 व्यावसायिक गतिविधियों का रास्ता खुलेगा। सरकार का मानना है कि इससे शिफ्ट आधारित रोजगार बढ़ेगा और सेवा क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। नए प्रावधानों के तहत यदि कोई प्रतिष्ठान चौबीसों घंटे संचालित होता है तो कर्मचारियों को अलग-अलग शिफ्टों में काम करने का विकल्प मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों को सप्ताह में एक अनिवार्य अवकाश मिलेगा, लेकिन यह अवकाश किस दिन होगा, इसका चयन कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकेंगे।

निरीक्षक राज पर भी लग सकती है रोक

प्रस्तावित कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। नई दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए सरकारी निरीक्षक की अनिवार्य भौतिक जांच की व्यवस्था समाप्त की जा सकती है। व्यापारी केवल आवेदन देकर अपना प्रतिष्ठान शुरू कर सकेंगे। इससे अनुमति प्रक्रियाओं में देरी और अनावश्यक हस्तक्षेप कम होने की उम्मीद है।

केंद्र के लेबर कोड की तर्ज पर बनेगा नया ढांचा

केंद्र सरकार ने श्रम क्षेत्र से जुड़े दर्जनों कानूनों को समाहित कर चार लेबर कोड बनाए हैं। अब मध्यप्रदेश भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। प्रस्तावित राज्य कानून में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, कार्यस्थल सुरक्षा और श्रमिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रावधानों को एकीकृत किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद राज्य के कई पुराने कानून समाप्त हो जाएंगे और श्रम प्रशासन का पूरा ढांचा एक ही कानून के तहत संचालित होगा। इससे उद्योगों, व्यापारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग नियमों और प्रक्रियाओं से राहत मिलने की संभावना है।

रोजगार बनाम श्रमिक अधिकारों की बहस

सरकार जहां इसे निवेश और रोजगार बढ़ाने वाला कदम बता रही है, वहीं श्रमिक संगठनों की नजर इस बात पर रहेगी कि 24 घंटे संचालन और लचीले कार्य प्रावधानों के बीच कर्मचारियों के अधिकार, कार्य घंटे, ओवरटाइम और सामाजिक सुरक्षा कितनी प्रभावी बनी रहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नए कानून में श्रमिक सुरक्षा और व्यापारिक सुविधा के बीच संतुलन कायम रखा गया तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार

मप्र के 11 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को मिल सकता है स्वास्थ्य बीमा का बड़ा लाभ

कैबिनेट में जल्द आ सकता है प्रस्ताव, कर्मचारियों को 20 लाख और पेंशनरों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा

भोपाल। मध्यप्रदेश के 11 लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को जल्द मंजूरी मिल सकती है। राज्य सरकार इस योजना का प्रस्ताव इसी माह कैबिनेट के समक्ष रख सकती है। यदि मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये तक और पेंशनरों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा। सूत्रों के अनुसार योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे संचालित करने की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को सौंपी जाएगी। यह एजेंसी वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना का संचालन भी कर रही है।

कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का विचार नया नहीं है। वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया था और 1 अप्रैल 2020 से शुरू करने की तैयारी थी। हालांकि राजनीतिक बदलाव और बाद की प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण योजना फाइलों में ही अटकी रही। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों के मॉडल का अध्ययन करने के बाद अब इसका नया प्रारूप तैयार किया गया है। यदि योजना को अंतिम मंजूरी मिलती है तो करीब छह वर्ष बाद यह महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर उतर सकेगी।

योजना के संचालन के लिए सरकार के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों को भी प्रीमियम का एक हिस्सा देना होगा। प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारियों से उनके मूल वेतन का 1 प्रतिशत मासिक अंशदान लिया जाएगा, जबकि पेंशनरों से उनकी पेंशन का 4 प्रतिशत योगदान प्रस्तावित है। सरकार का मानना है कि साझा अंशदान मॉडल से योजना वित्तीय रूप से टिकाऊ रहेगी और लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सकेगी।

आयुष्मान की तर्ज पर बनेगा डिजिटल हेल्थ कार्ड

योजना के तहत प्रत्येक पात्र कर्मचारी और पेंशनर परिवार को फोटोयुक्त यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। इसकी मदद से सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार मिल सकेगा। अस्पतालों का पैनल बनाया जाएगा और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए व्यापक कवरेज उपलब्ध कराने की तैयारी है। विशेष परिस्थितियों में यदि मरीज को किसी गैर-अनुबंधित अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपचार खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जा सकेगी।

परिवार के सदस्य भी होंगे पात्र

प्रस्तावित योजना में कर्मचारी के पति या पत्नी, माता-पिता, आश्रित दो बच्चे, दत्तक संतान और तलाकशुदा पुत्री को भी शामिल किया गया है। पेंशनरों के मामले में पति-पत्नी दोनों को योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बीमित कर्मचारियों को ओपीडी, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए प्रतिवर्ष 20 हजार रुपये तक की अलग सहायता देने का भी प्रस्ताव है।

कर्मचारियों की पुरानी मांग पूरी होने की उम्मीद

प्रदेश के कर्मचारी संगठन लंबे समय से व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना की मांग करते रहे हैं। उनका तर्क रहा है कि गंभीर बीमारियों के इलाज में होने वाला भारी खर्च कर्मचारियों और पेंशनरों पर आर्थिक दबाव डालता है। ऐसे में यह योजना लागू होने पर लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है।

अफगानिस्तान ए ने भारत ए को हराया, डीएलएस नियम बना कारण

दांबुला । भारत ए टीम यहां अफगानिस्तान ए टीम के खिलाफ हुए त्रिकोणीय सीरीज के अपने दूसरे मैच में 349 रनों का विशाल स्कोर बनाने के बाद भी हार गयी। इसका कारण बारिश होने के कारण डीएलएस नियम से किया गया फैसला रहा। इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाज करते हुए 9 विकेट पर 349 रन बनाए। इसक बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने 25.5 ओवर में ही दो विकेट पर 177 रन बना लिए थे। डीएलएस के आधार पर अफगानिस्तान ए को इतने समय तक 174 रन बनाने थे। ऐसे में उसे चार रनों से आगे होने के कारण विजेता घोषित कर दिया गया।

वहीं इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रभसिमरन सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा के अर्धशतको से भारत ए ने यहां त्रिकोणीय सीरीज में अफगानिस्तान ए के खिलाफ 49 ओवर में 9 विकेट खोकर 349 रन बनाये। इस प्रकार

अफगान टीम को जीत के लिए 350 रनों का कठिन लक्ष्य मिला। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही। वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 7.1 ओवर में 74 रन जोड़े। वैभव ने तेजी से खेलते हुए केवल 22 गेंदों में 44 रन बनाए। वहीं प्रियांश आर्या केवल 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और प्रभसिमरन ने तीसरे विकेट के लिए 74 गेंदों में 79 रन बनाये। ऋतुराज ने 80 गेंदों पर 66 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं प्रभसिमरन अपने शतक से रह गए और 69 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 84 रन ही बना पाये। आयुष बदोनी शून्य पर ही आउट हुए। वहीं तिलक ने 73 गेंदों में 5 चौके लगाकर 66 रन बनाए।

सूर्यांश शेडगे ने 27 गेंदों में 40 रन बनाये वहीं अरशद खान केवल एक रन ही बना सके। अनुकूल रॉय ने 8 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 16 रन बनाए। वहीं, विपराज निगम ने 3 गेंदों में 8 रन बनाए। अफगानिस्तान ए की ओर से गेंदबाजी में अब्दुल्ला अहमदजई ने 68 रन देकर 5 विकेट लिए जबकि फरमानुल्लाह साफी ने 3 विकेट जबकि कप्तान इमरान मीर ने एक विकेट लिया।

भारत में जन्मे क्रिकेटर निखिल चौधरी ऑस्ट्रेलियाई टीम से खेलेंगे

मेलबर्न । ऑस्ट्रेलियाई टी20 क्रिकेट टीम में भारत में जन्मे निखिल चौधरी को शामिल किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने बांग्लादेश दौरे के लिए अपनी टी20 टीम में अनुभवी बल्लेबाज ट्रैविस हेड की जगह पर निखिल को शामिल किया है। दिल्ली में जन्में निखिल अगर बांग्लादेश के खिलाफ 17 जून से शुरू होने वाली तीन मैच की टी20 सीरीज में डेब्यू करते हैं, तो वह 60 से अधिक सालों में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले भारत में जन्मे पहले खिलाड़ी बन जाएंगे।

ऑस्ट्रेलियाई टीम में भारतीय मूल के कई खिलाड़ी, जैसे गुरिंदर संधू और तनवीर संघा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं पर इन दोनो का जन्म भारत में नहीं हुआ था। इससे पहले 1960 के दशक में गुजरात में गुजरात में जन्मे लेग-स्पिनर रेक्स सेलर्स ने 1964 में कलकत्ता टेस्ट में खेला था, और तब से कोई भी भारतीय मूल का खिलाड़ी जिसने भारत में जन्म लिया हो, ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा नहीं बना। इस लिहाज से, यदि 30 वर्षीय चौधरी अगले हफ्ते मैदान पर उतरते हैं, तो यह उनके लिए एक अविस्मरणीय पदार्पण होगा और वे एक नया इतिहास रचेंगे।

निखिल अभी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नहीं, बल्कि स्थायी निवासी हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के सभी पात्रता मानदंडों को पूरा किया है, जिससे उन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने की अनुमति मिल गई है। दिल्ली में जन्मे चौधरी ने अपने शुरुआती करियर में पंजाब के लिए 14 सीमित ओवर मैच खेले हैं, जहाँ उन्होंने हरभजन सिंह, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के साथ खेले। उन्होंने आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के साथ ट्रायल्स में भी हिस्सा लिया था।पूर्व अंतर्राष्ट्रीय ऑलराउंडर जेम्स होप्स के कहने पर उन्हें बिग बैश लीग (बीबीएल) में होबार्ट हरिकेंस में शामिल किया गया था। वह पिछले तीन ब्बकसीजन से, चौधरी हरिकेंस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उभरे हैं। पिछले समर में बल्ले से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, जहाँ उन्होंने 30.70 की औसत और 153 के स्ट्राइक-रेट से 307 रन बनाए।

लिविंगस्टोन अब लंदन स्पिरिट की कप्तानी करते दिखेंगे

लंदन । इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन अब द हंड्रेड क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 में लंदन स्पिरिट की कप्तानी करते दिखेंगे। आईपीएल 2025 की विजेता टीम के सदस्य रहे लिविंगस्टोन का लक्ष्य ऐसे में लॉर्ड्स में अपनी टीम को जीत दिलाना रहेगा। लिविंगस्टोन अभी अच्छे फॉर्म में हैं और इसी कारण से उन्हें टीम की कमान सौंपी गयी है। इसकी घोषणा लंदन स्पिरिट ने एक विशेष वीडियो के जरिये की है। लिविंगस्टोन ने कहा, मैं इस गर्मी में लंदन स्पिरिट की कप्तानी करने को लेकर बेहद से उत्साहित हूं। लॉर्ड्स सिर्फ एक मैदान नहीं, बल्कि क्रिकेट का एक पवित्र स्थल है जहां यहां आने वाले दर्शक हर मैच को यादगार बना देते हैं।

स्टोक्स को दूसरे टेस्ट के लिए कप्तानी के साथ ही टीम से बाहर करने पर भड़के वॉन

लंदन। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने नाइटक्लब विवाद को लेकर बेन स्टोक्स को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कप्तानी से हटाने के साथ ही टीम से बाहर करने पर नाराजगी जतायी है। इंग्लैंड और मेहमान टीम न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट केनिंग्टन ओवल, लंदन में 17 जून से खेला जाएगा पर इस मैच से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने स्टोक और गस एटकिंसन को टीम से बाहर कर दिया है। ईसीबी ने जो रूट को दूसरे टेस्ट के लिए कप्तान बनाया है। इस फैसले पर भड़े वॉन का मानना है कि स्टोक्स ने जरूर गलती की है, मगर उन्हें कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए थे। बता दें, बेन स्टोक्स की अगुवाई में ही इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में हुए पहले टेस्ट में जीत दर्ज कर तीन मैच की इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी। वॉन ने कहा कि स्टोक्स ने नीयम तोड़कर गलती की थी पर उन्होंने सवाल किया कि क्या यह गलती इतनी गंभीर थी कि उन्हें कप्तानी के पद से हटाया जाए।

वॉन ने लिखा, स्टोक्स ने नियम तोड़ा। हां, उन्होंने गलती की। लेकिन क्या यह इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान के तौर पर हटाने लायक गलती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। वॉन ने कहा कि ईसीसी को कार्रवाई का पूरा अधिकार है पर वह स्टोक्स को लीडरशिप रोल से हटाने के किसी भी कदम से सहमत नहीं हैं। उन्होंने लिखा, ईसीब को इतना साहसी और मजबूत होना होगा कि वह वही करे जो उसे सही लगता है। अगर इसका मतलब उसे निकालना है तो ठीक है, लेकिन मैं इस मुद्दे पर उस फैसले से सहमत नहीं हूं।

वॉन ने स्टोक्स का बचाव ऐसे समय में किया है जब टीम प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद इंग्लैंड के कप्तान का भविष्य चर्चा का विषय बन गया है। यह मानते हुए कि वॉन ने तर्क दिया कि सजा गलती के हिसाब से होनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की हाल की सफलता में स्टोक्स की भूमिका को देखते हुए पूर्व कप्तान ने कहा कि फैसले में गलती होने पर कप्तानी अपने आप नहीं चली जानी चाहिए। वॉन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सिर्फ पेनल्टी ही खिलाड़ियों को गलतियां दोहराने से रोकने के लिए काफी है।

टी20 विश्वकप से 60 गुना अधिक है फीफा विश्वकप की इनामी राशि

सेन डियागो। अमेरिकि, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रुप से हो रहे टी20 विश्कवकप में पिछले बार से भी अधिक इनामी राशि मिलेगी। वहीं अगर टी20 क्रिकेट विश्वकप से तुलना की जाये तो फीफा विश्व की इनामी राशि 60 गुना अधिक है। इस प्रकार देखा जाये तो क्रिकेट और फुटबॉल जैसे दो सबसे लोकप्रिय खेलों के विश्वक कप की इनामी राशि में भारी अंतर हैं। जिससे सभी हैरान हैं। फीफा विश्व कप 2026 में इस बार कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट से पहले ही फीफा ने इस साल की इनामी राशि घोषित कर दी है। जिसमें पिछली बार के मुकाबले लगभग 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़त हुई है। पिछली बार 2022 में फीफा वर्ल्ड प अर्जेंटीना ने खिताब जीता था, और उस समय कुल इनामी राशि 440 मिलियन डॉलर थी। वहीं साल 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 655 मिलियन डॉलर (लगभग 6241 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया है।

अब अगर इस विशाल राशि की तुलना हाल ही में संपन्न हुए टी20 विश्व कप 2026 से करें, तो यह अंतर और भी हैरान करने वाला हो जाता है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने भारत में आयोजित टी20 विश्व कप 2026 जीतकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता था। ऐसे में उसे कुल प्राइज मनी 11.25 मिलियन डॉलर में से विजेता के तौर पर 2.63 मिलियन डॉलर (लगभग 24.28 करोड़ रुपये) मिले थे। वहीं फीफा विश्व कप 2026 की कुल प्राइज मनी टी20 वर्ल्ड कप की तुलना में 60 गुना अधिक है। इतना ही नहीं, फीफा विश्व कप में 33वें से 48वें स्थान पर रहने वाली टीमों को

भी 9-9 मिलियन डॉलर (लगभग 86 करोड़ रुपये) का इनाम मिलेगा, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 विजेता टीम इंडिया को मिली राशि से तीन गुना से भी ज्यादा है। और अगर हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के चैंपियन की इनामी राशि देखें, तो विजेता टीम को 50 मिलियन डॉलर (लगभग 476 करोड़ रुपये) मिलेंगे। ये टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम की राशि से 19 गुना अधिक है। उप-विजेता टीम को भी 33 मिलियन डॉलर यानी 314 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। वहीं तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 29 मिलियन डॉलर (लगभग 276 करोड़ रुपये) मिलेंगे। चौथे स्थान पर 27 मिलियन डॉलर (लगभग 257 करोड़ रुपये) जबकि 5वें से 8वें स्थान तक- 19 मिलियन डॉलर (लगभग 181 करोड़ रुपये)। 9वें से 16वें स्थान तक- 15 मिलियन डॉलर (लगभग 143 करोड़ रुपये)। 17वें से 32वें स्थान तक- 11 मिलियन डॉलर (लगभग 105 करोड़ रुपये) और 33वें से 48वें स्थान तक- 9 मिलियन डॉलर (लगभग 86 करोड़ रुपये) दिये जाएंगे।

रोहित और विराट 2027 एकदिवसीय विश्वकप में खेलें - अश्विन

चेन्नई। दिग्गज स्पिनर आर अश्विन का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को साल 2027 में होने वाले एकदिवसीय विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलना चाहिये। विश्वकप अगले साल अक्टूबर-नवंबर में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। उस समय तक रोहित जहां 40 साल। वहीं विराट 39 साल के हो जाएंगे। इसी को लेकर इन दोनो की फिटनेस को लेकर सवाल उठे हैं। वहीं दूसरी ओर अश्विन का कहना है कि इन दोनों ही स्टार खिलाड़ियों को साल 2027 के विश्व कप में जरुर खेलना चाहिए।

ए शो में अश्विन ने कहा, मेरे अनुसार ऐसी चीजें बहुत सीधी होती हैं। अगर प्रबंधन चाहता है कि रोहित और विराट दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप में खेलें तो देखे की उनकी फिटनेस कैसी है ओर अगर ये ठीक है तो इन्हें शामिल किया जाना चाहिये। अगर उनके पास पर्याप्त ऊर्जा है, तो उन्हें मैदान पर रखना और उनके अनुभव का इस्तेमाल करना पूरी तरह से संभव है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं और यह बात पूरे अधिकार से नहीं कह सकता पर अगर खिलाड़ियों के लिए एक सही रिहैब प्रोग्राम बनाया जाए और उन्हें प्रबंधन से सकारात्मक संकेत मिलें, तो वे इसे जरूर कर दिखाएंगे। वहीं अश्विन ने आगाह किया कि अगर खिलाड़ियों पर किसी भी तरह का संदेह थोपा जाता है, तो उनके लिए यह असंभव होगा। उन्होंने उम्र के साथ आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा, इस उम्र में चोटें लगना आम बात है। शरीर 35 साल और उससे कम उम्र जैसा नहीं रहता; 32 के बाद भी बदलाव आते हैं। इसलिए हर चरण पर आपको बदलाव के अनुसार ढ़लना होगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि 2027 के विश्व कप तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ से सकारात्मक ऊर्जा बेहद महत्वपूर्ण है। अश्विन ने स्पष्ट किया, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि इन दोनो अनुभवी खिलाड़ियों को वहां क्यों नहीं होना चाहिए। वे अपनी मौजूदगी और अपने अनुभव से टीम को निश्चित रूप से मजबूत बनाते हैं।

वहीं रोहित को लेकर अश्विन ने कहा, उसके किटबैग में अभी 50 ओवर का विश्व कप नहीं है। मुझे लगता है कि वह 2027 विश्व कप में जाकर अपना प्रभाव दिखाकर अपने और देश के लिए एक और ट्रॉफी जीतना चाहता है। अश्विन का मानना है कि रोहित ने अपनी जगह बनाने के लिए अब तक काफी कुछ किया है। उन्होंने साथ ही कहा, जब तक आपकी टीम में विराट और रोहित जैसे अनुभवी क्रिकेटर हैं, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में तो मुझे लगता है कि आपको उनसे जितना हो सके उतना अनुभव लेना चाहिए।

एकदिवसीय सीरीज के लिए पांड्या के विकल्प की घोषणा शीघ्र होगी – सैकिया

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के कारण अफगानिस्तान के साथ 13 जून से शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज से बाहर हो गये है। पांड्या की जगह पर अभी किसी खिलाड़ी को शामिल करने की घोष्णा नहीं की गयी है। वहीं इसको लेकर अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) सचिव देवजीत सैकिया का बयान आया है। सैकिया ने कहा कि चयन समिति जल्द ही यह फैसला करेगी कि उनके स्थान पर किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाए या वर्तमान 14 खिलाड़ियों के साथ ही सीरीज खेली जाए। सैकिया ने कहा, हार्दिक पांड्या चोट के कारण एकदिवसीय सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके विकल्प को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा।

पांड्या इसी महीने बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) पहुंचे थे। आईपीएल में खेलते हुए उनकी पीठ में एंठन आ गयी थी। रिहैब के दौरान उन्हें खेलने की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन बाद में जांघ की मांसपेशी में खिंचाव को देखते हुए उन्हें कुछ सप्ताह के लिए आराम की सलाह दी गई। उम्मीद है कि वह अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज तक फिट हो जाएंगे।

हार्दिक की गैरमौजूदगी में नितीश कुमार रेड्डी को उनकी जगह अंतिम ग्यारह में मौका मिल सकता है। आईपीएल 2026 में अपनी तेज गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी से नितीश ने प्रभावित किया था। नितीश ने 14 मैचों में 8 विकेट हासिल किए थे और कई अवसरों पर जबरदस्त बल्लेबाजी भी की हैं। उनके अलावा शिवदुबे और अर्शद खान भी दावेदार हो सकते हैं। शिवम दुबे फिलहाल टी20 मुंबई लीग में खेल रहे हैं, जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शद खान भारत-ए की ओर से श्रीलंका-ए और अफगानिस्तान-ए के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं।

ओलंपिक में विराट और वैभव को पारी की शुरुआत के लिए शामिल करे बीसीसीआई -श्रीसंत

मुम्बई । पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस. श्रीसंत भी उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से बेहद प्रभावित हैं। इसी को देखते हुए श्रीसंत ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से कहा है कि साल 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम की पारी की शुरुआत के लिए अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी को रखे। गौरतलब है कि साल 2028 में लॉस एंजिल्स में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों से क्रिकेट की वापसी हो रही है। जिससे लेकर क्रिकेट जगत में बेहद उत्साह है। इसमें टी20 प्रारुप में मुकाबले रखे गये हैं। इसमें भारत सहित कुल छह शीर्ष टीमों को भाग लेने का अवसर मिलेगा। श्रीसंत के अनुसार ओलंपिक खेलों के लिए विराट जैसे अनुभवी खिलाड़ी को टीम में रखा जाना चाहिए, और उनके साथ ही 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी मौका मिलना चाहिए। श्रीसंत के इस सुझाव के पीछे एक अनुभवी और एक युवा बल्लेबाज के मिश्रण से शीर्ष क्रम को मजबूती देने का विचार है। हालांकि, यह अनुरोध पूरा करना बीसीसीआई के लिए संभव नजर नहीं आता क्योंकि विराट ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया हैं, और वैभव को भी अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करना है। श्रीसंत ने एक वीडियो में कहा, विराट ने जो काम किया है, वह अविश्वसनीय है। यदि हम ओलंपिक स्वर्ण की बात कर रहे हैं, तो मैं अनुरोध करता हूं कि विराट टीम में खेलें। यह सीनियर और जूनियर का एक बेहतरीन मिश्रण होगा। विराट के साथ सूर्यवंशी का उतरना अद्भुत होगा। उन्होंने कहा, चयनकर्ताओं को विराट को टी20 में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उनकी फिटनेस अभी शीर्ष स्तर की है।

लिस्ट ए में शीर्ष पर पहुंचने ऋतुराज को करना होगा लंबा इंतजार

नई दिल्ली। इंडिया ए टीम में शामिल युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को लिस्ट ए में शीर्ष पर पहुंचने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा और करीब 30 शतक लगाने होंगे । ऋतुराज के नाम अभी लिस्ट ए में 21 शतक हैं। इससे वह अभी लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे

अधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से छठे स्थान पर हैं। अभी वह पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ की बराबरी की है, जिन्होंने अपने करियर में 21-21 लिस्ट ए शतक लगाये हैं। गौरतलब है कि लिस्ट एक में सभी वनडे इंटरनेशनल मैच के साथ-साथ देश में आयोजित होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट के मैच भी शामिल होते हैं। गायकवाड़ ने अपने एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक केवल एक शतक लगाया है। इस सूची में टॉप-5 में जगह बनाने के लिए गायकवाड़ को अभी काफी शतक और लगाने हैं। पांचवें नंबर पर कायम पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन उनसे काफी आगे हैं, जिन्होंने लिस्ट ए में कुल 30 शतक लगाये हैं। गायकवाड़ और धवन के बीच 9 शतकों का बड़ा अंतर है। भारतीय क्रिकेट और ओवरऑल लिस्ट ए में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है, जिन्होंने अपने करियर में कुल 60 लिस्ट ए शतक लगाए हैं। उनके बाद विराट कोहली के नाम 59 शतक हैं। वहीं तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं, जिनके नाम 37 शतक हैं, जबकि सौरव गांगुली 31 शतकों के साथ चौथे पायदान पर मौजूद हैं।

मानव सुथार अब वारविकशर की ओर से काउंटी चैंपियनशिप में खेलेंगे

नई दिल्ली । युवा लेग स्पिनर मानव सुथार अब इंग्लैंड की काउंटी चैम्पियनशिप में वारविकशर टीम की ओर से खेलते दिखेंगे। वारविकशर क्लब ने सुथार को अगले दो काउंटी चैम्पियनशिप मैचों के लिए शामिल किया है। 23 साल के सुधार अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद सभी की नजरों में आये हैं। उन्होंने पहली पारी में सिर्फ 33 रन देकर छह विकेट जबकि दूसरी पारी में भी 29 रन देकर एक विकेट हासिल किया था। इस प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण ही अब उन्हें काउंटी क्रिकेट में अवसर मिला है। सुथार ने इससे पहले घरेलू क्रिकेट में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। उनके नाम 29 प्रथम श्रेणी मैचों में 129 विकेट दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और कौशल का प्रमाण है। यह अनुभव उन्हें काउंटी क्रिकेट के चुनौतीपूर्ण हालातों और अनुभवी बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करने में निश्चित रूप से मदद करेगा। वारविकशर के साथ उनका यह अल्पकालिक अनुबंध उन्हें काउंटी चैम्पियनशिप के अगले दो मैचों के लिए चयन के लिए उपलब्ध कराएगा। उनका पहला मैच 12 से 15 जून तक यॉर्कशर के खिलाफ स्कारबोरो में खेला जाएगा। वहीं इसके बाद वह अगले सप्ताह टॉनटन में समरसेट के खिलाफ भी खेलते दिखेंगे। यह भारतीय स्पिनर के लिए इंग्लैंड के माहौल में ढलने और अपनी स्किल्स को परखने का एक शानदार अवसर होगा।वारविकशर के प्रदर्शन निदेशक जेम्स थॉमस ने सुथार को शामिल करने पर खुशी जताते हुए कहा, हमें मानव का में स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। यह टीम के लिए वास्तव में रोमांचक समय है। हमने इस सत्र में अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है और हमें विश्वास है कि मानव अपनी विविधतापूर्ण गेंदबाजी से हमारे आक्रमण में एक नया आयाम लाएंगे, जो हमें आगामी मैचों में बढ़त दिला सकता है।वहीं इस नए अवसर से सुथार भी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, मैं काउंटी चैम्पियनशिप के अगले दो मैचों के लिए वारविकशर में शामिल होकर बेहद उत्साहित हूं। टीम ने इस सत्र की शानदार शुरुआत की है और ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके टीम को खिताब की ओर बढ़ने में अहम योगदान दे पाऊंगा। यह मेरे लिए एक बेहतरीन अनुभव होगा और मैं इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हूं।

स्टोक्स के बचाव में उतरे न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मार्क रिचर्डसन

ऑकलैंड। नाइटक्लब कांड के बाद विवादों में फंसे इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स के बचाव में न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट ओपनर मार्क रिचर्डसन उतरे हैं। एक ओर जहां इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) नाइटक्लब कांड की जांच कर रहा है और ये भी कहा जा रहा कि इस मामले में उनकी कप्तानी तक जा सकती हैं। यहां कि उन्हें टीम से भी बाहर किया जा सकता है। वहीं ऐसी भी बातें कहीं जा रही हैं कि स्टोक्स इस मामले में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास भी ले सकते है। इसी को लेकर रिचर्डसन नाराज है उनका कहना है कि मैदान के बाहर की गतिविधियों के लिए स्टोक्स को समय से पहले संन्यास लेने पर मजबूर नहीं किय जाना चाहिये। साथ ही कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये खेल के लिए नुकसानदेह होगा। रिचर्डसन की ये टिप्पणी स्टोक्स की शारीरिक सेहत, टेस्ट कप्तान के रूप में उनके अत्यधिक कार्यभार और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके प्रभाव को दिखाती है। रिचर्डसन ने कहा कि स्टोक्स का जाना निराशाजनक होगा क्योंकि कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ है। साथ ही कहा कि कि जब आप इंग्लैंड के कप्तान होते हैं, जब आप पिछले 12 महीनों में उस टीम के साथ जो हुआ है, उसके बाद तनाव में होते हैं, तो एक जीत के बाद वह तरोताता होने नाइट क्लब गये थे हालांकि उन्हें बाहर शराब नहीं पीनी चाहिये थी। या इसे अकेले में पीते।रिचर्डसन ने स्टोक्स के व्यक्तित्व पर भी टिप्पणी की और कहा, मैं उसे जानता हूं। अगर ईसीबी कहे कि हम तुम्हें बैठाने वाले हैं, तो वो ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा, 'अरे, मैं तब रिटायर हो जाऊंगा'। बेन स्टोक्स का क्रिकेट करियर इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां उनके भविष्य का फैसला नाइटक्लब घटना और उसके बाद होने वाली जांच पर निर्भर करेगा पर उनके जैसे मैच विजेता खिलाड़ी का मैदान से दूर होना खेल और प्रशंसकों के लिए नुकसानदेह होगा।

महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के अध्यक्षों के साथ बैठक में बनी रणनीति

केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस नेतृत्व ने गुरुवार को अपने महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें संगठन से जुड़े मुद्दों, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम और वर्तमान सियासी घटनाक्रमों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग के बाद केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि हमारी बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात, खासकर आर्थिक संकट पर चर्चा हुई। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं। लोग भारी परेशानी में हैं, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी पूरे भारत में एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर भी चलाया जाएगा। जहां भी लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वहां जाएगी, उनकी भावनाओं को समझेगी और उनके लिए संघर्ष करेगी। केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा कि हम केवल आंदोलन के पारंपरिक तरीकों से ही नहीं, बल्कि उन लोगों तक पहुंचेंगे जो पीड़ित हैं, जो पीड़ा में हैं। हम उनके दर्द को समझने और अधिकतम आंदोलन के माध्यम से उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता को सडकों पर उतरना चाहिए। हम अगले दो से पांच दिनों में कार्यक्रम का विस्तृत विवरण तैयार करेंगे।

वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी का खेल

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह बताया गया कि उन्होंने अदालत द्वारा भेजे गए नोटिस का खुलासा नहीं किया। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला, कोई एफआईआर या कोई आरोपपत्र दर्ज नहीं था, फिर भी उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। दूसरी ओर, झारखंड में भाजपा समर्थित कॉरपोरेट उम्मीदवार ने संबंधित कॉलम में अपना नाम ठीक से नहीं लिखा, फिर भी रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन स्वीकार कर लिया। एक तरफ आपने मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया और दूसरी तरफ नामांकन पत्र में इतनी सारी खामियों के बावजूद नामांकन स्वीकार कर लिया। यह भारतीय लोकतंत्र की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी का खेल चल रहा है।

कांग्रेस में टीएमसी के विलय की खबरें निराधार

केसी वेणुगोपाल ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी में विलय की खबरों को पूरी तरह निराधार बताते हुए तृणमूल से बड़े पैमाने पर हो रहे विधायकों के पलायन के बीच चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया। वेणुगोपाल ने कहा कि अन्य पार्टियों के सांसदों को इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करना सीट-चोरी के समान है। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए टीएमसी और कांग्रेस नेतृत्व के बीच बातचीत चल रही है।

इस बैठक में कौन-कौन हुआ शामिल?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और कई अन्य नेता मौजूद थे। हालिया विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस महासचिवों एवं प्रभारियों की संयुक्त रूप से यह बैठक पहली बार हुई है। खडगे ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले और सामाजिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। नीट, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों ने करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों का विश्वास हिलाया है। राहुल गांधी खुद प्रभावित छात्रों और युवाओं से मिले हैं तथा उनकी आवाज को देश के सामने मजबूती से रखा है।

भारत में प्लास्टिक नोटों की चर्चा- दुनिया का अनुभव और आरबीआई का आकलन

मुंबई। भारत में प्लास्टिक के नोटों को लेकर चर्चा इन दिनों जोरों पर है, हालांकि तकनीक वैश्विक स्तर पर करीब चार दशकों से चलन में है। आज दुनिया के 60 से अधिक देशों में प्लास्टिक यानी पॉलिमर करेंसी का सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में इन नोटों को जारी कर एक नई शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य इन्हें अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाना था। बाद में कनाडा, ब्रिटेन और कई अन्य देशों ने भी इसी मॉडल को अपनाया। इन देशों में प्लास्टिक नोटों को लंबी उम्र और बेहतर सुरक्षा के लिए सराहा जाता है।

अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भी विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि केंद्रीय बैंक प्लास्टिक नोटों की संभावनाओं को खंगाल रहा है, हालांकि फिलहाल इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यह योजना अभी शुरुआती चरण में है और विशेषज्ञ इसकी उपयोगिता, उत्पादन लागत और व्यवहार्यता सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का गहन अध्ययन कर रहे हैं।

पॉलिमर नोटों की लोकप्रियता के कई कारण हैं। सामान्य कागजी नोटों की तुलना में ये कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ये आसानी से फटते नहीं, पानी से खराब नहीं होते और इनका जीवनकाल भी लंबा होता है। साथ ही, इसमें बेहतर सुरक्षा फीचर्स होने के कारण नकली नोटों की पहचान करना या उनका निर्माण करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि, हर तकनीक की तरह इसके भी कुछ नुकसान हैं। प्लास्टिक नोटों की छपाई कागज़ी नोटों के मुकाबले अधिक महंगी होती है। इसके अलावा, इन्हें रीसायकल करना भी जटिल प्रक्रिया है। इन्हीं सब कारणों से आरबीआई किसी भी बड़े निर्णय से पहले सभी आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं का बारीकी से मूल्यांकन कर रहा है। गवर्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में नकदी की कोई कमी नहीं है और बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त करेंसी उपलब्ध है। दुनिया के कई देशों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो रहे प्लास्टिक नोट भारत में कब और कैसे आएंगे, यह फैसला अभी बाकी है। आरबीआई का कहना है कि सभी जांच-पड़ताल के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा, इसके बाद में लोगों को आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार करना होगा।

तमिलनाडु में बिजली संकट गहराया, अघोषित कटौती से जनता परेशान

-विजय सरकार ने विशेष निगरानी और मरम्मत टीमें तैनात कीं

चेन्नई,। तमिलनाडु में मानसून की शुरुआत के साथ ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था गंभीर दबाव में दिखाई दे रही है। राज्य के कई हिस्सों में अघोषित बिजली कटौती की शिकायतों के बीच आम जनता में नाराजगी बढ़ गई है और विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। बढ़ती बिजली मांग और बार-बार आ रहे तकनीकी फॉल्ट राज्य की विजय सरकार के लिए बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन गए हैं।

राजधानी चेन्नई में स्थिति सबसे अधिक प्रभावित बताई जा रही है। शहर और उपनगरीय क्षेत्रों के कई इलाकों में बिना पूर्व सूचना बिजली कटौती की शिकायतें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विशेष रूप से रात के समय बिजली बाधित होने से घरेलू जीवन, व्यापारिक गतिविधियों और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तमिलनाडु बिजली विभाग के अनुसार 10 जून को चेन्नई में 5,008 मेगावाट की रिकॉर्ड बिजली मांग दर्ज की गई, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है। बढ़ी हुई मांग और वितरण नेटवर्क पर बढ़ते दबाव के कारण कई क्षेत्रों में आपूर्ति प्रभावित हुई है।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। बिजली मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने 125 पेट्रोलिंग वाहनों और 125 विशेष मरम्मत दलों को रवाना किया है। इसके साथ ही पूरे अभियान की निगरानी के लिए 10 उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग टीमों का गठन किया गया है, जिनका नेतृत्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी क्षेत्र से बिजली फॉल्ट की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए टीमों को आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिजली आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है।

बिजली संकट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि बढ़ती मांग और मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं तथा उन्हें दूर करने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है।

आज यहां रहेगी बिजली आपूर्ति बाधित

इसी बीच बिजली बोर्ड ने 12 जून को निर्धारित रखरखाव कार्यों के चलते चेन्नई के पल्लावरम, मिनजूर और मंबलम सहित कई क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की पूर्व सूचना जारी की है। अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

यूएई में छात्रों को मिलेगी राहत, विशेष परिस्थितियों में घर बैठे दोबारा परीक्षा देने की अनुमति

नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों और अभिभावकों के बीच चल रही भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में छात्रों को परीक्षा दोबारा देने की अनुमति ऑनलाइन या रिमोट माध्यम से दी जा सकती है। हालांकि मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि सामान्य परिस्थितियों में सभी अंतिम और केंद्रीय परीक्षाएं स्कूलों में उपस्थित होकर ही देनी होंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, दिव्यांग छात्र, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे छात्र, उपचार के लिए देश या विदेश में मौजूद विद्यार्थी तथा वैध कारणों से संयुक्त अरब अमीरात से बाहर रहने वाले छात्र रिमोट परीक्षा की सुविधा के पात्र हो सकते हैं। इसके अलावा किशोर सुधार गृहों में रह रहे नाबालिग छात्रों को भी यह सुविधा दी जा सकती है। ऐसी अनुमति स्कूल प्रशासन और संबंधित परीक्षा प्राधिकरण की मंजूरी के बाद ही मिलेगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी छात्र को केंद्रीय ऑनलाइन परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि वह तत्काल समस्या का समाधान करे। यदि समस्या समय रहते दूर नहीं हो पाती है, तो संबंधित छात्र को पुनर्परीक्षा या क्षतिपूर्ति परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि जिन छात्रों के पास परीक्षा देने के लिए उपयुक्त कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें स्कूलों की कंप्यूटर लैब या उपलब्ध उपकरणों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र की परीक्षा केवल तकनीकी कारणों से प्रभावित न हो। मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण को छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, लचीलापन और समान अवसर सुनिश्चित होंगे, जबकि शैक्षणिक मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

विधानसभा चुनावों और टीएमसी में चल रही फूट को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में गुरुवार को एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी के महासचिवों, प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्षों की अहम बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और कई अन्य नेता मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं की यह अहम बैठक हालिया विधानसभा चुनावों और टीएमसी में चल रही फूट के बीच हुई। इस बैठक से एक दिन पहले वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा के लिए यह आपात बैठक बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को हुई बैठक में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों के अलावा बीजेपी द्वारा केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के प्रचार अभियान और पीएम नरेंद्र मोदी के जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ने से जुड़े राजनीतिक विमर्श का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा की।

लोकपथ ऐप से सड़क संबंधी शिकायतें दर्ज करना हुआ आसान, नागरिकों से सहभागिता की अपील

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। सड़क अधोसंरचना को बेहतर बनाने तथा नागरिकों की सहभागिता से सड़क संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकपथ (श्वद्य ड्डह्लद्ध) मोबाइल ऐप संचालित किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक सड़क पर गड्ढों, क्षतिग्रस्त मार्गों एवं सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं की शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचा सकते हैं।

बालाघाट जिले के नागरिकों से लोकपथ ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की गई है। ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करना बेहद सरल है। नागरिक सड़क की समस्या का फोटो अपलोड कर सकते हैं, जबकि शिकायत की लोकेशन स्वत: दर्ज हो जाती है। इससे संबंधित विभाग को समस्या के सटीक स्थान की जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती है और निराकरण की प्रक्रिया में तेजी आती है।

लोकपथ ऐप की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा ऐप में सड़क सुरक्षा से जुड़ी उपयोगी जानकारियां उपलब्ध हैं तथा आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए एसओएस (स्ब्स्) सुविधा भी प्रदान की गई है। सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने में आम नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी सड़क पर गड्ढे, क्षति या अन्य सुरक्षा संबंधी समस्या दिखाई देती है तो नागरिक तत्काल लोकपथ ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे समस्याओं के शीघ्र समाधान में मदद मिलेगी और सड़क उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

जिलेवासियों से अपील की गई है कि वे अपने मोबाइल फोन में लोकपथ ऐप डाउनलोड कर सड़क सुधार अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। नागरिकों की जागरूकता एवं सहयोग से ही सड़कों को अधिक सुरक्षित, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। सड़क समस्या दिखे, लोकपथ ऐप पर शिकायत लिखें के संदेश के साथ सभी नागरिकों से इस डिजिटल पहल का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है।

मैं सच बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगा क्योंकि वे बहुत बड़े लोग हैं

-राम मंदिर दान में गड़बड़ी पर बृजभूषण शरण सिंह ने दिया चौंकाने वाला बयान

अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर में चढ़ावे के दुरुपयोग और चोरी के आरोपों पर एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। जिले के विश्नोहरपुर स्थित अपने पैतृक आवास पर बुधवार को पत्रकारों से कहा कि वह इस पूरे विषय पर बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिलहाल सच बोलने की स्थिति में नहीं हैं। अयोध्या में राम मंदिर के दान में गड़बड़ी को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी विवाद के बीच बृजभूषण की यह टिप्पणी राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे रही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बृजभूषण सिंह ने कहा कि मैं बहुत कमजोर आदमी हूं। अगर मैं सच बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगा क्योंकि वे बहुत बड़े लोग हैं। सच बोलने की हिम्मत अभी मेरे अंदर नहीं है। कभी समय आएगा तो बोलूंगा। उन्होंने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि वे से उनका तात्पर्य किससे है। सिंह की टिप्पणी अयोध्या में राम मंदिर के दान में गड़बड़ी को लेकर बढ़ते विवाद के बीच आई है। दिल्ली में करीब 10 दिन के प्रवास के बाद गांव लौटे बृजभूषण सिंह ने अपने हालिया राजनीतिक और सामाजिक अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से वह कई जटिल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। 2023 में कुछ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े विवाद का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से उस प्रकरण से उपजी परिस्थितियों को संभालने में लगे हुए हैं।

नीट में अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे पर बृजभूषण ने कहा कि किसी मंत्री के इस्तीफा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के पीछे एक संगठित तंत्र है जिसमें विभिन्न स्तरों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी मंत्री के इस्तीफा देने से भविष्य में पेपर लीक रुकने की गारंटी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मंत्री प्रत्येक परीक्षा केंद्र या व्यवस्था की व्यक्तिगत निगरानी नहीं कर सकता। उनके अनुसार जब तक दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि पहली बार बड़े अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती दिखाई दे रही है और उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा सरकार नकल एवं पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क को तोड़ने में सफल होगी।

भारत ने विकास-निर्यात के अवसर पैदा करने कई देशों से किए मुक्त व्यापार समझौते

नई दिल्ली। भारत के कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने विकास और निर्यात के नए अवसर पैदा किए हैं। यह समझौते हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए बड़ा मौका हैं। यह बात पीएम मोदी ने गुरुवार को नीति आयोग की बैठक में दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने विकास और निर्यात के नए अवसर पैदा करने के लिए कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करके और अपनी प्रतिस्पर्धा-क्षमता बढ़ाकर वैश्विक बाजारों के लिए तैयार होने में मदद करते हैं। भारत ने बीते एक साल में यूके, यूरोपीय यूनियन, ओमान और न्यूजीलैंड समेत कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। साथ ही अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते लिए बातचीत जारी है।

नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास विकसित भारत के विजन का एक अहम आधार है। खेती और स्टार्टअप से लेकर विज्ञान और इनोवेशन तक, नारी शक्ति हर क्षेत्र में योगदान दे रही है। राज्यों को महिलाओं की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने और भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उनकी शिक्षा, स्किलिंग, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक ऐतिहासिक अवसर है जिसे हम गंवा नहीं सकते। अच्छी शिक्षा, मांग के अनुरूप कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के जरिए अपने युवाओं के लिए सही इकोसिस्टम बनाना हमारी प्राथमिकता हो। सशक्त युवा ही विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा की मुख्य ताकत बनेंगे। नीति आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी के टीम इंडिया के विजन के अनुरूप, विकसित भारत के लिए इस साल की थीम 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। यह थीम उम्र, क्षेत्र, लिंग या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से परे, हर भारतीय की भलाई और विकास पर केंद्रित है।

तेजस एमके1ए के लिए सप्लाई पार्ट्स के 199 टेस्ट रिपोर्ट नकली, कंपनी पर एफआईआर

हैदराबाद। भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम को लेकर एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के एक आंतरिक ऑडिट में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एमके1ए प्रोग्राम के लिए सप्लाई किए जाने वाले पार्ट्स की 199 टेस्ट रिपोर्ट नकली पाई गई हैं। इस धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद एचएएल ने हैदराबाद की एक वेंडर कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला सीधे तौर पर देश के सबसे अहम फाइटर जेट प्रोजेक्ट की सुरक्षा और क्वालिटी से जुड़ा है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एचएएल के एयरक्राफ्ट डिवीजन के डिप्टी जनरल मैनेजर रानू गुप्ता की शिकायत पर 2 जून को बेंगलुरु के एचएएल पुलिस स्टेशन में टीईसी ऐरो डिवाइस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कंपनी के सीईटो एम. शिवराम प्रसाद को आरोपी बनाया गया है और पुलिस ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। शिकायत में में बताया कि एचएएल ने 28 मार्च, 2022 से एलसीए-83 एमके-1ए प्रोजेक्ट से जुड़े पार्ट्स की सप्लाई के लिए 18 खरीद ऑर्डर जारी किए थे। सैंपल, टेस्ट रिपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद, कंपनी को 35 कैटेगरी के पार्ट्स बनाने के लिए अप्रूवल सर्टिफिकेट मिले थे और बल्क सप्लाई के दौरान उन्हें ओरिजिनल टेस्ट रिपोर्ट जमा करनी थी। बाद में एचएएल के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने टेन्साइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ब्रेक लोड, शियर, एनडीटी, माइक्रोस्ट्रक्चर और सॉल्ट स्प्रे टेस्ट से जुड़ी ओरिजिनल रिपोर्ट मांगीं, लेकिन कंपनी पेश नहीं कर पाई। शिकायत के मुताबिक एचएएल को 22 नवंबर, 2023 को टीईसी ऐरो डिवाइस से एक माफीनामा मिला, जिसमें माना गया कि उसने हैदराबाद में दो गलत रिपोर्ट जमा की थीं। इसके बाद, टीईसी ऐरो डिवाइस ने 29 नवंबर, 2023 को एक ऑडिट किया ताकि टीईसी ऐरो डिवाइस द्वारा पहले जमा की गई टेस्ट रिपोर्ट की सच्चाई का पता लगाया जा सके।ऑडिट के दौरान एचएएल ने पाया कि फरवरी और सितंबर 2023 के बीच हैदराबाद की कंपनी द्वारा जमा की गई सभी 199 रिपोर्ट नकली थीं। यह भी पता चला कि रिपोर्ट एक्सिस इंपेक्शन सल्यूशन द्वारा जारी नहीं की गई थीं। एफआईआर में कहा गया है एक्सिस इंपेक्शन सल्यूशन ने एचएएल को बताया कि नकली रिपोर्ट बनाने और जमा करने के लिए उनके नाम और सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद, एचएएल ने टीईसी ऐरो डिवाइस को 10 मार्च 2027 तक, यानी तीन साल के लिए कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। साथ ही, यह भी बताया गया कि उस तारीख तक एयरक्राफ्ट डिवीज़न की ओर से टीईसी ऐरो डिवाइस को कोई पेमेंट नहीं किया गया था।

राज्य में इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं, दोषियों को दी जाएगी सजा

इंफाल। मणिपुर पुलिस ने कांगपोकपी ज़िले में हथियारबंद समूहों द्वारा अगवा किए गए लापता नागा पुरुषों में से छह लोगों के शव बरामद किए। नागा समुदाय के इन छह लोगों को 13 मई को लेइलोन वाइफेई गांव से अगवा किया गया था। एक आधिकारिक बयान में सीएम मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी और कहा कि हत्या के लिए ज़िम्मेदार दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी।

बता दें ये शव उस घटना के एक दिन बाद मिले, जब सेनापति जिले से लगभग एक महीने पहले अगवा किए गए 14 कुकी लोगों को 9 जून को रिहा किया गया। मणिपुर पुलिस ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के करीब 450 जवानों ने स्निफर डॉग्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट टीमों की मदद से करीब 24 घंटे तक लगातार तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद छह लोगों के शव बरामद किए। माना जा रहा है कि ये शव उन लोगों के हैं जिन्हें 13 मई, 2026 को लेइलोन वाइफेई से बंधक बनाया था।

खबरों के मुताबिक 13 मई को कांगपोकपी जिले में चर्च के तीन नेताओं की हत्या के बाद छह नागा और 14 कुकी लोगों का अपहरण कर लिया था। एक्स पर एक अलग पोस्ट में सीएम सिंह ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि कांगपोकपी ज़िले के लेइलोन वाइफेई गांव से अगवा किए गए छह बेगुनाह नागा ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या से मुझे गहरा दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।

सीएम सिंह ने कहा कि मणिपुर सरकार इस घिनौनी हरकत की कड़ी निंदा करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि दोषियों को सज़ा मिले। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। हमारे समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हम मणिपुर में शांति, सुरक्षा और कानून के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं।

पश्चिम बंगाल नीले से हुआ भगवा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकारी भवनों के रंग-रूप में भी बदलाव दिखाई देने लगा है। कोलकाता स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय 'नवान्न' समेत कई सरकारी इमारतों पर पहले मौजूद नीले-सफेद रंग की जगह अब भगवा रंग की पुताई की जा रही है। राज्य सरकार के इस कदम को नई प्रशासनिक पहचान और सौंदर्यीकरण अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से विभिन्न सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों को नए रंग में रंगा जाएगा। इस बदलाव को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है और इसे प्रतीकात्मक परिवर्तन माना जा रहा है।

प्रवेश मलेवार पर स्टाम्प वेंडर संघ ने लगाया अवैध वसूली का आरोप

न्यायालय परिसर के बाहर कार्यरत सेवा प्रदाताओं ने सौपा ज्ञापन लगाई इंसाफ की गुहार, 600 रु प्रति माह मांगे जाने के आरोपों का मलेवार ने किया खंडन, आरोपो को बताया झूठा- बे-बुनियाद

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रवेश मलेवार पर, दस्तावेज लेखन स्टांप वेंडर संघ द्वारा अवैध रूप से रुपयों की वसूली के आरोप लगाए हैं।आरोप है कि अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रवेश मलेवार,द्वारा दस्तावेज लेखन स्टांप वेंडर का काम करने वाले लोगों से अवैध रूप से 600 प्रति माह की मांग की जा रही है, वहीं अपनी इस मांग को लेकर संघ के पदाधिकारियो सदस्यों से अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। जिसकी लिखित शिकायत दस्तावेज लेखन स्टांप वेंडर संघ से जुड़े पदाधिकारियो सदस्यों ने जिला सत्र न्यायाधीश,कलेक्टर, एसपी और कोतवाली थाने में ज्ञापन सौपकर की है। जिसमें संघ द्वारा जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रवेश मलेवार पर वैधानिक कार्यवाही कर उन्हें इंसाफ दिलाए जाने की गुहार लगाई गई है। उधर इस पूरे मामले पर जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रवेश मलेवार ने, स्टाम्प वेंडर संघ द्वारा लगाए गए सभी आरोपो को झूठा व बे-बुनियाद बताते हुए, इस मामले में अधिवक्ताओं द्वारा भी वैधानिक कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है।

लाइसेंस चेक कर, परिसर में बैठने से किया मना, मांग रहे 600 रु प्रतिमाह

जिला न्यायालय परिसर के बाहर वर्षों से कार्य कर रहे स्टाम्प विक्रेताओं, कंप्यूटर टाइपिस्टों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं ने ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। आवेदन में बताया गया है कि वे पिछले 25 से 40 वर्षों से न्यायालय परिसर के बाहर वैध रूप से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे किसी भी प्रकार का न्यायालयीन कार्य नहीं करते, बल्कि भूमि पंजीयन से संबंधित दस्तावेज तैयार करने, स्टाम्प विक्रय तथा टाइपिंग का कार्य कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं।आवेदनकर्ताओं के अनुसार कुछ दिन पूर्व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मलेवार अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और उनका लाइसेंस जांचने के बाद उन्हें कार्य करने से मना कर दिया। आरोप है कि अध्यक्ष द्वारा परिसर के बाहर बैठकर कार्य करने के एवज में 600 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह देने की मांग की गई। सेवा प्रदाताओं ने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इतनी राशि देने में सक्षम नहीं हैं।

संघ ने अभद्र व्यवहार का भी लगाया आरोप इंसाफ की करी मांग

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि वे मेहनत-मजदूरी के माध्यम से अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं तथा किसी प्रकार की अवैध गतिविधि में शामिल नहीं हैं। इसलिए उनसे की जा रही धनराशि की मांग उचित नहीं है। सेवा प्रदाताओं ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा उन्हें पूर्व की भांति अपना कार्य करने की अनुमति दिलाने की मांग की है।

मामले में दिया जाए इंसाफ- दिनेश बोदरे

ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के दौरान दस्तावेज लेखन स्टांप वेंडर संघ कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार बोदरे ने बताया कि वह न्यायालय के बाहर झोपड़ी बनाकर दस्तावेज लेखन और स्टांप वेंडर का काम करते हैं लेकिन जिला अधिवक्ता संघ द्वारा हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर अवैध रूप से रूपयो की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष मालेवार आए थे,लाइसेंस पूछा, बोले लाइसेंस बाहर का है यहां नहीं चलेगा। हमारे साथी के पास गांव का लाइसेंस था उसे भी मानने से इनकार कर दिया ।बोले यहां पर बैठकर यह कार्य मत करो और यदि करना है तो प्रत्येक को 600रु प्रति माह देना होंगा। हमारे कुछ साथियों ने डर के मारे उन्हें पैसे भी दे दिए हैं। हमारी दुकानों में लगे विद्युत मीटर को भी हटा रहे हैं।हमारी मांग है कि इस मामले की उचित जांच कर हमें न्याय दिलाया जाए। उन्होंने बताया कि यहां कोई पहला मामला नहीं है बल्कि इसके पूर्व भी अधिवक्ता संघ अध्यक्ष द्वारा ऐसा कृत्य किया जा चुका है।

सभी आरोप झूठे व बे बुनियाद है- मलेवार

इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रवेश मलेवार ने बताया कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बे-बुनियाद है इसके पहले भी इन लोगों को हिदायत दी गई थी कि वह दस्तावेज और लाइसेंस साथ में रखें, यह लोग राजस्व प्रकरण बनाकर स्वयं पेश कर देते हैं, नामांतरण की कार्यवाही अधिवक्ता के माध्यम से होनी चाहिए लेकिन यह स्वयं नामांतरण दस्तावेज बनाकर उसे पेश कर रहे हैं।कुछ लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, कुछ लोगों के पास लाइसेंस है लेकिन वे बाहर के हैं और वे यहां आकर बैठकर न्यायलयीन कार्य कर रहे हैं। हमारी समझाईश के बाद भी नहीं मान रहे हैं। किसी विघुत मीटर में 20- 20 तो किसी मीटर में 15-15 कनेक्शन चल रहे हैं। हमारे द्वारा किसी प्रकार के रुपयों की मांग नहीं की गई है और ना ही किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है।जल्द ही इसकी शिकायत समस्त अधिवक्ताओं द्वारा की जाएगी।

पैसा ठीक होने के बाद देना
शादी से पहले एवं शादी के बाद
उम्र की अधिकता से कमजोर सेक्स, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, लिंग का छोटापन, टेडापन, निःसंतान, शुक्राणुओं की कमी, शुगर से आयी कमजोरी आदि सभी सेक्स समस्याओं का शर्तिया ईलाज किया जाता है।
पता-जगजीवन आयुर्वेदिक दवाखाना
गुरूनानक पेट्रोल पंप के सामने समाजवाड़ी रोड, बालाघाट, मो. 9243880464

पुलिस लाइन चौक के पास सड़क हादसे के बाद विधायक मधु भगत के वाहन चालक से मारपीट

घायल वाहन चालक जिला अस्पताल में भर्ती

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। नगर के वारासिवनी रोड स्थित पुलिस लाइन चौक के पास गुरुवार दोपहर सड़क दुर्घटना के बाद विवाद की घटना सामने आई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार परसवाड़ा विधायक मधु भगत के वाहन चालक घायल हो गए। आरोप है कि दुर्घटना के बाद दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार वन विभाग की वर्दी पहने एक व्यक्ति और उसके साथी ने विधायक भगत के घायल चालक के साथ मारपीट भी की त थ ा उसकी मोटरसाइकिल की चाबी लेकर मौके से फरार हो गए। घायल चालक सोन कादित्य पिता डिलन सोनवर्षा 25 वर्ष को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोन कादित्य ग्राम दमोह थाना बिरसा निवासी है।

जो परसवाड़ा विधायक मधु भगत के यहा वाहन चालक के रूप में कार्य करता है। बताया गया कि 11 जून को दोपहर करीब 2:45 बजे सोन कादित्य मोटरसाइकिल में बालाघाट बस स्टैंड विधायक के बेटे के लिए भोजन लेने आया था। भोजन का पार्सल लेकर वह विधायक कार्यालय लौट रहा था इसी दौरान वारासिवनी रोड स्थित पुलिस लाइन चौक के आगे फॉरेस्ट कॉलोनी मार्ग की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक मोटरसाइकिल, सोन कादित्य की मोटरसाइकिल से टकरा गई। मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से सोन कादित्य मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिर गया। जिससे उसे चोटें आई।बताया जा रहा है कि दूसरी मोटरसाइकिल पर वन विभाग की वर्दी पहने एक व्यक्ति और उसके साथ एक अन्य युवक सवार था। दुर्घटना के बाद दोनों ने घायल सोन कादित्य के साथ गाली-गलौज करते हुए विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि दोनों व्यक्तियों ने सोन कादित्य के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की और बाद में उसकी मोटरसाइकिल की चाबी लेकर मौके से फरार हो गए।घटना के बाद सोन कादित्य ने विधायक मधु भगत के पुत्र सोमिल भगत को फोन कर जानकारी दी। सूचना मिलते ही सोमिल भगत मौके पर पहुंचे और घायल चालक सोन कादित्य को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती कराया।जहां उसका उपचार जारी है।जिला अस्पताल पुलिस चौकी ने घायल सोन कादित्य के बयान दर्ज कर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना भेज दी है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।

आवश्यकता है
फिल्ड कार्य हेतु लड़कों की आवश्यकता है
संपर्क करें-पद्मेश सिटी केबल
काली पुतली चौक, बालाघाट

ग्रेसियस् कॉलेज
2026-27 ADMISSION OPEN
SC ,ST, OBC वर्ग के विद्यार्थियों को म. प्र. शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति
नर्सिंग
बी.एस.सी. नर्सिंग
4 वर्षीय डिग्री
मान्यता : आई.एन. सी. नई दिल्ली, म.प्र. नर्सिंग रजि. काउंसिल भोपाल, राजा शंकरशाह वि. वि. छिंदवाड़ा
फार्मेसी
बी.फार्मा. 4 वर्षीय डिग्री
2 वर्षीय डिप्लोमा डी.फार्मा.
मान्यता : पी.सी.आई. नई दिल्ली, आर.जी.पी.वी. भोपाल, डी.टी.ई. भोपाल
योग्यता : 12 वी उत्तीर्ण (जीव विज्ञान/गणित संकाय)
73820 53000 / 73820 54000
आर.टी.ओ.ऑफिस के पास, वारासिवनी रोड , बरबसपुर - कायदी,बालाघाट म.प्र.

AICTE भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं RGPV & DTE भोपाल से सम्बध्द
सतपुड़ा कॉलेज ऑफ
इंजीनियरिंग एण्ड पॉलिटेक्निक
बी.टेक. पॉलिटेक्निक JOB SAHi
• कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
• माईनिंग इंजीनियरिंग
• सिविल इंजीनियरिंग
• मैकेनिकल इंजीनियरिंग
• इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
ADMISSION OPEN
नई शिक्षा नीति के तहत किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों का Lateral Entry द्वारा बी.टेक. के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश
सतपुड़ा कैम्पस, लालबर्रा रोड, गर्रा-बालाघाट
6262604111, 9425836824 www.satpudaengineeringcollege.com

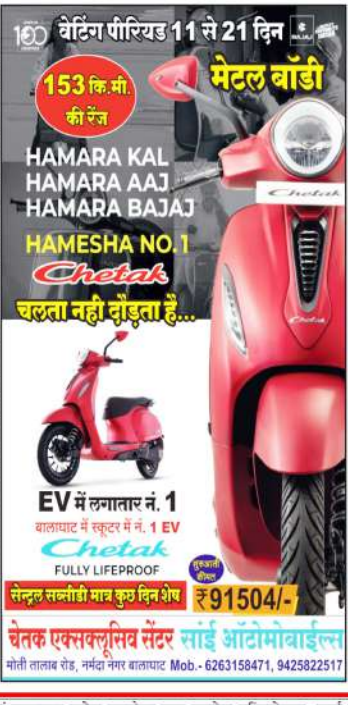

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट(म.प्र.) से प्रकाशित,
प्रधान संपादक : उमेश बागरेचा, मो.नं. :9425138710, , ई-मेल- balaghatexpress@gmail.com पंजीयन क्रं. MPHIN/2009/32311, न्यायालयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट